VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
RN 30 SEP 2016 No 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 766)

Name of Candidate	Shailendra Singh Pudhiya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	30/9/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Legislative Councils in states are expensive and otherwise superfluous legislative appendages. Examine the utility of legislative councils in this context. Also, comment on the procedural aspect of setting up and abolishing them.

राज्य विधान परिषदें महंगी और अनावश्यक विधायी उपांग हैं। इस संदर्भ में विधान परिषदों की उपयोगिता की जांच करें। इसके अतिरिक्त इनके सृजन व उत्सादन के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर टिप्पणी करें।

राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल के एक अंग है। इनके सृजन के संबंध में कई प्रक्रियात्मक पहलू जुड़े हैं। इनके महंगी होने के बावजूद इन्हें एक अनावश्यक उपांग नहीं माना जा सकता है।

विधानपरिषद की उपयोगिता -

- तकनीकी रूप से सशक्त व्यक्तियों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से न जीतने की स्थिति में उन्हें विधानपरिषद में सदस्य बनाया जा सकता है।
- यह विधानसभा द्वारा लिये गये जल्दबाजी के निर्णयों में पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करती है।
- इसके सदस्यों का विविध पृष्ठभूमि से होने के कारण राज्य विधानमंडल का समावेशी चरित्र बरकरार रहता है।

तथापि विधानपरिषद की विधायी शक्तियां सीमित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है। इसके द्वारा किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोका जा सकता है तथा इसके अस्वीकृति की दशा में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है।

सृजन व उत्सादन हेतु प्रक्रिया -

इस हेतु विधानसभा में उपस्थित व मतदान वालों का 2/3 तथा सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक विधायकों द्वारा विधेयक पारित कराना अनिवार्य है।

तथापि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात संसद को ही इस विधेयक पर अनुमति लेनी पड़ती है। संसद द्वारा उपस्थित सांसदों के आधे के अधिक द्वारा अनुमति देने की स्थिति में राज्य विधानपरिषद का सृजन या विघटन किया जा सकता है।

उत्सादन की स्थिति में राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पास कर इसे लागू किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महत्वपूर्ण हैं -

- राज्य विधानमण्डल को राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के समान 'पंचायतों की परिषद' के रूप में बनाने की आवश्यकता है।
- इसके सदस्यों का चुनाव पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. While some argue that Article 3 provides usurping powers to the center at the cost of states, according to others it enables the Parliament to maintain and preserve federalism as enshrined in the constitution. Discuss. Is it time to have a relook at Article 3 in the spirit of co-operative federalism?

जहाँ कुछ लोगों का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों की कीमत पर केंद्र को अनन्य शक्तियां प्रदान करता है, वहीं दूसरों के अनुसार, यह संविधान में निहित संघवाद को बनाए रखने तथा संरक्षित करने के लिए संसद को सक्षम बनाता है। चर्चा कीजिए। क्या सहकारी-संघवाद की भावना के अनुरूप अनुच्छेद 3 पर पुनः विचार करने का समय आ गया है?

अनुच्छेद-3 के अंतर्गत केंद्र को राज्यों की सीमा घटाने, राज्यों का विलय करने, या नए राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करने संबंधी अधिकार हैं क्योंकि भारत को 'विभाज्य राज्यों का अविभाजित संघ' माना गया है।

यद्यपि इस संबंध (3 अनुच्छेद) में केंद्र को अनन्य शक्तियां हैं तथापि स्वतंत्रता के पश्चात देश को सुदृढ़ व अखंड बनाने हेतु ऐसी शक्तियों का केन्द्र में होना अनिवार्य था। राज्यों को ऐसी शक्तियां देने पर विभाजन का संकट पुनः उत्पन्न हो सकता था।

यह अनुच्छेद संघ को संघवाद बनाये रखने हेतु शक्तियां प्रदान करता है क्योंकि राष्ट्रहित के खिलाफ केवल राज्य द्वारा अपनी सीमा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को घटाया नहीं जा सकता है।

सहकारी संघवाद प्रशासनिक निर्णयों, विधायी निर्णयों के संबंध में राज्यों की भूमिका को बढ़ाता है। तथापि अनुच्छेद-3 को सहकारी संघवाद की दिशा में बाधक नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान में भी अलगाववादी ताकतें विद्यमान है। पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैण्ड, मणिपुर में अलगाववादी ताकतों के सक्रिय होने के कारण इस अनुच्छेद में ढील देना राष्ट्रहितों व देश की संप्रभुता व अखंडता के लिए उपयुक्त कदम नहीं होगा।

पूंछी आयोग ने भी इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें की है।

इस प्रकार अनुच्छेद-3 को ढील देने या इसके संबंध में राज्यों को शक्ति देना एक प्रभावी कदम नहीं होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1φ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. While the British Parliament is a sovereign legislature, the Parliaments of India and USA are non-sovereign legislatures. Explain. Also, compare the organisation and powers of the Indian Lok Sabha with the British House of Commons.

जहाँ ब्रिटिश संसद एक संप्रभु विधायिका है, वहीं भारत और अमरीका की संसदें गैर-संप्रभु विधायिकाएं हैं। स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त, हाउस ऑफ कॉमन्स और भारतीय लोक सभा के गठन की प्रक्रिया और शक्तियों की तुलना करें।

ब्रिटिश संसद एक संप्रभु विधायिका है क्योंकि इसके द्वारा लिये गये विधायी कार्यों या शक्तियों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत व अमेरिकी संसदें द्वारा की गई कार्यवाहियों या उनके द्वारा पारित विधेयक न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होते हैं जिन्हें न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निरस्त भी किया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

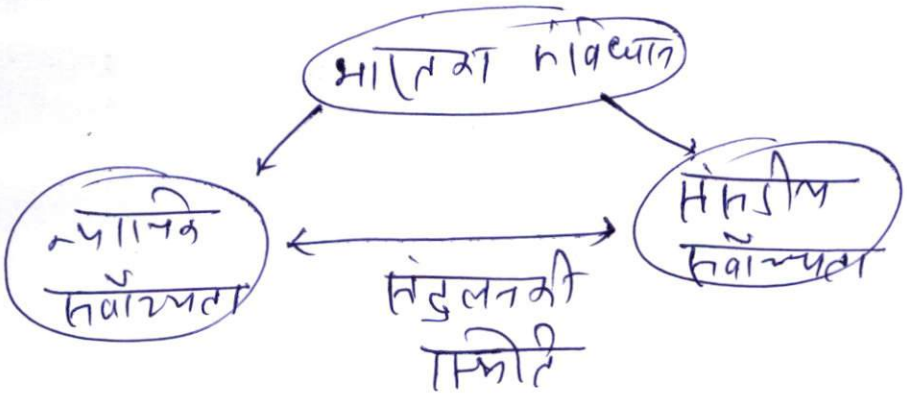

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हाउस ऑफ कामन्स तथा लोकसभा के गठन व शक्तियों में कई अंतर है।

हाउस ऑफ कॉमन्स का गठन निर्वाचन द्वारा व अप्रत्यक्ष रूप से नामांकन द्वारा होता है जबकि लोकसभा में सदस्य मनोनीत करने का उपबंध नहीं है।

लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित विधेयक को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. While Fundamental Rights are crucial to the survival of a vibrant democracy, Fundamental Duties are equally important. While enumerating the Fundamental Duties, discuss the statement.

जहाँ एक जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को चिन्हित करते हुए प्रस्तुत कथन पर चर्चा कीजिए।

जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व हेतु मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दोनों आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार "जब व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों पर बल देने से उनके अधिकार अपने आप सिद्ध हो जायेंगे"

संविधान में मूल कर्तव्य लोकतंत्र हेतु आवश्यक है।

- संविधान द्वारा प्रदत्त मूल आदर्शों का पालन करना। आपसी स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा विकसित मूल्यों को हृदय में सम्मान देना।
- राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना।
- ऐसी परंपराओं का विरोध करें जो महिलाओं के खिलाफ हों। - सामाजिक लोकतंत्र
- आर्थिक लोकतंत्र - सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पर्यावरणीय लोकतंत्र - सभी व-पशुओं, झीलों का संरक्षण करें।
- सामाजिक संस्कृति विकसित करें।

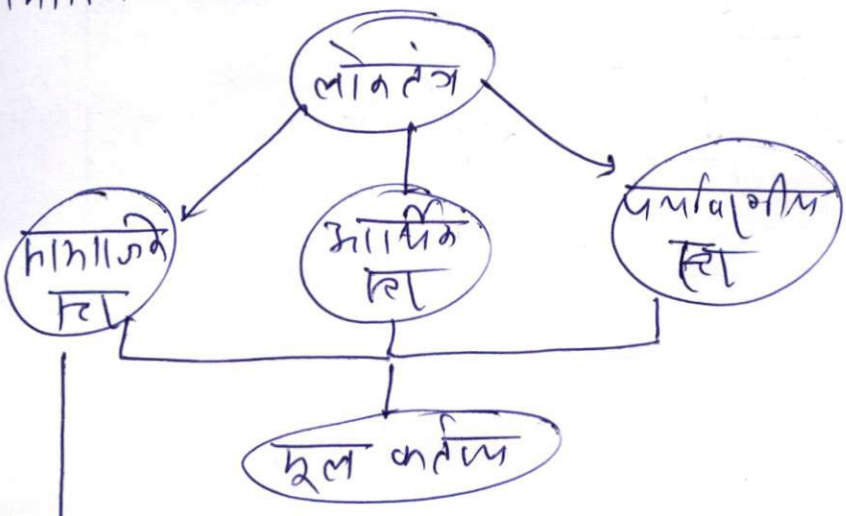

- लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करें।
- 6-14 वर्ष तक के बच्चों के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना।

- लोकतंत्र की स्थापना का मूल आधार देश की एकता व अखंडता है। मूल कर्तव्यों में देश की एकता, अखंडता को बनाये रखने की बात है।
- इस प्रकार मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों के समान महत्वपूर्ण हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

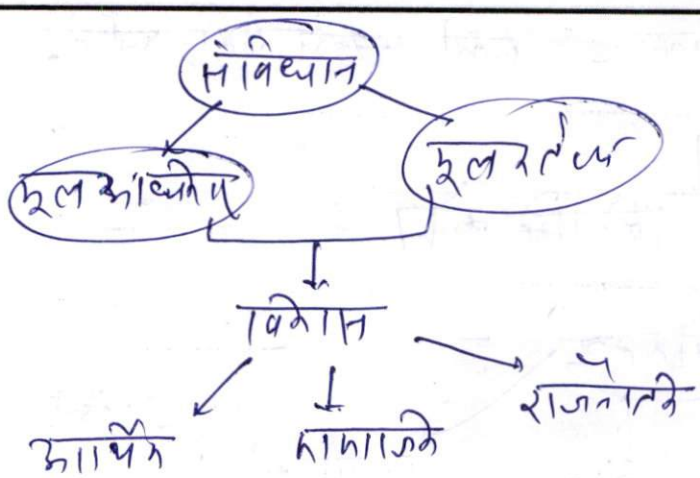

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Several constitutional experts have found the process of appointment and removal of governor to be against the very grain of democratic traditions and constitutional propriety. Do you think that this process warrants a fresh look in context of recent controversies surrounding the post?

कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्यपाल की नियुक्ति व इसे हटाने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक परंपराओं की मूलभावना और संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध पाया है। इस पद से जुड़े हाल के विवादों को देखते हुए क्या आप इस प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं?

वर्तमान में संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने हेतु मौजूद प्रावधानों का राजनीतिक उद्देश्यों से लाभ उठाया जाता है। "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगा"- यद्यपि ऐसी अवधि 5 वर्ष होगी।

तथापि राज्यपाल को हटाने हेतु वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा S.R. बोम्मई वाद कई महत्वपूर्ण फैसले दिये गये।

हाल में सरकार बदलने पर कई राज्यपालों को अपने पद से हटाया गया। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में न मानकर स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया था। किंतु राजनीतिक उद्देश्यों ने राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि बना दिया। अरुणाचल प्रदेश केस में राज्यपाल की भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की गई। राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकारिया आयोग व पुंछी आयोग द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई।

- राज्यपाल को राज्य के बाहरी व्यक्ति होना चाहिए।
- राज्यपाल को राजनीति में अनासक्त होना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री के सलाह ली जानी चाहिए।
- राज्यपाल को हटाने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तथा उसे कार्यकाल 5 वर्ष के पहले नहीं हटाना चाहिए।
- राज्यपाल 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त' पद पर रहेगा। इस कथन को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नहीं करनी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राज्यपाल को हटाने के पहले उसे अपनी स्पष्टता का मौका दिया जाना चाहिए।
- राज्यपाल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। जिसका राजनीतिकरण लोकतांत्रिक व संवैधानिक सिद्धांतों व मूल्यों के खिलाफ होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Repeated violations of the Model Code of Conduct (MCC) have raised questions on its effectiveness. In this light, discuss the idea of making MCC a part of Representation of Peoples Act, 1951.

आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) के बार-बार होने वाले उल्लंघन ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े किये हैं। इस आलोक में, आदर्श आचार संहिता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का हिस्सा बनाने के विचार पर चर्चा करें।

आदर्श आचार संहिता को चुनावों की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में लागू किया जाता है। यह संहिता चुनावी परिणाम आने तक लागू रहती है

मुद्दे:

- आचार संहिता के लागू होने के कारण विकासपरक व नीतिगत कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ता है।
- सिविल सेवकों व पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों का स्थानांतरण की शक्ति चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है
- आचार संहिता के लागू रहने पर भी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन न करना।
- वोट बैंक हेतु उपहारों का वितरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस संदर्भ में आचार संहिता को प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाने पर विचार चल रहा है।

- इसके पश्चात् आचार संहिता उल्लंघन करने पर पर्याप्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- राजनीतिक उम्मीदवारों पर लगाम लगाने का प्रयास होगा। उनके द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों को दूरंत प्रभाव से रोका जा सकेगा।
- निर्वाचन अभ्यागमी शक्तियों का विध्वंसीकरण होने से उनमें पर्याप्त स्पष्टता आयेगी जिससे निर्वाचन आयोग दूरंत प्रभावी कदम उठा सकता है।
- चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही का विकास होगा।
- राजनीतिक अपराधीकरण जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायक होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तथापि इस संबंध में विधेयक सोसायटी, चुनाव अध्योग, विधि आयोग के परामर्श विचार विमर्श का कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है।

आदर्श आचार संहिता का विश्लेषण चुनावी प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित का लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाकर सैद्धान्तिक सिद्धांतों को अभिपुष्टि प्रदान करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The government cannot condition receipt of public benefits on waiver of fundamental rights. Discuss this statement in context of the recent issues raised in the Aadhaar petitions.

सरकार, जनता के समक्ष कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकारों के परित्याग की शर्त नहीं रख सकती। हाल ही में आधार कार्ड से सम्बंधित याचिका में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें।

आधार कार्ड के संबंधित विवाद में प्रमुख मुद्दा 'निजता का अधिकार' से संबंधित है। सरकार द्वारा कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने में आधार की अनिवार्यता लोगों के निजता के अधिकार को प्रभावित करेगी।

मुद्दे :-

- आधार कार्ड की प्रक्रिया निजी कंपनियों को दी गई है ऐसी कंपनियों द्वारा डाटा का दुरुपयोग व्यक्ति की निजता को प्रभावित करेगा।
- आधार कार्ड में व्यक्ति का नामांकन से डाटा की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं सरकार द्वारा डाटा सुरक्षा के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने हेतु किसी संस्थान के प्रक्रिया को निर्धारित नहीं किया गया है ऐसे में व्यक्तियों के निजी डाटा की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

गोपनीयता खुलासे नहीं माने जा सकते।

एक बार आधार कार्ड बन जाने अर्थात सरकार के डाटा बेस में आ जाने पर उस व्यक्ति को हटने का अधिकार या अपनी निजी जानकारी समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यह व्यक्ति की 'विकल्पों की स्वतंत्रता' के अधिकार के खिलाफ होगा।

हाल में बच्चों के आधारकार्ड को भी इस आधार पर गलत माना जा रहा है क्योंकि भविष्य में बच्चों द्वारा आधार प्रणाली से हटने का विकल्प उनके सामने मौजूद नहीं होगा।

देश में साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों के परिप्रेक्ष्य में डाटा की सुरक्षा (वायरसों द्वारा) की चुनौती बनी हुई है।

हाल में महाराष्ट्र सरकार ने 10 वीं परीक्षा के लिए आधारी अनिवार्यता लागू करने के संबंध में कदम उठाये हैं। भारत जैसे देश के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

डाटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में ऐसे बाध्यकारी कदम को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

आधार बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों में छूट की निजता संबंधी मामले मार्गदर्शक के संबंध में प्रावधान है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम डाटा की गोपनीयता का नैतिक प्रश्न खड़ा कर देता है।

(अमेरिका में एपल-FBI का मामला)

अतः भारत को व्यक्तिगत अधिकारों को बनाये रखते हुए कल्याणकारी लाभों का अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए। आधार के संबंध में डाटा सुरक्षा हेतु एक जवाबदेह तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Though the institutions protecting human rights and rights of the vulnerable sections are meant to act as watchdogs, they are treated as subordinate departments with scant regard for their autonomy or statutory character. Discuss the issues which these institutions are facing related to appointment, structure and functioning.

यद्यपि मानवाधिकारों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संस्थानों से इन अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इन विभागों की स्वायत्तता या वैधानिक चरित्र के प्रति महज औपचारिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए अधीनस्थ विभागों जैसा व्यवहार किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा नियुक्ति, गठन और कामकाज से संबंधित सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

मानवाधिकारों से जुड़े संस्थान - जैसे - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय आदि का प्रमुख कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। तथापि प्रभावी व उपयुक्त शक्तियों के अभाव में इनकी कार्यविधि प्रभावित होती है।

संस्थानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां

- नियुक्ति संबंधी
- गठन संबंधी
- कार्यप्रणाली संबंधी

नियुक्ति संबंधी

- इन संस्थाओं की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जाती है।
- सदस्य व अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नियंत्रण में कोई मानक क्रियाविधि व वस्तुनिष्ठ प्रणाली नहीं है।

- अक्सर ऐसी संस्थाओं में मानवाधिकार विशेषज्ञों के स्थान पर नौकरशाह व न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
- संस्थाओं के सदस्यों को उपयुक्त योग्यता नहीं।

गठन -

- कई राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया गया है।
- मानवाधिकार संस्थाओं में उपयुक्त स्टाफ की कमी।
- स्टाफ सदस्यों का प्रशिक्षण न होना।

कार्यप्रणाली

- मानवाधिकार संस्थाओं की स्वयं की जांच एजेंसी न होने के कारण कार्यप्रणाली प्रभावहीन
- इनके द्वारा ऐसी किसी घटना का संज्ञान नहीं लिया जा सकता जिसे मीडिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आयोग का गठन बीत गया हो।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियम जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है जबकि मानवाधिकार के हनन संबंधित कई घटनाएं वहां होती हैं।

- इसी प्रकार इन संस्थाओं की रिपोर्ट केन्द्र/राज्य पर बाध्यकारी नहीं होती तथा इनकी सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

समाधान :

- इनकी रिपोर्ट पर संसद/विधानसभा में प्रभावी चर्चा की आवश्यकता।

- 2nd ARC रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Equality of seats among states in Rajya Sabha could not be adopted after independence because of the circumstances prevailing at that time. However, there is a need to take a fresh look at this. Evaluate.

स्वतंत्रता पश्चात् राज्यसभा में राज्यों के बीच सीटों की समानता की संकल्पना तत्कालीन परिस्थितियों के कारण नहीं अपनाई जा सकी। हालांकि इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन करें।

अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन भारत में राज्यसभा में सीटों की असमानता है। इस कारण उत्तरपूर्वी राज्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है।

तत्कालीन परिस्थितियों में राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति व अन्य संकल्पनाओं के कारण समानता की संकल्पना नहीं अपनाई जा सकी। तथापि वर्तमान पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है-

क्योंकि लोकसभा में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या आधार पर होता है। राज्यसभा में भी ऐसा कारक केवल दोहराव की स्थिति उत्पन्न करता है।

उत्तरपूर्वी राज्यों का संसद में प्रभावी प्रतिनिधित्व न होने के कारण इनके संबंधित मुद्दों की अवहेलना होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को, राज्यसभा में कुछ राज्यों का बहुमत होने के कारण प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा सकता है।
- इस संबंध में रेड्डी आयोग, सरकारिया आयोग ने भी समीक्षा की बात की थी।
- राज्यसभा में सीटों का समान वितरण राज्यों की समानतापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
- राज्य विशेष मुद्दों का प्रभावी निवारण हो सकेगा।
- वर्तमान में लोकसभा स्तर पर राज्यों से संबंधित मुद्दों के बढ़ने से राज्यसभा की भूमिका बढ़ेगी। इस संबंध में रचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता है ताकि सहकारी संघवाद की धारणा प्रभावी रूप से लागू हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

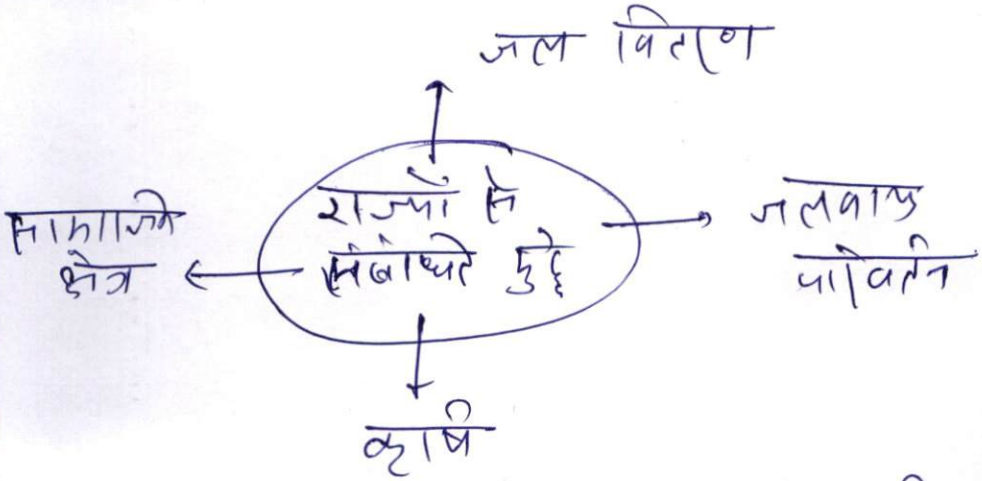

वैश्वीकरण दौर में राज्यों की भूमिका

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. It is contended that the implementation of One-Rank-One-Pension (OROP) for the armed forces would create a severe strain on government finances. Explain the principles underlying the OROP and arguments that have been cited in its support as well as opposition.

यह दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) का कार्यन्वयन सरकार के वित्त पर एक गंभीर दबाव उत्पन्न करेगा। ओ.आर.ओ.पी. के अन्तर्निहित सिद्धांतों तथा इसके समर्थन एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Article 311 of the Constitution has been a matter of much debate. Arguments range from its retention in its present form, or even strengthening it, to its total deletion. Comment.

संविधान का अनुच्छेद 311 बहस का महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस विमर्श में इसे वर्तमान रूप में ही बनाए रखने, अधिक सशक्त करने से लेकर इसके विलोपन तक के मुद्दे शामिल हैं टिप्पणी करें।

अनुच्छेद 311 में सिविल अधिकारियों की सुरक्षा के संबंधित प्रावधान हैं इसके अंतर्गत उन्हें हटाने से बचाने हेतु क्रियाविधि दी गई है।

एक केन्द्रीय कर्मचारी को हटाने के पहले उसे अपने बचाव का प्रस्ताव दिया जाएगा। केन्द्रीय कर्मचारी को उसके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा नहीं हटाया जायेगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिविल अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण उनको अधिक सुरक्षा प्रदान करना अप्रासंगिक सा लगता है। तत्कालीन परिस्थितियों में ही गई इस उपबंध का अधिकतर गलत इस्तेमाल ही हुआ है।

2nd ARC ने अपनी पहली शासन में नैतिकता रिपोर्ट में भी इसे हटाने की बात की थी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके स्थान पर 309 उपबंध को मजबूत करने की बात की थी।

(उद्देश्य) -

- 311 उपबंध का अत्याचारी व दोषी सिविल सेवकों द्वारा अधिक उपयोग
- प्रशासन के कार्यकुशलता में कमी
- ईमानदार सिविल सेवकों की आड़ लेकर दोषी सिविल सेवकों द्वारा प्रशासन के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना
- इस उपबंध के कारण दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रभावी सजा मिलने में सफल लग जाता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों के नजर में इस उपबंध की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। तथापि इसे पूरी तरह से हटाना ईमानदार सिविल सेवकों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While Public Interest Litigations have provided access to justice for the poor and the marginalized sections of the society but many vested interests have also misused it. In this context, examine the utility of PILs as a tool of social justice.

यद्यपि जन हित याचिकाओं ने समाज के निर्धन एवं अधिकार विहीन वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान किया है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जन हित याचिकाओं की उपयोगिता का परिक्षण करें।

जनहित याचिकाओं को निर्धन व अधिकारहीन वर्ग हेतु न्याय उपलब्ध कराने के लिए नवाचारी कदम के रूप में लागू किया गया था। तथापि वर्तमान में इन PILs का प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है-

संबंधित मुद्दे --

अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों द्वारा पंजाब, हरियाणा, NCR PIL की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि निर्धन राज्यों द्वारा डाली जाने वाले PIL की संख्या में कमी आई है।

PIL के द्वारा समृद्ध लोगों से संबंधित मुद्दों को उलझाया जाने लगा है। ~~मंत्रीजी क्रिकेट~~ के संबंध में PIL डाली जाने लगी है। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट हितों के संबंधित PIL में वृद्धि हुई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- समूह लोगों-राज्यों से दाखिल PIL पर सफलता का दर 74% है जबकि निर्धनों वाले वर्गों के केस में सफलता दर 49% है।
- PIL पर समूह व कॉरपोरेट लोगों के बढ़ते प्रभाव से गरीब वाले वर्गों के न्यायिक अधिकारों की अवहेलना होती है।

इस प्रकार न्यायपालिका को गरीबों के लिए जारी इस नवाचारी काम को जारी करने की आवश्यकता है। PIL के माध्यम से अधिकार विहीन लोगों तक न्याय पहुंचाने की आवश्यकता है।

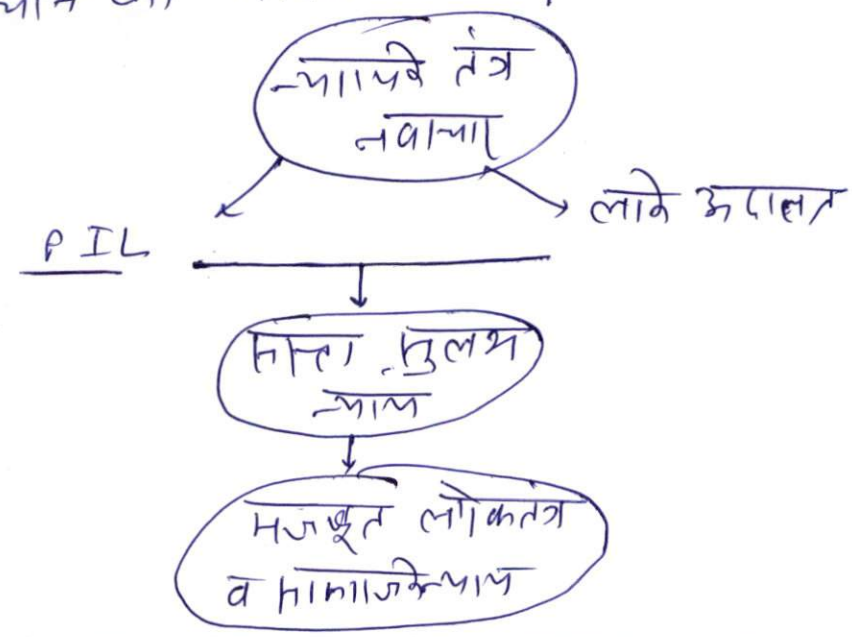

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. What do you understand by alternate dispute redressal mechanism? Discuss the various tools of ADR. In light of the problems faced by the Indian judiciary enumerate the advantages of Lok Adalats.

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से आप क्या समझते हैं? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (ए.डी.आर.) के विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। भारतीय न्यायपालिका के समक्ष पेश आ रही समस्याओं के आलोक में लोक अदालतों के लाभों का वर्णन करें।

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से अभिप्राय परंपरागत न्याय प्रणाली से अलग अदालती प्रक्रिया से है। इसका प्रमुख उदाहरण लोक अदालत, मध्यस्थता है।

लोक अदालत, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र द्वारा अपेक्षाकृत सस्ते माध्यमों का प्रयोग किया जाता है।

भारतीय न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियाँ:

विलंबित केसों की बढ़ती संख्या

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, अधीनस्थ कोर्टों में न्यायाधीशों की अनुपलब्धता।

केसों का प्रभावी निपटारे न निवारण की समस्या।

सस्ती प्रक्रिया न होना, शोषणकारी प्रवृत्ति की भावना, सुलभ न नहीं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इन चुनौतियों को दूर करने हेतु लोक अदालत एक प्रभावी विकल्प है-

- लोक अदालत परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से सस्ती प्रक्रिया है।
- इसमें तुरंत न्याय मिलता है। विलंबन की प्रक्रिया से बचा जाता है।
- इसके निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होते हैं तथा इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। इस प्रकार विवाद का तुरंत प्रभावी समाधान किया जाता है।
- इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश उपस्थित होते हैं तथा दोनों पक्षों को प्रभावपूर्ण सुनवाई किया जाता है।
- लोक अदालत से न्यायिक तंत्र में विद्यमान अनावश्यक केसों के बोझ को दूर किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

न्यायक्षेत्र

वैकल्पिक विवाद निवारण
↓
सत्ता सुलह मध्यस्थता
↓
आसान प्रक्रिया

न्यायालय
↓
केसों का विलंबन
↓
लंबी प्रक्रिया

इस प्रकार लोक अदालत एक प्रभावी विवाद निवारण तंत्र है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Bringing political parties under the ambit of RTI will not only usher accountability and transparency in governance but will also be a major step towards electoral reforms. Discuss.

राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के दायरे में लाने से न केवल पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन की शुरुआत होगी बल्कि यह चुनाव संबंधी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चर्चा करें।

सूचना के अधिकार अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। तथापि इसके अंतर्गत राजनीतिक दल शामिल नहीं है। पारदर्शी व उत्तरदायी शासन हेतु इन दलों को RTI के तहत लाना एक प्रभावी कदम होगा।

वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित है जबकि राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा निर्धारित नहीं है जिस कारण चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती।

राजनीतिक दलों द्वारा 20,000/- से अधिक की राशि देने वालों का ही लेखा जोखा रखा जाता है जबकि 90% से अधिक योगदान को 20,000/- से कम दर्शाया जाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक दलों को RTI में लाने से उनकी आंतरिक लेखांकन प्रक्रिया में सुधार होगा क्योंकि उन्हें एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। जो सूचनाएं उपलब्ध करायेगा।

राजनीतिक दलों को लाने के कारण,

- राजनीतिक दलों ~~द्वारा~~ को सस्ती जमीन उपलब्ध करवाई जाती है।
- सरकार माध्यमों में चुनाव प्रचार हेतु समय प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार अन्य गतिविधियों में दलों द्वारा करदाताओं के धन का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने हेतु उनको RTI के दायरे में लाने की आवश्यकता है। तथापि कई विषय जैसे- मीटिंग की आंतरिक बहस, निर्वाचन हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव, आदि को RTI के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता है ताकि RTI का दुरुपयोग न हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

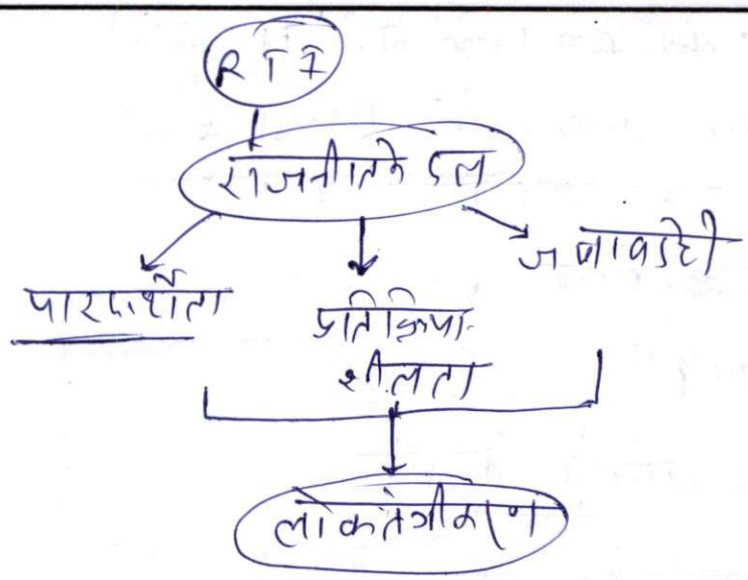

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. A generational shift in railway operations is required. In light of this, discuss the need for an independent tariff and safety regulatory authority of India.

रेलवे के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तथ्य के प्रकाश में, भारत के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ एवं सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें।

रेलवे के संचालन से जुड़े कई प्रचालनात्मक व अन्य समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में कई समितियों द्वारा सुझाव दिये गये हैं

काकोदर समिति

रेलवे समिति — विवेक देवराय समिति

सैम पित्रोदा समिति

रेलवे के राजनीतिकरण के कारण इसके संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इस हेतु एक स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ व सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर विवेक देवराय समिति ने भी बल दिया था।

रेलवे का किराया जन भावनाओं के मद्देनजर नहीं बढ़ाया गया। जिससे रेलवे राजस्व में कमी हुई।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- रेलवे में यात्री भाड़ा कम होने के कारण इसके क्रॉस सब्सिडाइजेशन (Cross subsidisation) की समस्या उत्पन्न होती है। मालभाड़े की दरें विश्व की दरों की तुलना में काफी अधिक है। इससे औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती है।
- सुरक्षा संबंधी मानकों पर ध्यान देने के बजाय लोकप्रियता पर अधिक बल दिया गया। जिससे कई समस्याएँ उत्पन्न हुई।
- इस संबंध में एक प्रभावी प्रावधान एवं महत्वपूर्ण कदम होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. It has been argued that the 'First past the post' system fails to represent the will of the majority and encourages vote-bank politics. In this context, examine whether India should adopt Proportional Representation System to reform our electoral process.

यह तर्क दिया जाता है कि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली बहुमत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर वोट बैंक की राजनीति को प्रोत्साहित करती है। इस संदर्भ में, इस बात का परिक्षण करें कि क्या भारत को अपनी चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना चाहिए?

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई गई जिसमें जो उम्मीदवार अधिक मत (चुनाव के कुल मत के 50% से कम हो) प्राप्त करता है वह जीतता है जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक उम्मीदवार का 50% से अधिक मत पाना जीतने हेतु अनिवार्य शर्त है

यद्यपि ऐसी प्रणाली के लाभ व हानि दोनों हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हानि:

इस प्रणाली में मतदाता पार्टी को मत देता है। अतः उसे अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के संबंध में जानकारी नहीं होती।

जटिल प्रक्रिया

ऐसी प्रक्रिया में गठबंधन प्रणाली को बल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मिलेगा। दलगत राजनीति को बल मिलेगा क्योंकि सीटों का बंटवारा मत प्रतिशत के अनुपात में होगा।
उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जवाबदेही कुछ कम हो जाएगी।

लाभ :
वहीं वोट बैंक की राजनीति कम प्रोत्साहित होगी। 50% से अधिक मत पाने वाली पार्टी ही उस क्षेत्र में विजयी होगी। जनता के मत का उचित मूल्य कुशलतापूर्वक होगा।
तथापि भारत के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली उचित है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सरल है जबकि आनुपातिक प्रणाली के जटिल होने के कारण मतदाताओं को प्रभावित करेगी।

'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली' के सरल होने तथा मतदाताओं को उम्मीदवारों की दक्षता की जानकारी होने के कारण अधिक प्रभावी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तौर पर मत डालने का अवसर मिलता है।

- चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- राजनीति का अपराधीकरण के बचने के उपाय करना
- उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करना
- राजनीतिक दलों की चुनावी खर्च सीमा निर्धारित करना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Independence of judiciary and separation of powers, both are part of the basic structure of the constitution. In this context, discuss the recent Supreme Court judgment on the constitutional validity of the National Judicial Appointments Commission.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं शक्तियों का विभाजन, दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.)की संवैधानिक वैधता पर दिए गए निर्णय पर चर्चा करें।

न्यायपालिका द्वारा हाल में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया गया। क्योंकि इसके द्वारा मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना (केशवानंद भारती वाद) हुई।

न्यायपालिका ने इस आयोग को इस आधार पर असंवैधानिक माना क्योंकि न्यायिक नियुक्ति का अधिकार न्यायाधीशों से लेकर अन्य शाखाओं को हस्तांतरित करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित होगी- ऐसा न्यायालय ने माना।

इसके अतिरिक्त न्यायिक आयोग में सदस्य मंत्री की उपस्थिति को शक्तियों के विभाजन सिद्धांत के खिलाफ माना। क्योंकि इससे कार्यपालिका का न्यायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तथापि राष्ट्रीय आयोग के संबंध में दी गई निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में न्यायाधीशों की कुशलता, योग्य कुशलता जैसे क्षेत्रों में बढ़ती रोलिफ्टता के बावजूद उन्हें हटाने की कोई ~~सरल~~ (महाभियोग के अलावा) प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया जटिल व लगभग असंभव सी है।

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव।

अन्य देशों में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका है।

इस परिदृश्य में नियुक्ति आयोग के संबंध में एक प्रगतिशील कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता को बनाया जा सके। न्यायिक जवाबदेही व स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्यायिक स्वतंत्रता को बनाये रखते

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हुए न्यायिक जवाबदेही का पालन न करना भी एक असंवैधानिक कार्य है। अतः इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

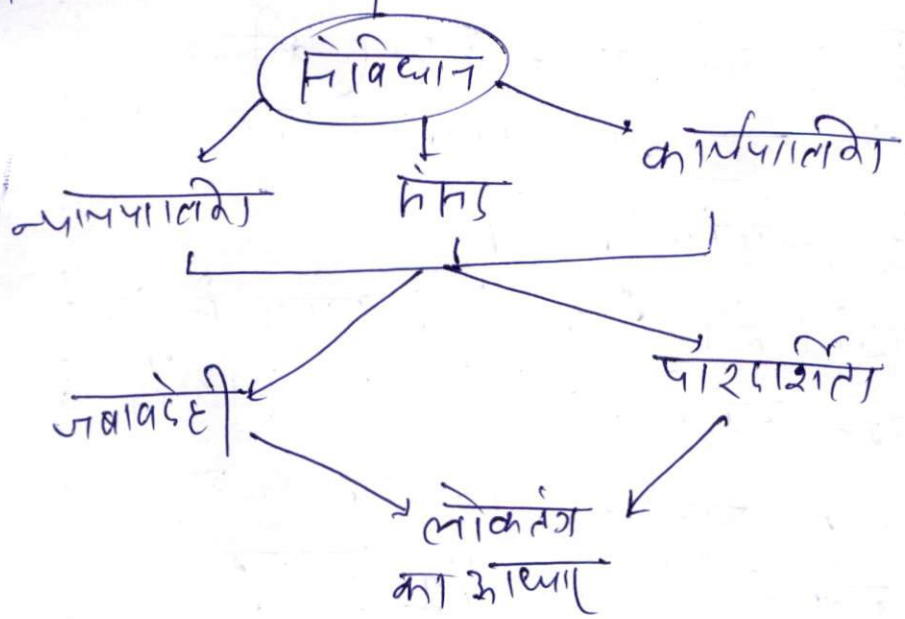

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. AMRUT gives state governments the flexibility in designing schemes and eases central monitoring. Explain. How far can it recast the urban landscape of India?

अमृत (AMRUT) राज्य सरकारों को योजनाओं के प्रारूप निर्धारण के सन्दर्भ में लचीलापन प्रदान करता है तथा केंद्र द्वारा की जाने वाली मॉनीटरिंग को आसान बनाता है। वर्णन करें। भारत के शहरी परिदृश्य को यह किस हद तक पुनर्निर्मित कर सकता है?

अमृत मिशन के अंतर्गत भारत के 500 प्रमुख शहरों का पुनर्नवीकरण व सुधार की योजना है यह JNNURM का एक अधिक प्रभावपूर्ण संशोधित रूप है।

इसमें राज्यों को योजनाओं के प्रारूप निर्धारण में उपयुक्त लचीलापन प्रदान किया गया है।

इस मिशन के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 1/3 सहायता केन्द्र देगा व 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में केन्द्रीय सहायता एक तिहाई होगी।

JNNURUM में जहां राज्यों की नगण्य भागीदारी थी तथा केन्द्र का इस नियंत्रण था वहीं यह योजना राज्यों को प्रभावपूर्ण भागीदारी प्रदान करती है।

तथा 'सरकारी सेवाओं' की 'सुगमता' सफल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बनाती है।

राज्यों को मानीटरिंग करने का भी अधिकार प्रदान है जिसमें केन्द्र सरकार उन सहायता प्रदान करेगी।

शहरों को चुनने के संबंध में भी योजनाबद्ध रूप से निर्धारण किया जायेगा जिसमें राज्यों व केन्द्र की भूमिका होगी।

भारत के शहरी परिदृश्य को निर्मित करने में इसकी प्रभावी भूमिका होगी।

शहरी क्षेत्र → AMRUT
शहरी क्षेत्र → स्मार्ट सिटी
AMRUT → केन्द्र-राज्यों की भागीदारी
स्मार्ट सिटी → केन्द्र-राज्यों की भागीदारी
↓
bottom-up उपागम
↓
भागीदारीपूर्ण शासन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना भागीदारीपूर्ण शासन विकसित करेगी।
- शहरी योजनाओं में राज्यों की प्रमुख भूमिका होने के कारण इनका कार्यान्वयन प्रभावी रूप से होगा।
- केन्द्र-राज्य संबंधों के सबल होने से प्रभावी निगरानी होगी जिससे योजनाओं का सुधार किया जा सकेगा।
- भारत में 2001 की तुलना में 2016 में शहरीकरण की आबादी लगभग दोगुनी (220 मिलियन से 420 मिलियन) हो गई है शहरीकरण को प्रभावी बनाने में अमृत की प्रमुख भूमिका होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There has been a tendency to resolve specialized cases faster through the means of Tribunals. In light of this, discuss the issue of increasing "tribunalisation" of courts in India.

न्यायाधिकरण जैसे साधनों के माध्यम से विशेष मामलों को तेजी से हल करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके सन्दर्भ में, भारत में न्यायालयों को न्यायाधिकरणीकृत करने की बढ़ती प्रवृत्ति के मुद्दे पर चर्चा करें।

न्यायाधिकरण विशेष मामलों को निपटाने हेतु बनाये जाते है। संविधान में अनुच्छेद 323 (क) व (ख) में प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं।

वर्तमान में न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों के त्वरित निपटान की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में इस संबंध में न्यायालयों का न्यायाधिकरणीकरण का मुद्दा प्रचलित हुआ है।

मुद्दा :

- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित। न्यायाधिकरण के माध्यम से कार्यवाही की जाती है।
- न्यायाधिकरण सदस्यों के न्यायिक विशेषज्ञ न होने के कारण उनसे जुड़ा मुद्दा।
- न्यायाधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्णय दिया जाता है। जिसमें

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1908, CRPC जैसी कानूनों का संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

- न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने में वादी के सभी पक्षों पर विचार न किया जाना।

- हाल में न्यायाधिकरण द्वारा कई फैसले दिये गये - डीजल वाहनों पर दिल्ली में रोके लगाना (10 वर्ष पुराने)
. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसले।
इनमें से कई फैसलों की आलोचना हुई इनके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई अधिकरण जैसे- राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण आदि को असंवैधानिक घोषित किया।

- इस संबंध में एक प्रभावशाली निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अधिकरणों के निर्णय से न्याय पालिका शक्तियों में कमी परिलक्षित न हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिकारों द्वारा न्यायपालिका के संज्ञान में मौजूद मुद्दों पर विचार नहीं करना चाहिए तथा अधिकरण द्वारा प्रभावी न्यायिक प्रक्रियाओं का मद्देनजर रखते हुए ही निर्णय देना चाहिए।

न्यायाधिकरण
↓
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रभावित
↓
तकनीकी मूल्यों की अवहेलना
↓
प्रभावी न्याय सुलभ न होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. While the 73rd and 74th constitutional amendments provided for representation to women in local governance, much work remains to be done to ensure their true participation, given their present socio-economic conditions. Comment.

यद्यपि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, लेकिन उनकी वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। टिप्पणी करें।

73 वें - 74 वें संविधान संशोधन (पंचायत व नगरपालिका) में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण की सुविधा दी गई थी। कई राज्यों ने इसे 50% किया गया। लेकिन महिलाओं की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

- महिलाओं के खिलाफ पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन नहीं आया है। जिन पंचायतों में महिला सरपंच या प्रधान है वहां भी पुरुष पति का प्रभाव आम है। इस संबंध में 'सरपंच पति' की अवधारणा सामने आई है।
- कई राज्यों - राजस्थान, हरियाणा ने पंचायती चुनावों हेतु न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य की है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसका भी महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की अपेक्षा कम है।

महिलाओं के नाम पर संपत्ति न होने के कारण उन्हें बैंकों से कर्ज मिलने में परेशानी होती है। महिलाओं की क्रेडिट स्थिति में अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है।

महिलाओं के स्थानीय प्रशासन में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनको पर्याप्त प्रशिक्षित, शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हो।

महिला सशक्तिकरण

सामाजिक स्थिति सुधार

आर्थिक स्थिति सुधार

लोकतंत्र मजबूत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं को प्रभावी आरक्षण सुनिश्चित करना
- महिलाओं की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना, ग्राम सभा - पंचायत की बैठकों में महिलाओं का बराबर भागीदारी दिलाना।

महिला भागीदारी बढ़ाने का एक उदाहरण राजस्थान की तोड़ा पंचायत की सरपंच छवि राजावत ने प्रस्तुत किया है जो प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है।

- महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने हेतु व्यवहारात्मक व मनोवैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R. No
09 OCT 2016
2
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 824)

Name of Candidate	Shailendra Singh Indoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	9/10/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Rights-based approach to social policy, which has rippled through India over the past decade and a half, reorients governance from ideas of patronage towards duty of the state and justified claims of citizens. Discuss with examples. Also, explain how the rights-based approach helps in improving public service delivery.

   'सामाजिक नीति के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण', जिसने पिछले डेढ़ दशकों से भारत को आंदोलित किया है। शासन को संरक्षण के विचारों से पुनः राज्य के प्रति कर्तव्य तथा नागरिकों के न्यायोचित अधिकारों की ओर ले जाता है। दृष्टान्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करें। इस बात की भी व्याख्या करें कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में किस प्रकार सहायता करता है?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक नीति- शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण से नागरिकों को प्रभावी सेवा उपलब्धि सुनिश्चित हुई है।

उदाहरण लिए- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से नागरिकों द्वारा प्रभावी सूचना प्राप्ति से उनकी शासन संबंधी प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

सरकार द्वारा नीति निर्माण → क्रियान्वयन
↓
नागरिकों तक सेवा की पहुंच
↓
भागीदारीपूर्ण शासन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इसी प्रकार शिक्षा के संबंध में न्यायालय व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से शिक्षा के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण विकसित हुआ है।
- सरकार द्वारा कल्याण आधारित उपागम से अधिकार आधारित उपागम की ओर जाने का चिंतन राष्ट्रीय महिला नीति में भी परिलक्षित होता है।

कल्याण आधारित उपागम
↓
अधिकार आधारित उपागम

नागरिकों की प्रभावी भागीदारी

जवाबदेह व पारदर्शिता पूर्ण शासन

समावेशी व न्यायपूर्ण लोकतंत्र

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सार्वजनिक सेवा वितरण में अधिकार आधारित दृष्टिकोण का लाभ :

- नागरिकों द्वारा सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता मिलती है.
- योजनाओं की नागरिकों तक प्रभावी पहुंच
- सहभागी व नागरिक भागीदारीपूर्ण शासन का विकास
- सार्वजनिक सेवा वितरण में लीकेज की समस्या का कम होना

- हाल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, RTI कैसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण से नागरिकों तक प्रभावी लाभ की पहुंच सुनिश्चित हुई है.

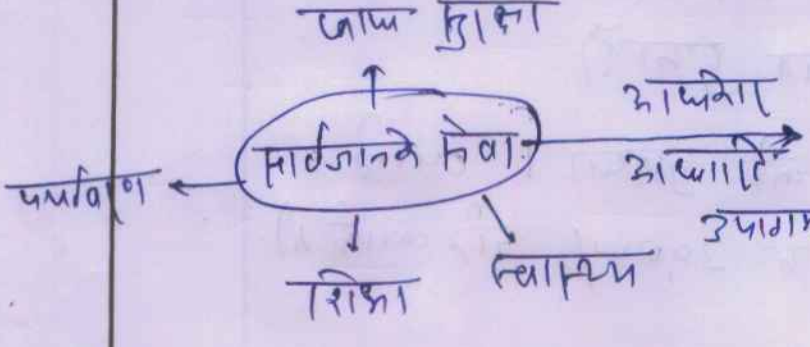

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Despite high enrolment in Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), out-of-pocket expenditure on health has steadily increased over the years. In this context, highlight the achievements and shortcomings of RSBY. Also, discuss the challenges faced in its implementation.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) में उच्च नामांकन (इनरोलमेंट) के बावजूद, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में वृद्धि हुई है। इस सन्दर्भ में, आर.एस.बी.वाई. की उपलब्धियों तथा कमियों पर प्रकाश डालें। इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा की आम लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना था। आउट ऑफ पॉकेट व्यय लोगों की आय की तुलना में आधिक व्यय से संबंधी स्थिति है।

RSBY की उपलब्धियां:

- स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में नागरिकों को प्रभावी बीमा उपलब्धता सुनिश्चित
- गरीबों वंचित वर्गों का प्रभावी इलाज कुछ हद तक संभव हुआ है
- कैशलेस उपचार की सुविधा। लोगों व परिवार को अधिकतम 30,000/- प्रति लोगों की सुविधा प्राप्त है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कमियां :

- RSBY की प्रभावी पहुंच न होना
- ग्रामीण क्षेत्रों में RSBY के प्रचार व जागरूकता हेतु आशा सहयोगियों का प्रभावी ढंग से उपयोग न करना।
- RSBY की योजनागत व प्रक्रियागत खामियां।
- RSBY हेतु लाभार्थियों की उपयुक्त पहचान न हो पाना।
- निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे में प्रभावी ढंग से न ला पाना।

कार्यान्वयन में चुनौतियां :

- RSBY की निगरानी हेतु उपयुक्त तकनीकी तंत्र का अभाव।
- अस्पतालों के स्तर पर अनियमितताओं की स्थिति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- योजना का विस्तार सभी लाभार्थियों तक न होना। RSBY की लाभार्थिता हेतु स्मार्टकार्ड बनने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- निजी अस्पतालों व सरकारी अस्पतालों के मध्य सामंजस्य का अभाव।

RSBY को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करके स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं को हासिल किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Unhealthy competition between Self Help Groups (SHGs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) reduces the effectiveness of both. Discuss. How can creating a synergy between the two help in addressing development challenges at the sub-district level?
स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) तथा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा, दोनों की प्रभाविता को कम करती है। चर्चा करें। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से उप-जिला स्तर पर विकास की चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है?

स्वयं सहायता समूह व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य प्रक्रियागत व संरचनागत स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर्द्वंद्व, वर्तमान में दोनों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा दोनों की प्रभाविता को कम कर रही है।

- स्वयं सहायता समूह में पंचायतों का बढ़ते प्रभाव के कारण अनावश्यक राजनीतिकरण की स्थिति होना।
- पंचायतों द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्धारित गतिविधियों में दखलंदाजी।
- स्वयं सहायता समूह में समान स्तर के सदस्यों (विशेषकर गरीबों, उपेक्षित, महिला) के बजाय पंचायती स्तर पर प्रभावी व्यक्तियों की भागीदारी होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- स्वयं सहायता समूह व पंचायती संस्थानों द्वारा एक दूसरे के कार्यों में प्रभावी सहयोग न करना। दोनों द्वारा कार्यों के संबंध में उपयुक्त परामर्श, विचार विमर्श का अभाव है।

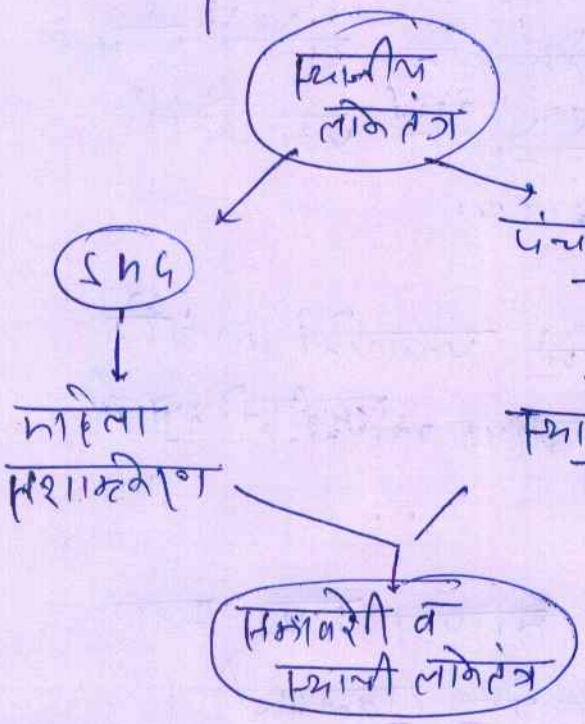

दोनों के बीच सामंजस्य से प्रभावी विकास

- SHG व PRI के बीच प्रभावी सामंजस्य से विकासपूर्ण गतिविधियों का प्रभावी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

- S.H.G. व पंचायतों के बीच कार्यों के संबंध में प्रभावी विचार विमर्श के स्थानीय स्तर पर विकास की गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन होगा।

S.H.G. व PRI के बीच सामंजस्य स्थानीय स्तरीय समस्याओं का प्रभावी निगरानी कर उनका समाधान करेगा।

- S.H.G. का अनावश्यक राजनीतिकरण रुकेगा।

- S.H.G. में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी व पंचायतों द्वारा S.H.G. पर प्रभुत्व की स्थिति समाप्त होगी।

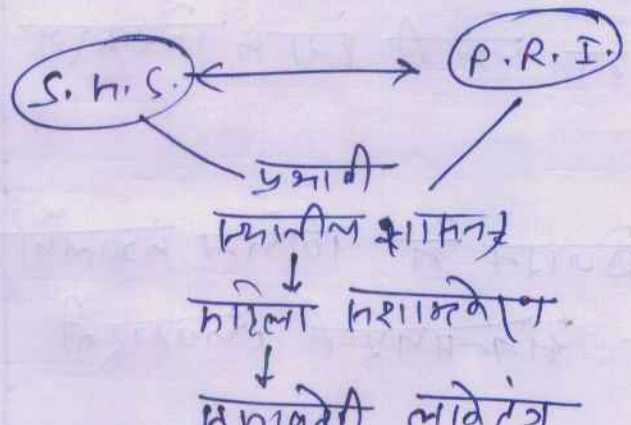

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. With an expected increase in old age population in the near future, there is a need to increase the ambit and reach of social safety net for their welfare. Discuss the challenges which policymakers face in design, development and execution of welfare measures for the elderly. How far do the recent measures taken by the government address these?

निकट भविष्य में वृद्ध आबादी में अनुमानित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, वृद्ध जनों कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे को बढ़ाने और इस तंत्र की पहुँच उन तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नीति-निर्माताओं द्वारा सामना की जा रही उन प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए जो बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना, विकास और उनके क्रियान्वयन से सबंधित हैं। सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम इन चुनौतियों का किस हद तक समाधान करते हैं?

निकट भविष्य में भारत में वृद्ध आबादी के लगभग 12% होने की उम्मीद है, वृद्ध जनों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रभावी नहीं है।

कल्याणकारी योजनाओं की डिजाइन में चुनौती :

कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में वृद्ध/वरिष्ठ जनों की भागीदारी न होने के कारण उनकी आकांक्षाओं का प्रभावी ढंग से निराकरण नहीं होता है।

योजनाओं के डिजाइन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वयपूर्ण व्यवहारी की कमी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- योजनाओं के डिजाइन में उपलब्ध कमियों को दूर करने हेतु स्कीमों की प्रभावी मॉनीटरिंग नहीं की जाती है।

कल्याणकारी योजनाओं के विकास में चुनौतियां :

- वर्तमान में वृद्ध सुरक्षा के कई आयाम हैं जबकि योजनाओं में केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है।
- योजनाओं का विकास वृद्धजनों की नये दौर में बढ़ रही समस्याओं को दरकिनार कर किया जा रहा है।
- वृद्धजनों से जुड़े गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी की योजना स्कीमों के विकास में भागीदारी नहीं।

क्रियान्वयन में चुनौतियां :

- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव
योजनाओं के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु
प्रभावी संस्थागत निगरानी तंत्र का अभाव
योजनाओं के संबंध में वृद्ध लोगों
से फीडबैक न लेने से कमियां बनी
रहती है।

सरकार द्वारा हाल के कदम:

वृद्ध जनों हेतु 2007 में वरिष्ठ जन
सुरक्षा कानून पारित किया गया।
हाल में SC (सुप्रीम कोर्ट) ने पति को
माता पिता से अलग करने के पत्नी के
कृत्य को तलाक का आधार माना है।

वृद्धजनों की पेंशन, सुरक्षा में प्रभावी
उपाय।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Civil Society Organizations and Corporates share a symbiotic relationship, which can be leveraged to meet the developmental needs of India. Analyze. Also enumerate the CSR provisions under Companies Act, 2013.
नागरिक समाज संगठन तथा कॉर्पोरेट के सहजीवी संबंध, भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में लाभदायक हो सकता है। विश्लेषण करें। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर. संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें।

सिविल सोसायटी व कॉरपोरेट का परस्पर संबंध नागरिकों हेतु बुनियादी आवश्यकताओं की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है

कॉरपोरेट के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में इन्हें प्रभावी प्रावधान किये गये हैं

सिविल सोसायटी ⟷ कॉरपोरेट
↓ ↓
योजनाओं की प्रभावी पहुंच - नागरिकों में जागरूकता → भागीदारीपूर्ण शासन
वित्त उपलब्धता

कॉरपोरेट द्वारा सिविल सोसायटी के साथ मिलकर स्थानीय स्तरी समस्याओं को जानकर उनका प्रभावी समाधान किया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 में C.S.R प्रावधान,

इस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित लाभ को अर्जित करने वाली कंपनियों को कुल लाभ का 2% CSR गतिविधियों में देना अनिवार्य है।

- C.S.R. गतिविधियों का प्रभावी निर्धारण सिविल सोसायटी के माध्यम से हो सकता है।
- इसका प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरणीय सुधार जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है।

C.S.R. संबंधी मुद्दे

- कंपनी अधिनियम, 2013 में C.S.R. (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) संबंधी गतिविधियों को स्पष्टतया नहीं बताया गया है।
- कई कंपनियों द्वारा C.S.R. का प्रयोग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ब्रांड प्रमोशन के तौर पर किया जा रहा है।

- सभी कंपनियों द्वारा C.S.R. का प्रभावी उपयोग नहीं हो रहा है।
- C.S.R. के गैर अनुपालन की स्थिति में कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में नहीं है।

इस कारण C.S.R. मानकों का उपयोग कई कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

- C.S.R. गतिविधियों की स्थानीय शासन से सहसम्बद्धता हेतु कोई संस्थागत तंत्र उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार सिविल सोसायटी व कॉरपोरेट के मध्य सहभागी संबंध विकसित करने हेतु C.S.R. का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है। इस हेतु कंपनी एक्ट 2013 में कुछ सुधार आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. According to a recent WHO report, India sees the largest number of suicides globally. In this context, enumerate the objectives and approach of India's new National Mental Health Policy. Also, explain what is Mental Health Action Plan 365.

हाल की डब्ल्यू.एच.ओ. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सर्वाधिक आत्महत्याएं भारत में होती हैं। इस संबंध में, भारत की नवीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों तथा दृष्टिकोणों का उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 365 के संबंध में विस्तार से बताएं।

W.H.O. रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक आत्महत्या वाला देश माना गया है इसके कई कारण - सामाजिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक हैं भारत की नवीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति में इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

उद्देश्य :

- मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में उपयुक्त दशाओं का निर्माण करना
- मानसिक स्वास्थ्य को बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित करना
- मानसिक अवसाद ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को कम करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दृष्टिकोण :

- इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने हेतु बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं के विकल्प बल दिया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य हेतु मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में उचित संशोधन की बात की गई है।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगी को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग देने की बात की गई है।
- इस नीति में मानसिक अस्वस्थ को रोगी/मरीज की तरह उपचारित न करके एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपचारित करने को कहा गया है।
- मानसिक अस्वस्थता की स्थिति को एक रोग न मानकर एक स्थितिजन्य कारक माना गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 1367

इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को बुनियादी रूप से स्थापित करने का प्रावधान है व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य हेतु उचित संस्थान उपलब्ध कराने की योजना है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Urban sanitation has not received adequate attention at the national level in the past and few initiatives have been taken to tackle deficiencies in urban sanitation. In light of this, examine whether the Swachh Bharat Abhiyan can help in solving the urban sanitation problem.
अतीत में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तथा शहरी स्वच्छता में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए कुछ ही कदम उठाए गए थे। इस कथन के आलोक में इस बात का परीक्षण करें कि क्या स्वच्छ भारत अभियान शहरी स्वच्छता की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है?

अतीत में शहरी स्वच्छता को शहरी योजना विभाग के एक प्रमुख तत्व के रूप में नहीं लिया गया था इसके कारण शहरीकरण के बाद शहरों का योजनाबद्ध विकास नहीं हुआ। वर्तमान में शहरी आबादी 32% है जिसके 2030 तक 40% होने की उम्मीद है

राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम
↓
निर्मल भारत अभियान
↓
स्वच्छ भारत अभियान

} स्वच्छता हेतु तीन कार्यक्रम

स्वच्छ भारत अभियान (2014-2019) तक क्रियान्वयन में रहेगा। इसका लक्ष्य 2019 तक खुले में शौच को रोकना, शहरों में प्रभावी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वच्छता लाना है

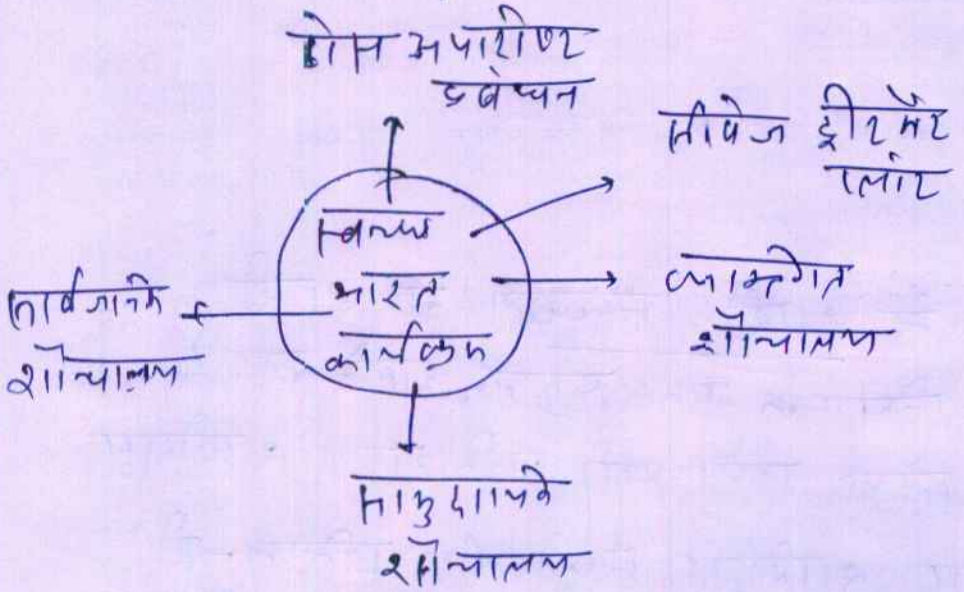

वर्तमान में शहरों की प्रमुख समस्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। जिसका प्रभावी निपटान स्वच्छ भारत कार्यक्रम के द्वारा शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

सुझाव :

स्वच्छ भारत अभियान में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण पर बल देने की आवश्यकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में सामाजिक सोच्यता के कुछ विशेषताओं के कारण WHO मानकों के गड्ढे वाले शौचालयों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

- शौचालयों में पानी की उपलब्धता न होना।
- स्वच्छता संचार तंत्र पर प्रभावी रूप से ध्यान न देना।

तथापि स्वच्छ भारत अभियान एक ऐतिहासिक प्रभावी पहल है इसका क्रियान्वयन शहरी स्वच्छता को प्रोत्साहित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. There is a need to move away from debates of 'public' versus 'private' provision of education towards models of education provision with public funding and private management. Discuss. Can such a move impact the quality and learning outcomes in elementary education?

अब शिक्षा के सार्वजनिक बनाम निजी प्रावधान संबंधी बहसों से आगे, सार्वजनिक वित्तीय सहायता तथा निजी प्रबंधन संबंधी प्रावधान वाले शैक्षिक प्रतिदर्शों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। चर्चा करें। क्या इस प्रकार का कदम प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा सीखने (अधिगम) की प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित कर सकता है?

शिक्षा के संबंध में वर्तमान में सार्वजनिक वित्तपोषण व निजी प्रबंधन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक वित्तपोषण

- शिक्षा के सेवा के रूप में होने के कारण सार्वजनिक वित्तपोषण की आवश्यकता है। निजी वित्तपोषण के परिणामस्वरूप शिक्षा का वाणिज्यीकरण का खतरा बढ़ जाता है।
- शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है। निजी वित्तपोषण से शिक्षा क्षेत्र में विषमता बढ़ने की संभावना है क्योंकि कीमतें संपन्न निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक कारक बनेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निजी प्रबंधन की आवश्यकता :

- शिक्षा क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निजी प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अधिक प्रभावी है।

- निजी प्रबंधन से बच्चों को प्रभावी शिक्षा के साथ प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का भी विकास होगा।

उपलब्धि — शिक्षा — पहुंच, अधिगम

- निजी प्रबंधन शिक्षा की पहुंच, अधिगम बढ़ाने में भी सहायक होगा।

=> ऐसा करना शिक्षा की गुणवत्ता व सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव नहीं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

डालने की संभावना है। तथा साथ इसके क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षकों के बेहतरीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

आंगनवाड़ी प्रक्रिया को आगे प्रभावपूर्ण बनाने हेतु उपयुक्त निरीक्षण व्यवस्था होना अनिवार्य है।

पाठ्यक्रम विस्तृत तथा निजी प्रबंधन शिक्षा को समावेशीपूर्ण व प्रभावपूर्ण बनाने की दिशा में एक तर्कसंगत कदम होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) bill recently passed by the Parliament is a regressive step towards protecting child rights in India. Examine.
हाल ही में संसद द्वारा पारित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक भारत में बाल अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है। परीक्षण कीजिए।

किसी भी देश की न्याय व्यवस्था को दण्डात्मक/प्रतिशोधात्मक होने की बजाय सुधारात्मक होना चाहिए। वर्तमान में किशोर न्याय (देखभाल व संरक्षण) अधिनियम के प्रावधान कई मामलों में प्रतिगामी प्रतीत होते हैं।

नकारात्मक पक्ष -

16-18 वर्ष के किशोरों द्वारा किये जघन्य अपराध (जिनमें बलात्कार की सजा 7 वर्ष से अधिक मिल सकती है) में उन्हें वयस्क की तरह उपचारित किया जा सकेगा।

बालक के तौर पर मुकदमा चलाने का निर्णय किशोर न्याय बोर्ड का होगा। जबकि वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड में मनोवैज्ञानिकों की कमी है तथा बोर्ड में प्रभावी मनन व्यक्तियों का अभाव है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किशोर न्याय
बिल

बाल कल्याण समिति
↓
बाल रक्षा हेतु

किशोर न्याय बोर्ड
↓
कानून से साथ संघर्ष की स्थिति वाले किशोर

प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियां प्रावधान। यद्यपि इनकी संख्या हेतु स्पष्टता नहीं है।

समाधानात्मक पक्ष.

CARA (केन्द्रीय दत्तक विनियमन प्राधिकरण) को सांविधिक दर्जा दिया गया है। यह बच्चों के गोद लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को विनियमित करती है इससे बच्चों के गोद लेने की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रक्रिया में सुधार आयेगा।

- इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों में समन्वय का अभाव इस बिल को एक प्रतिगामी कदम बनाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चे की उम्र 18 से कम मानी गई है।

- आपराध्ये संहिता में परिवर्तन से IPC के अंतर्गत 18 साल की उम्र से कम किशोर द्वारा सहमतिपूर्ण यौन संबंध भी अपराध की श्रेणी में ला देगा जिसमें उस पर बड़े कार्यवाही इस बिल के अंतर्गत हो सकती है। (जघन्य अपराध श्रेणी)

- इन मुद्दों को संबोधित करने इस बिल में प्रभावी सुधार की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. "In a nation of one billion cell phones, M-governance or mobile governance has the potential to make development a truly inclusive and comprehensive mass movement". Illustrate how M-government can bring in more transparency and accountability in government functioning. Also, discuss the challenges in implementing M-government.

"एक अरब सेल फोन वाले देश में एम-शासन या मोबाइल शासन में, विकास को वास्तविक रूप में समावेशी तथा व्यापक जनांदोलन का रूप प्रदान करने की क्षमता है।" दृष्टांत के साथ व्याख्यायित करें कि एम-शासन किस प्रकार सरकार के काम-काज में और अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व ला सकता है। इसके अतिरिक्त, एम-शासन के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

M. गवर्नेंस से तात्पर्य प्रशासनिक योजनाओं की प्रभावी सुपुर्दगी में मोबाइल के प्रयोग से है। मोबाइल का प्रयोग JAM ट्रिनिटी (जनधन-आधार-मोबाइल) में फल रहा है।

मोबाइल शासन से विकास समावेशी व व्यापक बनेगा।

मोबाइल शासन

समावेशी
मोबाइल तक सभी की पहुंच से लाभ परियोजनाओं किसानों का लाभार्थियों को प्रभावपूर्ण लाभ मिलेगा।

व्यापक
मोबाइल द्वारा किसानों की व्यापक रूप से पहुंच

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- मोबाइल के प्रयोग से सब्सिडी का प्रत्यक्षीकरण हुआ। JAM trinity से लाभार्थी की लाभार्थियों तक प्रभावी पहुँच द्वारा लीकेज की समस्या का समाधान हुआ।

- सरकार की योजनाओं की लाभार्थियों को प्रभावी जानकारी मिली। जागरूकता का विकास होने से अधिकार आधारित दृष्टिकोण विकसित हुआ।

- केरोसीन, राशन के संबंध में ग्रामीण इलाकों पर सामग्री की उपलब्धता के संबंध में लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज जा सकता है जिससे उन्हें बार-बार आने की बजाय एक बार सामग्री ले जाने का लाभ मिलेगा।

- ब्राजील जैसे देश में मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सब्सिडी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित हुआ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

डिजीटल गवर्नेंस / मोबाइल गवर्नेंस

मोबाइल ⟷ आधार

↓

बैंक में जुड़ाव

↓

प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण

↓

समावेशी शासन

गवर्नेंस में चुनौतियां :

- मोबाइल का उपयोग करने के संबंध में कई लोगों में जागरूकता का अभाव
- चीनी (Chinese) मोबाइलों के बढ़ते प्रयोग से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां
- गांव में बिजली समस्या के कारण मोबाइल चार्जिंग की समस्या

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. The Rights of the Persons with Disabilities Bill, 2014 fails to adopt United Nation Convention on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD) in its true spirit. Examine. Also, highlight the recent suggestions made by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment in this regard.

नि:शक्तजन अधिकार विधेयक-2014, नि:शक्तजनों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) को सही अर्थों में अपनाने में विफल रहा है। परीक्षण करें। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण से संबंधित स्थायी समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों पर प्रकाश डालें।

निशक्त अधिकार विधेयक, 2014 द्वारा संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया।

संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में निशक्त जनों के सरकारी सेवाओं, रोजगार में भागीदारी संबंधी प्रावधानों को इस बिल में अपूर्ण रूप से अपनाया गया है।

बिल में निशक्त जनों हेतु आरक्षण को 5% तक करने की बात की गई है।

अभिसमय में निशक्तजनों हेतु प्रभावी वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र की बात की गई है। जबकि बिल में इस तरह के प्रावधान का अभाव है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- बिल में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर निशक्तजन कल्याण बोर्ड बनाने की बात की गई है। जबकि इन बोर्डों के संबंध में प्रभावी शक्तियों व कार्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निशक्तजनों के लिए कल्याण आधारित उपागम के बजाय अधिकार आधारित उपागम पर बल दिया गया था जिसका अभाव इस बिल में दिखाई देता है।

- बिल में राष्ट्रीय व निशक्तजन समिति के संबंध में उपयुक्त प्रावधानों का अभाव।

- बिल की ड्राफ्टिंग व विकास में निशक्तजनों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। सिविल सोसायटी, NGO का बिल निर्माण में प्रभावी योगदान नहीं लिया गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थायी समिति द्वारा इन्हें सुझाव -

- रोजगार, सेवा के विशेषज्ञों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- उपयुक्त मॉनीटरिंग हेतु मेरुदण्ड तंत्र उपलब्ध कराना।
- विशेषज्ञों की प्रभावी भागीदारी हेतु बोर्ड, प्राधिकरण को सशक्त बनाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. An empowered Gram Sabha is the bedrock of successful local governance. In this context, analyse the role of Gram Sabha as a pillar of development. What steps can be taken to strengthen their functioning?
एक सशक्त ग्राम सभा सफल स्थानीय शासन का आधार है। इस संदर्भ में, विकास के एक स्तंभ के रूप में ग्राम सभा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उनके कामकाज को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

सशक्त ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को जीवंत करने हेतु आवश्यक है। ग्रामसभा में उस गांव के सभी वोट डालने हेतु योग्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं (वोटिंग लिस्ट में नामदर्ज)

- ग्राम सभा की विकास के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी भागीदारी है।
- सोशल ऑडिट के द्वारा ग्राम सभा प्रमुख अधिकारी का निर्वहन करती है जिससे स्थानीय स्तर के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है।
- विभिन्न परियोजनाओं जैसे- मनरेगा के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है।
- स्थानीय स्तर के लोगों की प्रशासन में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

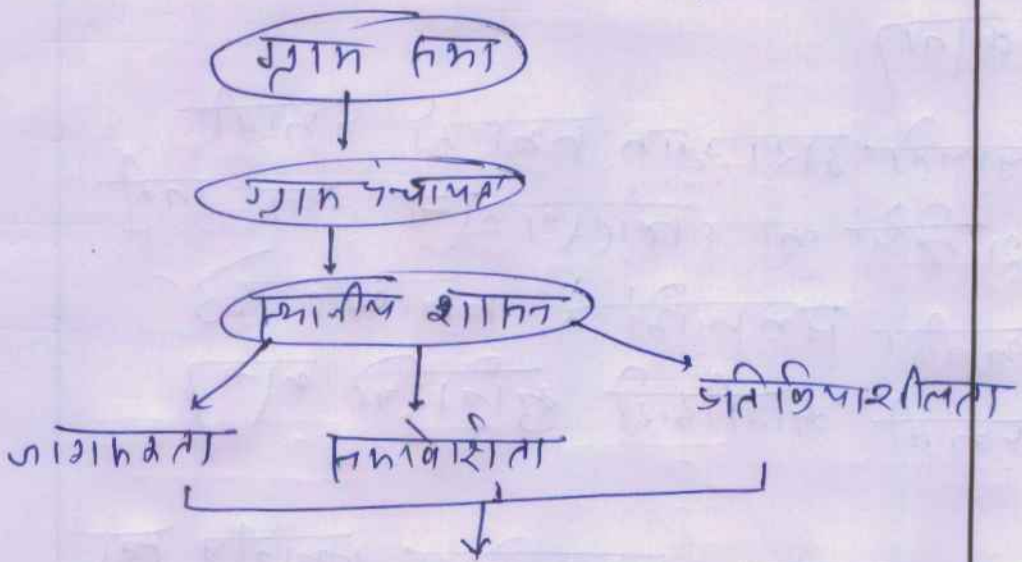

मजबूती देने कदम:

- ग्रामसभा की बैठकों को नियमित स्तर पर लागू करना।
- ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत प्रयास करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों को पंचायतों के ऊपरी स्तरों तक विचारार्थ करना।
- पंचायतों द्वारा ग्राम सभा को प्रभावी शक्तियों का हस्तांतरण करना तथा उनकी स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभाएं सशक्तिकरण स्थानीय स्तर की समस्याओं का प्रभावी निराकरण कर लोकतांत्रिक पद्धति का सशक्तिकरण करेगा।

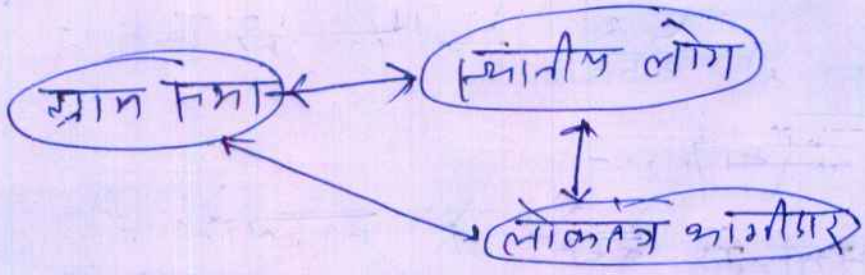

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The recent amendments to Child Labour Act seek to strike a balance between the need for education of a child and the reality of the socio-economic conditions. Critically evaluate.
बाल श्रम अधिनियम में हाल में किये गए संशोधनों का उद्देश्य किसी बालक की शिक्षा की आवश्यकता तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति की वास्तविकता में संतुलन स्थापित करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

बाल श्रम अधिनियम में वर्तमान संशोधन आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किये गये हैं।

- संशोधनों में बालक की शिक्षा व सामाजिक आर्थिक स्थिति में संतुलन परिवार के उपक्रमों के संबंध में स्थापित किया गया है।

14 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी तरह के नियोजन में प्रतिबंधित किया गया है लेकिन पारिवारिक उपक्रमों को इससे छूट प्रदान की गई है यदि उनके द्वारा बच्चे की शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित न हो (स्कूल के घंटों के बाद परिवार कार्य)

- 14-18 उम्र के बच्चों के लिए किशोर श्रेणी बनी है। 18 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उपक्रमों में नियोजन का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें अत्यन्त उच्चकोटी 3 श्रेणियां बनाई गई है।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया गया है।
- बच्चों के पुनर्वास हेतु पुनर्वास कोष बनाया गया है।
- यद्यपि पारिवारिक उपक्रमों के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है क्योंकि वर्तमान में कई रिश्तेदारों द्वारा ही बच्चों का उपयोग के नाम पर शोषण किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त माता पिता द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर प्रथम बार में कोई सजा न होने का प्रावधान है। अधिकतर स्थिति में गरीब अभिभावकों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा बच्चे का नियोजन उपकरणों में किया जाता है।

समाधान :

- कानून में निरोधकों को प्रभावी बनाने हेतु इनका क्रियान्वयन आवश्यक है। पारिवारिक उपकरणों संबंधी कौशल की शिक्षा बच्चे को स्कूलों में देने का प्रावधान भी किया जा सकता है।
- पारिवारिक उपकरणों के माध्यम बच्चों का शोषण न हो। इसके मॉनीटरिंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।
- बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों व नीतियों (जैसे- राष्ट्रीय बाल नीति) में समन्वय की आवश्यकता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Give an account of the features of 'Housing for All by 2022' mission. Also, discuss the challenges that lie ahead in its implementation.
"2022 तक सबके लिए आवास मिशन" की विशेषताओं का विवरण दें। इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

2022 तक सबके लिए आवास मिशन का उद्देश्य 2022 तक भारत के सभी नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना है।

हाउसिंग फॉर ऑल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

PMAY- शहरी

इसी आवास योजना की तुलना में "सबके लिए आवास योजना-2022" में वित्त को बढ़ाया गया है।

योजना की निगरानी हेतु उपयुक्त तकनीकी तंत्र का विकास किया गया है।

ग्रामीण व शहरी दोनों स्तरों पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का प्रयास है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ :

- वित्तपोषण की समस्या
- क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव।
- विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्यता का अभाव।
- योजना को लागू करने हेतु राज्य व केन्द्र के बीच प्रभावी तालमेल की आवश्यकता है। कई राज्यों में इस तालमेल का अभाव है।
- घरों के उन्नयन का प्रावधानों का उपयोग न होना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपोजना की जागरूकता का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Enumerate the directives laid down by the Supreme Court for police reforms in the Prakash Singh case. Discuss the challenges faced in implementing these reforms.
प्रकाश सिंह वाद में पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख करें। इन सुधारों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

प्रकाश सिंह वाद में सुप्रीमकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देशों का उल्लेख किया।

- राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की बात की गई जिसका कार्य उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण, पदोन्नति के संबंधित मामलों को देखना था।
- पुलिस कमीशन की नियुक्ति न्यूनतम 2 साल तक की जायेगी तथा इसका स्थानांतरण आयोग की सिफारिश पर होगा।
- पुलिस के गंभीर मामलों की सुनवाई हेतु स्वतंत्र सुरक्षा आधिकरण का गठन किया जायेगा।
- पुलिस तंत्र में संस्थागत, संरचनागत सुधारों हेतु सिफारिशें दिये गये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अपराधिक प्रक्रिया संहिता में सुधार का निर्देश।
- पुलिस में कांस्टेबल स्तर पर सुधार का निर्देश। कांस्टेबल व पुलिस अधिकारियों हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण का विकास करना।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ -

- राज्य सरकारों द्वारा इन सुधारों पर प्रभावी कार्यवाही न करना।
- ~~राज्य~~ पुलिस राज्य सूची का विषय है। राज्यों द्वारा प्रभावी सुधार न होना ही कार्यान्वयन में चुनौती है।
- कई राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग बने हैं लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं। हाल में शीना बोहरा केस में राकेश मारिया (मुंबई पुलिस कमीशनर) का स्थानांतरण सुरक्षा आयोग की सिफारिश

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के बिना कर दिया गया।

- पुलिस के राजनीतिकरण की समस्या। राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस के संवैधानिक शक्तियों को स्वतंत्र व स्वायत्त आयोगों को देने से इनकार करना।
- सुधारों के कार्यान्वयन की उपयुक्त निगरानी तंत्र का अभाव। सुधारों को लागू न करने के संबंध में कोई बाध्यात्मक अवबंध न होना।
- सर्वोच्च न्यायालय दिशानिर्देशों का पालन न करने पर कोई कार्यवाही न होना।

पुलिस सुधार हेतु इन दिशानिर्देशों को दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. What is E-Kranti? How is it an improvement over National e-Governance Plan? Discuss the challenges foreseen in the implementation of E-kranti.
ई-क्रान्ति क्या है? यह किस प्रकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना का परिष्कृत रूप है? ई-क्रान्ति के कार्यान्वयन संबंधी पूर्वानुमानित चुनौतियों की चर्चा करें।

ई-क्रांति से तात्पर्य सामाजिक सेवाओं - शिक्षा, स्वास्थ्य के मुख्य क्षेत्रों में तकनीक का प्रभावी उपयोग से है जिसके अंतर्गत टेलीमेडिसिन, टेलीएडुकेशन आदि सुविधा उपलब्ध है।

=> राष्ट्रीय ई-शासन योजना में केवल प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। इस ई-क्रांति के अंतर्गत सामाजिक सरोकारों के प्रभावी निराकरण का प्रयास किया जायेगा जिससे नागरिकों को प्रभावी सेवा सुपुर्दगी होगी।

- राष्ट्रीय ई-शासन की तुलना में ई-क्रांति एक व्यापक अवधारणा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

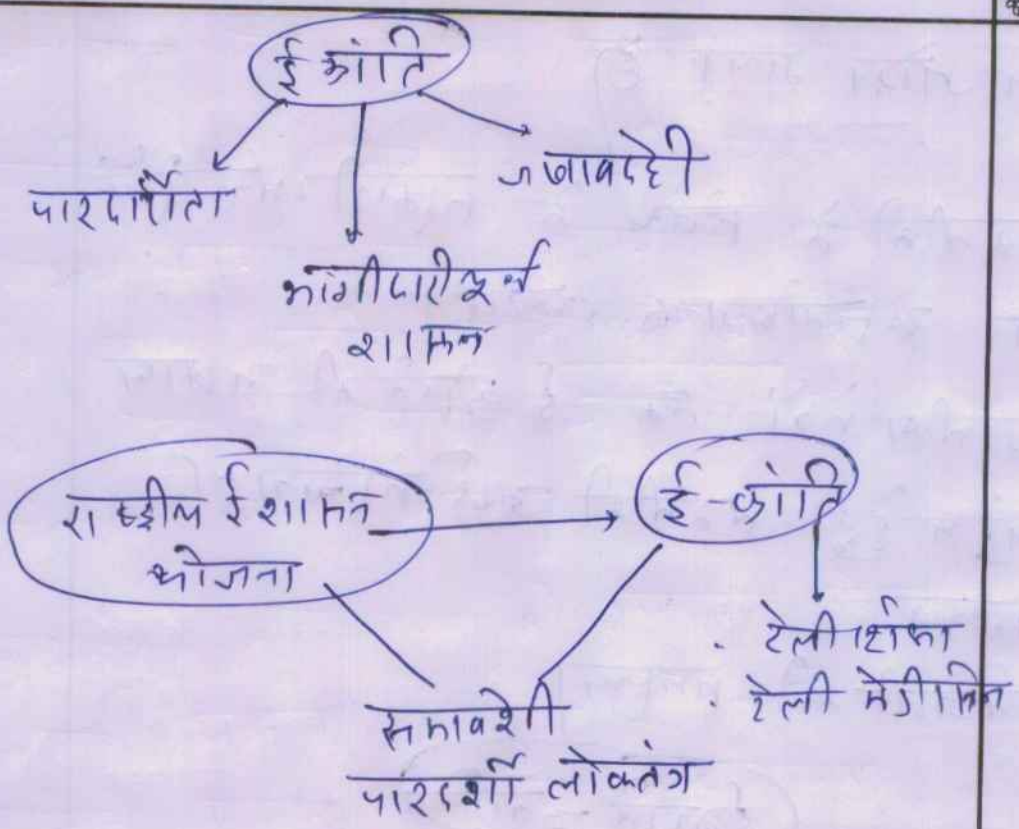

ई क्रांति हेतु कार्यान्वयन चुनौतियां:

- भारत में इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बहुत कम है।
- राष्ट्रीय मॉडल फाइबर नेटवर्क स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन न होना। जिसके 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य था। जबकि अभी तक केवल 50,000 पंचायतों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को जोड़ा गया है।

- तकनीकी के संबंध में सरकारी कर्मचारियों का असंतोषजनक व्यवहार।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक ई-क्रांति की अबाध पहुंच हेतु तकनीकी अवसंरचना का अभाव
- बिजली की समस्या।

ई-क्रांति - चुनौतियाँ

- अवधारणात्मक
  - व्यवहार संबंधी
  - अभिवृत्ति संबंधी
- संरचनागत
  - विज्ञान संबंधी
  - शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान

ई-क्रांति का प्रभावी उपयोग सशक्त व समावेशी लोकतंत्र उत्पन्न करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Some provisions of Official Secrets Act, 1923 go against the spirit of Right to Information. Explain. In this context, examine whether this necessitates repealing of the Official Secrets Act.

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कुछ प्रावधान सूचना के अधिकार की भावनाओं के विरुद्ध हैं, व्याख्या करें। इस सन्दर्भ में, इस बात की जांच करें कि क्या इसके लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है?

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 में गोपनीयता पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का मुख्य कार्य लोगों को प्रशासन की जानकारियों में हिस्सेदार न बनाना था।
जबकि सूचना का अधिकार, 2005 लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

गोपनीयता अधिनियम, 1923 — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

गोपनीयता (औपनिवेशिक) मामला

पारदर्शिता — जवाबदेही

समावेशी व भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में नागरिकों को जानकारी प्राप्त कर पारदर्शी शासन की ओर कदम बढ़ाये गये हैं तथापि, गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कुछ प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखंडता की दृष्टि से लाभप्रद है।

सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा हेतु कुछ गोपनीयता संबंधी उपबंधों को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि पारदर्शिता के साथ सरकारी तंत्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।

सरकारी कुछ योजनाएं जिनका सुरक्षा की दृष्टि से अहम स्थान है उनको सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2nd ARC व अन्य आयोग ने भी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर OSA (सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923) को बनाये रखने का सुझाव दिया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Desp te increasing awareness of beneficiaries, social audits have not played a significant role in reducing malpractices and detecting irregularities. Discuss. How can social audits be made more effective?
लाभार्थियों की बढ़ रही जागरूकता के बावजूद सामाजिक लेखांकन ने भ्रष्टाचार को घटाने तथा अनियमितताओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। चर्चा करें। सामाजिक लेखांकन को किस प्रकार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है?

सामाजिक लेखांकन से अभिप्राय किसी परियोजना के द्वारा लाभ/हानि के संबंध में की गई अंकेक्षण प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से भ्रष्टाचार धनिय अनियमितताओं का पता लगाने में सफल नहीं रही है।

कारण :

- सामाजिक लेखांकन की प्रक्रिया की कई परियोजनाओं में अनदेखी।
- सामाजिक लेखांकन के संबंध में की गई कार्यवाही की प्रभावी मॉनीटरिंग न होना।
- सामाजिक लेखांकन में स्थानीय लोगों की भागीदारी के स्थान पर बाहरी लोगों की भागीदारी का होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सामाजिक लेखांकन से पहले परियोजना का प्रारंभ हो जाना। सामाजिक लेखांकन हेतु आवश्यक जानकारी ग्राम सभा को प्रदान न किया जाना।
- ग्राम सभा की प्रभावी भागीदारी न होना।
- स्थानीय लोगों में सामाजिक लेखांकन के संबंध में जागरूकता का अभाव।
- सामाजिक लेखांकन में निर्धारित मानकों का प्रयोग न करना। सिविल सोसायटी, NGO की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित न होना।

प्रभावी बनाने के उपाय :

- सामाजिक लेखांकन के संबंध में रिपोर्टों का गहन विश्लेषण। सामाजिक लेखांकन की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की उपयुक्त जांच करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- किसी परियोजना की शुरुआत के पहले सामाजिक लेखांकन प्रक्रिया करवाना।
- ग्राम सभाओं को सामाजिक लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराना।
- इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में निगरानी हेतु उचित संस्थागत तंत्र का विकास करना।
- सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया में सिविल सोसायटी, NGO, सामाजिक समूहों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।

सामाजिक लेखांकन को प्रभावी बनाने से प्रशासनिक निर्णयों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी प्रभावपूर्ण होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Nutrition status is linked to non-nutrition factors. In light of this statement, examine why despite a fast growing economy and the largest anti-malnutrition programme, India has the world's worst level of child malnutrition. What steps has the Government taken to to tackle the malnutrition problem in India?

पोषण की दशा का सम्बन्ध गैर-पोषण कारकों से है। इस कथन के आलोक में, इस बात की परख करें कि तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था तथा सबसे बड़े कुपोषण-रोधी कार्यक्रम के बाद भी, भारत विश्व में बाल-कुपोषण के संदर्भ में निम्नतम स्तर वाले देशों में शामिल है।

पोषण की दशा कई कारकों पर निर्भर करती है। भारत में कुपोषण की समस्या विश्व की लगभग 40% है जिसके लिए संस्थागत व उपयोगात कारक हैं

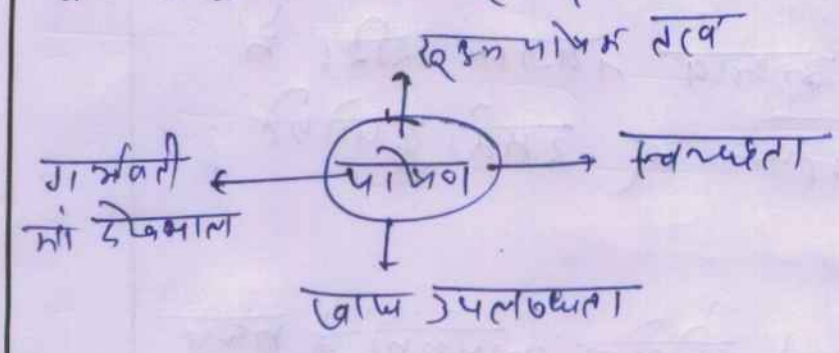

कुपोषण का सीधा संबंध सामाजिक आर्थिक कारकों से है। पितृसत्तात्मक सोच के कारण गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। (यदि गर्भ में लड़की हो तो)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- रूढ़िवादी परंपराओं / सोच के कारण गर्भवती मां को कम पोषण। अमतगांवो में यह सोच है कि कमजोर शिशु पैदा होने के प्रभाव में आसानी होती है।
- गर्भवती मां को प्रभावी पोषण का अभाव नवजात शिशु के कुपोषण का कारण बनता है।
- स्वच्छता का अभाव नवजात शिशु में बीमारियां उत्पन्न कर उसको कुपोषित करता है।
- कुपोषण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य निर्माण समन्वय का अभाव

महिला व बाल विकास मंत्रालय
बाल कुपोषण → स्वास्थ्य मंत्रालय
} समन्वय अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- कुपोषण-रोधी कार्यक्रमों की जानकारी का ग्रामीण स्तर पर अभाव।
- बच्चों का स्तनपान कराने की और महिलाओं की कम प्रवृत्ति के कारण बच्चों में स्थायी कुपोषण उत्पन्न होता है। वर्तमान वैश्वीकृत दौर में महिलाओं द्वारा शिशु के लिए बाजारीकृत दूध का प्रयोग किया जाता है।

कुपोषण कारक योजनाएं
- संस्थागत कमी
- कार्यान्वयन स्तर

- प्रभावी वित्त उपलब्धता का अभाव।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में भी 'मां व शिशु' पर विशेष ध्यान देकर कुपोषण हटाने की दिशा में प्रयास सुझाए गये हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Autonomous District Councils (ADCs) based on the Sixth Schedule of the Constitution of India are described as 'State in miniature'. Elaborate. Also, critically evaluate the functioning of ADCs over the years.

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पर आधारित स्वायत्त जिला परिषद (ए.डी.सी.) को 'लघु रूप में एक राज्य' के रूप में वर्णित किया जाता है। व्याख्या करें। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों के दौरान ए.डी.सी. की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

6वीं अनुसूची पर आधारित स्वायत्त जिला परिषद को कई संवैधानिक अधिकार दिये गये हैं। जो इसे लघु रूप में राज्य बनाता है।

- विधायी अधिकार - जनजाति उत्पादों, भूमि के हस्तांतरण में अधिकार
- न्यायिक अधिकार
- कार्यपालिका संबंधी शक्तियां
- परंपरागत रीतिरिवाजों के आधार पर प्रशासनिक गतिविधियां चलाने की स्वायत्तता
- संसाधनों पर विशेष अधिकार संबंधी उपबंध।

राज्यों की इन जिलापरिषदों के संबंध में व्यापक शक्तियां है। राष्ट्रपति को इस संबंध में विशेष शक्तियां दी गई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पिछले कई वर्षों में जिला स्वास्थ्य परिषद् के कार्यों का प्रभावी आवंटन नहीं किया गया है।

- इसके अतिरिक्त जिला परिषदों द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप निधि नहीं लिये गये हैं।
- राज्यों के कई उपबंधों तथा जिला परिषदों के निधियों के संबंध में वास्तविक अभाव।
- स्वायत्त जिला परिषदों को प्रभावी आधिकारों के आवंटन के संबंध में छिटे संघर्षों की समस्या।
- संसाधनों पर जिला परिषदों के अधिकार के संबंध में विरोधाभास की स्थिति। (नागालैंड राज्य के क्षेत्रों में सामुदायिक व्यक्तियों द्वारा संसाधनों का उपयोग, अन्वेषण करना)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार स्थापित जिला पालिकाओं व राज्यों के बीच प्रभावी परामर्श व विचार विमर्श की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक उपबंधों व सिद्धांतों का प्रभावी पालन हो सके।

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R
N 22 OCT 2016
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 843)

Name of Candidate	Shailendra Singh Indoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7447
Center	ORN	Date	22/10/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।.
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Discuss the need for adhering to the road map for fiscal consolidation by fixing the fiscal deficit. Has the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 served the purpose for which it was envisaged?

राजकोषीय घाटा के निर्धारण के माध्यम से राजकोषीय समेकन (कंसोलिडेशन) के लिए एक रोड मैप का पालन करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्या राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम, 2003 ने अपनी परिकल्पना के उद्देश्य की पूर्ति की है?

राजकोषीय घाटा से अभिप्राय सरकार द्वारा कुल देनदारी से है। राजकोषीय घाटा के प्रभावी संतुलन होने से राजकोषीय समेकन की गतिविधि सकारात्मक होती है।

- राजकोषीय घाटा के सम्बन्ध एक परास में (Range) होने की आवश्यकता है ना कि एक नंबर के रूप में इसका निश्चित मान होना चाहिए।
- क्रेडिट वृद्धि व राजकोषीय घाटा के मध्य में नकारात्मक सहसंबंध होता है जिसे ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटा को परिवर्तनशील होना चाहिए।
- राजकोषीय घाटा की प्रभावी निगरानी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित होना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चाहिए राजकोषीय घाटे के प्रभावपूर्ण व संतुलित स्तर पर बने रहना अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण / संतुलन के लिए आवश्यक है।

FRBM Act, 2003 की समीक्षा :

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ में 2009 तक राजकोषीय घाटे को 3% तथा (GDP का) राजस्व घाटे को शून्य के स्तर तक बनाये रखना था। वैश्विक मंदी व किसानों के ऋण माफी के कारण इसकी सीमा बढ़ाई गई।

वर्तमान में राजकोषीय घाटा 3.9% है जिसे 2016-17 तक 3.5% तथा 2017-18 तक 3.0% करना है।

- यद्यपि यह अधिनियम प्रभावपूर्ण नहीं रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत राजकोषीय परिषद (कार्यों की निगरानी हेतु) की स्थापना नहीं की गई।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- वैश्विक व घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित नहीं किया गया।
- इसी संदर्भ में 14वें वित्त आयोग ने एक स्वतंत्र वित्त राजकोषीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की है।
- FRBM Act में संशोधन कर राजकोषीय घाटे की रेंज (Range) निर्धारित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Public investment in railways has a multiplier effect for the larger economy. Elaborate. What factors have held back the railways despite having a separate budget and considerable resources? In this context, enumerate the relevant recommendations of Bibek Debroy committee?

रेलवे में किए गए सार्वजनिक निवेश का, वृहद् अर्थव्यवस्था के लिए गुणक (मल्टीप्लायर) प्रभाव होता है। विस्तार पूर्वक बताईए। अलग बजट और यथेष्ट संसाधनों के बावजूद कौन से कारकों ने रेलवे को पीछे रखा है? इस संदर्भ में, बिबेक देबरॉय समिति की प्रासंगिक अनुशंसाएं बताईए?

रेलवे निवेश का अर्थव्यवस्था पर गुणक रूपी प्रभाव पड़ता है।

- उद्योगों पर प्रभाव - कोयला, लोहे का आवागमन अधिकतर रेलों द्वारा होता है। रेलवे के द्वारा प्रभावपूर्ण आवागमन से इस्पात उद्योग जैसे विनिर्माण क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- खाद्य आपूर्ति की बिना बाधा के आवागमन होना।
- इसके अतिरिक्त ~~अन्य~~ कच्चे मालकी प्रभावी आपूर्ति।
- पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रेलवे के पिछड़ने के कारण -

- स्वतंत्रता के पश्चात रेल परियोजनों की संख्या में वृद्धि न होना। रेल बजट के राजनीतिकरण के कारण केवल रेलों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया गया ना कि परियोजनों की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई।
- यात्री रेलों व माल भाड़ा गाड़ियों के लिए अलग परियोजनों का न होना।
- रेलवे के कुल बजट के लिए निर्धारित राशि का केवल 5-7% ही अधिकतम खर्च किया गया है।
- रेल किराये निर्धारण के लिए रेलवे टैरिफ प्राधिकरण का गठन न किया जाना।
- रेलवे हेड कर्मचारियों के उपयोग के संबंध में निगरानी हेतु उपयुक्त कर्मचारी तंत्र का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिसके देखरेख कमेटी की सिफारिशें -

- रेलवे सुरक्षा तथा टैरिफ प्राधिकरण का गठन।
- कमजोर रूप से रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत करने को खत्म करना
- रेलवे के निजीकरण के बजाय कॉरपोरेट प्रणाली को शामिल करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. "There is a myth that small firms create the most jobs in an economy. The fact is that small firms that grow big create the jobs". In context of the Indian economy what are the factors that prevent firms that start small from growing bigger. What progress has India made in this respect and what other measures are required?

"ऐसा मिथक है कि किसी अर्थव्यवस्था में छोटी फर्में सर्वाधिक रोजगार पैदा करती हैं। जबकि तथ्य यह है कि वही छोटी फर्में जो बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होती हैं, रोजगार पैदा करती हैं"। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, छोटी फर्मों को बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होने से रोकने वाले कारक कौन-से हैं? इस संदर्भ में भारत ने क्या प्रगति की है और कौन-से अन्य उपाय आवश्यक हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था सीमित प्रवेश वाले समाजवाद से बिना नियंत्रण वाले बाजारवाद की ओर विकसित हुई है जिसके कारण फर्मों की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

बड़ी फर्मों के विकास में बाधक कारक:

प्रतिबंधात्मक श्रम विनियमों के कारण फर्में छोटे रहने हेतु बाध्य है। उदाहरण लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 100 से अधिक श्रमिकों की छंटनी हेतु सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

श्रम व औद्योगिक संबंध विषय के समवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों में अलग-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अलग कारणों से निवेशकों को नुकसान हानि वाले फर्मों के निकासन हेतु उपयुक्त संस्थागत ढांचा का अभाव।

- बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होने के कारण छोटी फर्मों को सरकार से वित्तीय सहायता मिलना बंद हो जाता है।
- 'Exit' (निकासी) संबंधी समस्या।

भारत सरकार के प्रयास -

- इसके कारणों में सुधार हेतु प्रयास। प्रोत्साहक लोगों के निर्माण की दिशा में कदम।
- ऋणशोधन व दिवालियापन कानून, 2015 हेतु ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
- हानि में चल रही फर्मों को समाप्त करने हेतु उपयुक्त संस्थागत ढांचा विकसित किया जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अन्य उपाय -

- भारतीय उद्योगों में कंपनियों के विकास को सुगम बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में निहित स्वार्थों के कारण घाटे में चल रही कंपनियों को भी बंद नहीं किया जाता है। ऐसी कठिनाइयों को दूर समाप्त करने की आवश्यकता है।
- श्रम विनियमनों को प्रतिबंधात्मक के बजाय सरल व प्रभावी बनाने की आवश्यकता जिससे वे उद्योगों के विकास में सहायक हों।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Enumerate the reasons why problem of NPAs is more pronounced in the public sector banks as compared to the private sector. Discuss the implications of having high NPAs in an economy. Also list the measures which the government has taken in order to address them.

निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एन.पी.ए. की समस्या अधिक गंभीर होने के कारण बताएं। किसी अर्थव्यवस्था में उच्च एन.पी.ए. के निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या अधिक गंभीर है।

- सार्वजनिक बैंकों के अधिक प्रभावी विलय पर ध्यान दिया गया है। कुल ऋण के 70% के अधिक भाग पर सार्वजनिक बैंकों के अंतर्गत है।
- ऋण देने हेतु सरकारी दबाव से जुड़ी गतिविधियां
- सरकारी कंपनियों हेतु ऋण देने के कारण NPA की समस्या। स्टील कंपनियों की NPA में प्रमुख भागीदार जिसके पीछे प्रमुख कारण चीन की अधिक स्टील उत्पादन क्षमता व वैश्विक मांग का कम होना है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- साधारणतः बैंकों द्वारा ऋण देने के पहले जोखिम हेतु उपयुक्त निकायों का पालन न करना।
- कई बैंकों के प्रबंध निदेशकों ने जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों में संलिप्तता।

⇒ उच्च N.P.A. के निहितार्थ:

उच्च N.P.A होने के बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकों द्वारा ऋण न देने के (क्रेडिट वृद्धि नकारात्मक होना) कंपनियों द्वारा निवेश गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

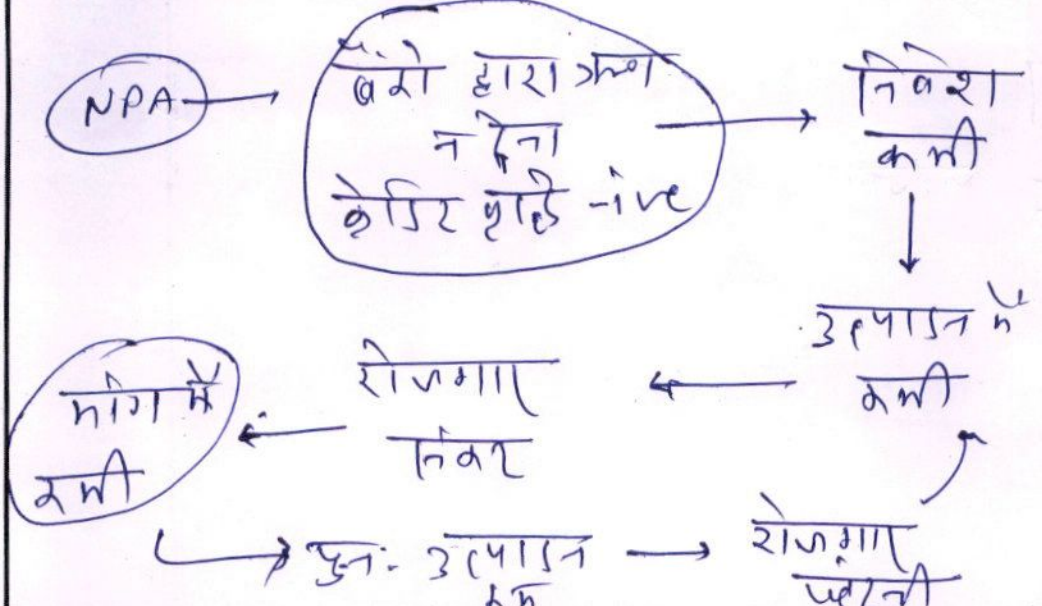

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

- NPA की जांच प्रोसेस सरल (शुरुआत में कर्ज देने- RBI द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किये गये है।
- सरफेसी अधिनियम, 2002 में सुधार हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
- Asset Reconstruction Company को प्रभावी बनाया गया।
- Debt Recovery Tribunal को प्रभावी बनाने हेतु दावों का स्थानांतरण करने का प्रयास।
- SUAI योजना

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Mention the salient features of the Hybrid Annuity Model (HAM) proposed by the government to reinvigorate private investment in infrastructure sector. How is it an improvement over the EPC model?

अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एच.ए.एम.) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कैसे यह ई.पी.सी. मॉडल से बेहतर सुधार(इम्प्रूवमेंट) है?

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नया मॉडल है

इसके अंतर्गत किसी परियोजना का वित्तपोषण हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ में 40% राशि दी जाती है तथा 60% राशि बाद में किश्तों में दी जाती है

सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस व भूमि अधिग्रहण संबंधी अनुमोदन प्रदान किया जाता है

जोखिम का संतुलित ढंग से बंटवारा किया जाता है ताकि निजी निवेशकों के निवेश पर विपरीत प्रभाव ना पड़े

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

E.P.C मॉडल (अभियांत्रिकी, अधिग्रहण, निर्माण) में निजी कंपनी कान्ट्रेक्टर की भूमिका निभाती है जिसमें इस वित्तपोषण निजी सरकार द्वारा किया जाता है तथा निजी कंपनी contractor की तरह योजना दूसरी सरकारों को सौंप देती है

वर्तमान परिदृश्य में सरकारी वित्त कमी के कारण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल उपयुक्त है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा प्रोजेक्ट का 40% वित्तपोषण किया जायेगा बाकी पैसा निजी कंपनी लगायेगी।

EPC मॉडल में Toll उगाही का कार्य सरकार द्वारा किया जायेगा जबकि HAM में टोल उगाही निजी कंपनी द्वारा की जायेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

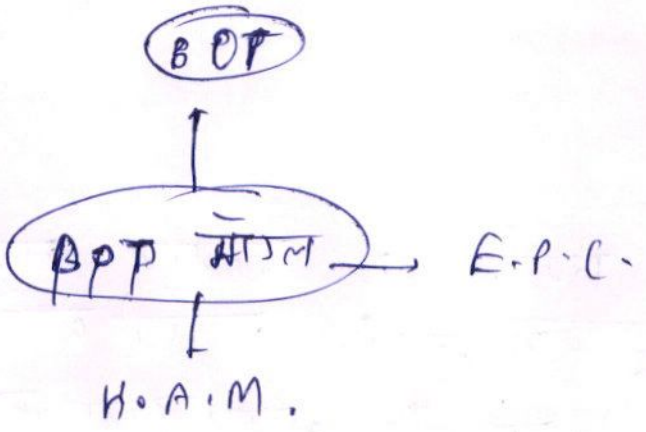

इस बार H.A.M. एक उपयुक्त मॉडल है इससे निजी क्षेत्रों की बैलेंस शीट पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा तथा निजी कंपनियों द्वारा पर्यावरण व सोशल आकलन स्वीकृति न मिलने से परियोजना के लेट होने पर NPA की समस्या उत्पन्न होती थी। इस प्रकार की समस्या से भी छुटकारा मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Even within the multilateral format of WTO the FTA route has served India well. Comment. How can India effectively deal with the challenges posed by the new mega regional agreements such as TPP?

यहां तक कि डब्लू.टी.ओ. के बहुपक्षीय प्रारूप (multilateral format) के अंतर्गत भी भारत को एफ.टी.ए. मार्ग (FTA route) का अच्छा साथ मिला है। टिप्पणी कीजिए। भारत टी.पी.पी. जैसे नये मेगा क्षेत्रीय समझौतों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों मे किस प्रकार प्रभावी ढंग से निपट सकता है?

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत द्वारा बहुपक्षीय प्रारूप का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। भारत द्वारा कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किये गये हैं।

इस संबंध में भारत-आसियान FTA तथा दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण है।

तथापि भारत को FTA के द्वारा आयात की तुलना में निर्यात अपेक्षाकृत कम हुआ है इसके अतिरिक्त कई देशों के साथ मात्र वाद क्षेत्र में FTA के कारण भारत अपने कॉस्टवेयर व अन्य सेवा क्षेत्रों पर प्रभावी उपयोग नहीं कर पाया है।

भारत द्वारा FTA के अंतर्गत mode-4

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सेवाओं (श्रमिकों का अस्थायी आवागमन) का प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है।

यद्यपि FTA के कारण भारत की वैश्विक GDP में भूमिका 2001-07 के 4.8% से बढ़कर 2008-13 में 6.1% हो गई है।

=) यद्यपि WTO (विश्व व्यापार संगठन) जैसे बहुआयामी संगठन में कई अनसुलझे वार्ताओं (दोहा वार्ता) के कारण ~~भारत~~ अमेरिका ऐसे प्रादेशिक संगठन बनाने की ओर उन्मुख हुए हैं। इन संगठनों में/करारों में नये मुद्दे भी शामिल किये गये हैं।

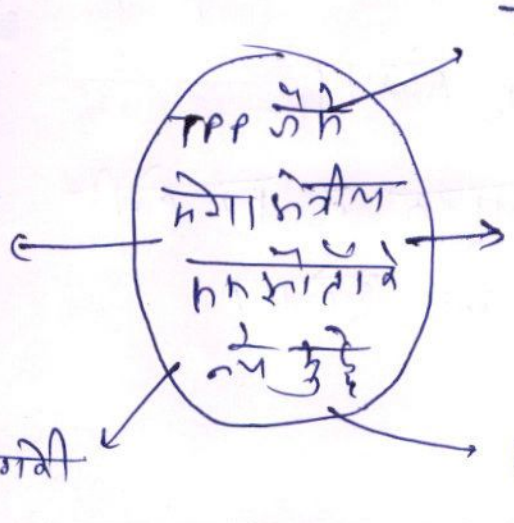

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत इन क्षेत्रीय समझौतों के आधार समर्थक हो नहीं रह सकता क्योंकि बाद में इन समझौतों के नियमों के निर्धारण में भारत की कोई भूमिका नहीं होगी। उसे केवल नियमों का पालन करना होगा।

भारत को अपनी परिस्थिति, मांग को ध्यान में रखते हुए नये मेगा क्षेत्रीय समझौतों का हिस्सा बनने का प्रयास करना होगा। जैसे- RCEP.

भारत को FTA प्रणाली को अन्य देशों, लेकिन अमेरिकी देश जो TPP में शामिल है, के साथ लागू करना होगा।

FTA को अधिक व्यापक व समावेशी बनाने का प्रयास करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Cashless economy is a global trend now. What are the challenges of achieving a cashless economy in the case of India? How can these challenges be overcome?

नकदीरहित (कैशलेस) अर्थव्यवस्था अब वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है। भारत के प्रकरण में नकदीरहित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

कैशलेस अर्थव्यवस्था से आशय वित्तीय गतिविधियों में नकद के बजाय मूल्य ट्रांजिशन गतिविधियों के प्रयोग से है।

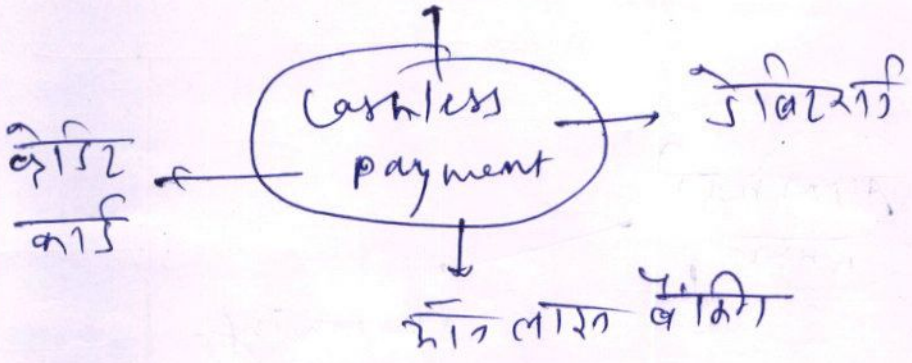

भारत के संदर्भ में कैशलेस अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद है।

बैंकों के सुरक्षा मानकों के संबंध में प्रभावशील तंत्र न होना। सुरक्षा तंत्र के प्रभावी न होने के कारण हाल में 3.4 मिलियन कार्डों के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संबंध में धोखाधड़ी मामलों का पता चला है।

- वित्तीय समावेशन की समस्या ग्रामों में बैंकिंग शाखाओं की कमी।
- PM जनधन योजना के अंतर्गत खोले गये खातों में दुरुपयोगों का प्रयोग न किया जाना।

ATM संबंधी समस्या
- Skimming
- Card swapping
- Enter Key Block

- वित्तीय तंत्र के संबंध में ग्राहकों में जागरूकता का अभाव।
- बैंकों में सरल ऋण विशेषज्ञों की अनुपलब्धता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान :

बैंकों द्वारा ग्राहकों को समय समय पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करना।

बैंकों द्वारा प्रभावी डाटा सुरक्षा तंत्र का विकास करना।

RBI द्वारा बैंकिंग प्रतिभूति पर स्थानीय हुए कार्यरत लघु बैंकों व पेमेंट बैंकों को लाइसेंस जारी करना।

बैंकों में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की उपस्थिति।

भारतीय बैंकों द्वारा वैश्विक बैंकों के साथ मिलकर उपयुक्त डाटा सुरक्षा विनियामकों का विकास करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Abysmal level of formally skilled workers in Indian economy, as indicated by the Labour Bureau Report 2014, is a cause of concern. What are the factors responsible for such a scenario? Also, examine the measures taken by the government in recent years to address the relevant concerns.

श्रम ब्यूरो रिपोर्ट 2014 द्वारा यथा इंगित, भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अति निम्न (Abysmal) स्तर, चिंता का कारण है। ऐसे परिदृश्य के लिए उत्तरदायी कारक कौन-से हैं? साथ ही, प्रासंगिक चिंताओं को दूर करने हेतु हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए।

श्रम ब्यूरो रिपोर्ट के ~~अनुसार~~ अनुसार भारत की 90% से अधिक आबादी अकुशल है। जबकि ~~दक्षिण कोरिया~~ में 96%, कोरिया में लगभग 80% आबादी कुशल है।

उत्तरदायी कारण :

- भारत में कौशल विकास हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव।
- भारत में मांग द्वारित कौशल पर ध्यान देने के बजाय आपूर्ति द्वारित कौशल को मांग के अनुरूप कौशल न देना।
- कौशल संस्थानों का अभाव।
- भविष्य के अनुरूप अनुकूल प्रौद्योगिकी के बजाय वर्तमान तकनीकी में कौशल देना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिसके वर्तमान तकनीक कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएगी।

उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा 2022 तक 50 करोड़ व्यक्तियों का कौशल विकास किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश व बिहार में कौशल बैंकों की स्थापना की जाएगी। जिसके द्वारा मांग प्रेरित कौशल प्रदान किया जाएगा।

प्रोटोकॉल आधार पर कौशल विकास किया जायेगा। इस क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं को देखते हुए कौशल विकास हेतु गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समीक्षा :

- क्षमता द्वारा किये गये कार्यों की निगरानी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- कौशल विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी-रोबोटिक्स, जैसे तकनीकी को ध्यान में रखना चाहिए।
- वैश्विक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास की आवश्यकता है। जैसे- जापान में वृद्ध आबादी के बढ़ने से हेल्थकेयर व नर्स रोजगार की संभावना के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास करना आवश्यक है।

जनसांख्यिकीय लाभांश → कौशल विकास → रोजगार → अर्थव्यवस्था सुधार

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. In the 10 years of its existence MGNREGA has won laurels as well as attracted criticism. Comment. What changes are required for the scheme to be relevant in the current scenario.

अपने अस्तित्व के 10 वर्षों में मनरेगा ने ख्याति अर्जन के साथ ही आलोचनाएं भी झेली है। टिप्पणी कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में योजना को प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से परिवर्तनों की आवश्यकता है?

मनरेगा कार्यक्रम 2005 में लोकहित के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण वयस्क सदस्यों को कुशल रोजगार (न्यूनतम 100 दिन) प्रदान करना था।

मनरेगा के द्वारा ग्रामीण प्रवास में कमी आई।

फलतः मांग में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

100 दिन निश्चित रोजगार के साथ कृषि संबंधी सेवाओं में 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया।

महिलाओं की प्रभावी भागीदारी (50% से ज्यादा) से आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं की पकड़ मजबूत हुई। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हुआ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मनरेगा के अंतर्गत पर्यावरणीय कुछ संबंधी तथा कृषिगत कार्य हुए।

आलोचना

मनरेगा द्वारा 100 दिन निश्चित कार्य देने से कृषि हेतु मजदूरों की लागत में वृद्धि होने से किसानों को नुकसान हुआ।

ग्रामीण आय बढ़ने से मुद्रास्फीति की समस्या

मनरेगा द्वारा पारदर्शिता निर्धारण न किया जाना। फर्जी दस्तखतों द्वारा लीकेज की समस्या।

मनरेगा के अंतर्गत कई गांवों में ऐसे मामले सामने आये जहां सरपंच द्वारा बिना काम किये हुए कुछ धन अपने पास रखा अन्य धन को साथियों में बंटवारा किया गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पोर्टलों की आवश्यकता :

- मनरेगा की आधार कार्ड के साथ सेवाओं द्वारा प्रभावी बनाने की आवश्यकता।
- उपयुक्त सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था करना।
- प्रबंधन सूचना तंत्र को प्रभावपूर्ण व संस्थागत रूप से लागू करना।
- दूरस्थ क्षेत्रों में मनरेगा दिवसों की वृद्धि करना।
- मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान देना तथा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उपशमन व अनुकूलन गतिविधियों पर बल देना।
- ग्राम सभा को मनरेगा की उपयुक्त निगरानी हेतु संस्थागत रूप से सशक्त उपलब्ध कराना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Power sector reforms, crucial as they are, have remained elusive. Discuss the reasons for their failure. How far can the UDAY scheme address the issues concerning DISCOMS and improve the entire power sector value chain?

बिजली क्षेत्र में सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद दुष्प्राप्य बने हुए हैं। इनकी विफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। उदय (UDAY) योजना डिस्कॉम (DISCOMS) से संबंधित समस्याओं को किस सीमा तक समाधान कर सकती है और समस्त विद्युत क्षेत्रक मूल्य श्रृंखला(power sector value chain) में कैसे सुधार ला सकती है?

बिजली क्षेत्र के कई समस्याओं के कारण यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान नहीं दे रहा है

~~समस्याएं~~ / विफलता के कारण :

- राज्य बिजली बोर्डों के पास संसाधनों का अभाव
- बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का नुकसान में लगातार बने रहना।
- बिजली टैरिफों के प्रतिस्पर्धात न होने के कारण बिजली कंपनियों का लगातार नुकसान
- पारेषण व वितरण नुकसान (ATAC loss)
- विभिन्न समितियों - शुंगलू कमेटी की रिपोर्टों को प्रभावी ढंग से लागू करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उदय योजना द्वारा डिस्काम (वितरण कंपनियों) के नुकसान को राज्यों द्वारा प्राप्त किया जायेगा। बांड जारी करके राज्यों द्वारा उनके नुकसान की भरपाई मानेगा प्रदान किया जायेगा।

- डिस्काम के नुकसान को समाप्त करना।

वर्तमान में डिस्काम वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण बिजली नहीं खरीद रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

बिजली निर्माण कंपनी → DISCOM → उपभोक्ता

विद्युत क्षेत्र में दुर्बला

- DISCOM के नुकसान से पूरी मूल्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- उपयोजना विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता सुधार, उपभोक्ता व निगमों की समस्याओं का समाधान करेगी।
- निगमों द्वारा बिजली खरीद से उपभोक्ता को उपभी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- सरकारी बॉड मार्केटिंग विकास होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Market volatility and vulnerability to weather are the major issues facing Indian agriculture. Elaborate. In this regard, critically examine the importance of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana vis-a-vis earlier insurance schemes in addressing the problems of Indian agriculture.

बाजार की अस्थिरता और मौसम के प्रति सुभेद्यता (vulnerability to weather) भारतीय कृषि के समक्ष बड़ी समस्याएं हैं। वर्णन कीजिए। इस संबंध में भारतीय कृषि की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में पूर्व की बीमा योजनाओं की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या घरेलू व वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव तथा परिवर्तनशील मौसमी स्थिति है।

कृषि

बाजार की अस्थिरता
↓
- वैश्विक बाजार में मांग में परिवर्तन
- घरेलू मांग
- भारतीय बाजार की वैश्विक बाजार से संबद्धता का प्रभाव

मौसम परिवर्तन
↓
जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के कारण कृषि पर विपरीत प्रभाव
↓
- उष्ण लहर की आवृत्ति में वृद्धि
- लगातार 2 वर्षों तक सूखे की समस्या

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभाव :

- अन्य योजनाओं की तुलना में इसके अंतर्गत रबी व खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम निर्धारित किया गया है। किसानों को हानि की स्थिति में पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- फसल नुकसान हेतु खेत को मानक इकाई के रूप में माना गया है।
- प्राकृतिक घटनाओं द्वारा नुकसान के साथ फसलेत्तर (फसल कटाई पश्चात) नुकसान पर भी ध्यान दिया गया है।
- खेतों की उपयुक्त निगरानी व हानि की जांच हेतु तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया गया है। किसानों द्वारा खेत की तस्वीर भेजकर हानि का आकलन किया जा सकेगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- बीमा कंपनियों को अन्तरराज्यी बनाने हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित किया गया है।
- किसानों को हुई हानि की क्षति भरपाई हेतु प्रीमियम सरल व त्वरित बनाया गया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) is a step forward from the New Exploration Licensing Policy (NELP). Compare the two policies and elaborate how HELP can encourage investment in the hydrocarbon sector as well as curtail India's export dependence?

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन (अन्वेषण) लाइसेंसिंग पॉलिसी (नीति) [HELP], न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) से एक कदम आगे है। दोनों नीतियों की तुलना कीजिए और वर्णन कीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में HELP किस प्रकार सहायता प्रदान सकता है?

HELP नीति में प्रभावी परिशोधन कर इसे व्यापक बनाने हेतु HELP नीति प्रस्तुत की गई है।

- HELP में तेल, गैस, कोल के लिए अलग-अलग लाइसेंस के स्थान पर दो ब्लॉक के लिए एक ही लाइसेंस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
- Production sharing model को अपनाया गया है।
- नीलामी की उपयुक्त व्यवस्था।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- HELP नीति में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एकल लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई है। इससे ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया को बल मिलेगा।
- भारत के शेल गैस, हाइड्रोकार्बन खोज होने के साथ आयात पर निर्भरता घटेगी। क्योंकि HELP व्यवस्था से निजी निवेश आकर्षित होंगे तथा अन्वेषण प्रक्रियाओं को बल मिलेगा।
- निजी कंपनियों द्वारा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। निजी कंपनियों द्वारा प्रभावी अन्वेषण हाइड्रोकार्बन विकास/खोज में सहायता करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Although equal land ownership rights are essential for the economic empowerment of women, these rights are often overlooked. Discuss. What steps have been taken by the government to ensure land rights for women?

यद्यपि समान भूमि स्वामित्व अधिकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं परन्तु इन अधिकारों की प्राय: अनदेखी की जाती रही है। चर्चा कीजिए। महिलाओं के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

समान भूमि स्वामित्व अधिकार महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है। महिलाओं को भूमि स्वामित्व अधिकार देने से उनकी आर्थिक स्वायत्तता पहल सुनिश्चित होगी।

भूमि स्वामित्व अधिकार
↓
आर्थिक स्वायत्त
↓
समाज के कार्यों - शिक्षा, बचत पर खर्च
↓
महिला सशक्तिकरण

परंतु ग्रामीण स्तर पर पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिये जाते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार द्वारा किये गये प्रयास :

- सरकार द्वारा कृषि स्वामित्व महिलाओं के नाम पर हस्तांतरित करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम पर बनाये जाने का प्रावधान है।
- उत्तराधिकार कानून में 2005 में संशोधन कर महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार दिये गये हैं।
- महिलाओं के नाम पर कृषि पट्टे को देने का प्रावधान।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Micro irrigation methods would not only lead to increased productivity but also conservation of water. Enumerating the different methods of micro irrigation, identify the bottlenecks in their implementation and benefits that can acrue once they are implemented.

सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि जल संरक्षण भी होगा। सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों को गिनाते हुए उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं उनके कार्यान्वयन से प्राप्त हो सकने वाले लाभों की पहचान कीजिए।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि व जल संरक्षण सुनिश्चित होगा।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति :

- ड्रिप सिंचाई
- स्प्रिंकलर सिंचाई

कार्यान्वयन में बाधा :

- ~~प्रा~~ प्रारंभिक लागत अधिक होने के कारण किसानों द्वारा न अपनाना।
- सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए priority sector lending के तहत ऋण न देने का प्रावधान जिससे इन पद्धतियों को अपनाने हेतु वित्त का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किसानों के बीच इन पद्धतियों के प्रति कम जागरूकता।

इन पद्धतियों को बढ़ाने हेतु उपयुक्त तकनीकी का अभाव

लाभ :

ड्रिप सिंचाई पद्धति से जल सिंचाई के मौजूदा बाढ़ पद्धति (flood technique) द्वारा होने वाली जलकी बर्बादी रुकेगी।

सतही सिंचाई द्वारा होने वाली क्षारीयता, जलप्लावन (water logging) की समस्या से निजात मिलेगी।

फसलों हेतु अनुकूलतम जल देने से उनकी पोषण क्षमताएँ वृद्धि होगी तथा उत्पादकता में सुधार होगा।

उर्वरकों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित होगा। अन्यथा बिना ड्रिप सिंचाई के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों की पानी के साथ बर्बादी हो जाती है।

उर्वरकों के व्यर्थ जल के साथ न बहने से यूट्रोफिकेशन की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

जल का अनुकूलतम प्रयोग से फसलों द्वारा उर्वरकों का प्रभावी अवशोषण होगा जिससे मृदा की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. It has been argued that the Nutrient based subsidy (NBS) scheme launched in 2010 has created more problems than it intended to solve. Examine. What measures are required to address concerns arising out of the fertilizer subsidy policy in India?

ऐसी दलीलें दी जाती रही हैं कि वर्ष 2010 में आरंभ की गई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एन.बी.एस.) योजना ने समस्याओं के समाधान के बजाए कहीं अधिक समस्यायें उत्पन्न की हैं। परीक्षण कीजिए। भारत में उर्वरक सब्सिडी नीति से उत्पन्न चिन्ताओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है?

पोषण आधारित सब्सिडी के अंतर्गत पोषक तत्वों के आधार पर (N, P, K) सब्सिडी दी जाती है। यद्यपि इस योजना की कई आधारों पर आलोचना की जाती है।

NBS के अंतर्गत यूरिया को शामिल नहीं किया गया। जबकि वर्तमान में अधिकतर सब्सिडी यूरिया पर दी जाती है।

यूरिया पर सब्सिडी देने के कारण N:P:K में असंतुलन की स्थिति से मृदा उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यूरिया को NBS प्रणाली से बाहर रखने के कारण यूरिया फर्मों की दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि यूरिया पर सब्सिडी पोषकतत्वों की मात्रा के बजाय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उत्पादन लागत के आधार पर दी जाती है। जिससे अकुशल व अदक्ष कर्मों को आय के साधनों की प्राप्ति होती है।

सर्वेक्षण नीति से संबंधित उपाय :
वर्तमान में सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं नीम कोटेड यूरिया के द्वारा यूरिया का केवल कृषि कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा चौथी मृदा के संबंध में जानकारी देगा।

सरकार के अन्य उपाय :
वर्तमान में Cannelization की समस्या है। यातायात के लिए मात्र 3 कर्मों को अनुमति दी गई है तथा उनकी कुल यातायात मात्रा, दूरवर्ती को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- शारदा को NBJ प्रणाली के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।
- शारदा के कस्टे होने के कारण विदेशों (बांग्लादेश, नेपाल) में इसका निर्यात किया जाता है। इसे रोकने हेतु उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- शांता कुमार कमेटी के सिफारिशों के अनुरूप उर्वरकों पर सब्सिडी को सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है जिससे लीकेज की समस्या कम हो।
- उर्वरक कंपनियों के 'exit' नीति के जुड़ी समस्याओं का प्रभावी उपाय करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. The success of "Operation Flood" proves that thoughtful intervention in the livestock sector has the potential of acting as a growth engine for the agriculture sector and rural economy. In light of this, examine the potential of the livestock sector and the challenges it faces. Also enumerate the steps taken by the government in recent years to leverage the potential of this sector.

"ऑपरेशन फ्लड" की सफलता से सिद्ध होता है कि पशुधन क्षेत्रक (लाइवस्टॉक सेक्टर) के लिए उठाए जाने वाले विचारशील कदमों में कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु विकास इंजन के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इस तथ्य के आलोक में, पशुधन क्षेत्रक की क्षमताओं एवं उसके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, सरकार द्वारा हाल के वर्षों में इस क्षेत्रक की क्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों को गिनाइए।

पशु क्षेत्र कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक विकास इंजन है। पशुधन प्राकृतिक आपदा व फसल नुकसान के समय प्राकृतिक बीमा के रूप में कार्य करते हैं।

पशुधन पर स्वामित्व फसल स्वामित्व (भूमि स्वामित्व) की तुलना में अधिक समावेशी है। 70% पशुधन पर स्वामित्व 67% लघु व सीमांत कृषकों का है।

पशुधन के साथ भेड़, बकरी के रूप में किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है तथा फसल नुकसान के समय उन पर कम विपरीत प्रभाव पड़ता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पशुधन द्वारा क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। उन क्षेत्रों में सूखे का असर कम दृष्टिगत होता है जहां किसानों के पास पशुधन के रूप में अतिरिक्त आय का स्रोत होता है।

- पशुधन द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती :

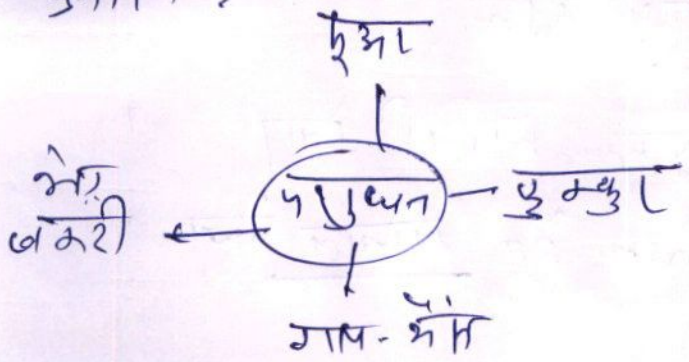

कुक्कुट / मुर्गा : . सस्ते की कम उपलब्धता
. एविएन (बर्ड फ्लू) का खतरा

गाय-भैंस - . पशुओं हेतु चारे की कम उपलब्धता

फसल क्षेत्र के बढ़ने के कारण चारा भूमि कंकालमय होती जा रही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पशुओं के बीमारी निदान हेतु पशु चिकित्सालयों की कमी।
- पशु टीकों का अभाव
- पशु चिकित्सालयों की कम संख्या जिसके कारण पशु उत्पादों की उपयुक्त जानकारी नहीं।

समाधान उठाये गये कदम :

- पशुपालकों को उपयुक्त कार्यशैली देना।
- देशी नस्लों के विकास हेतु गोपाल योजना प्रारंभ करना।
- राष्ट्रीय डेयरी मिशन की स्थापना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What are the twin objectives of government food procurement policy in India? Discuss the instruments of this policy. Do you think there is an urgent need for rationalization of MSP policy in India?

भारत में सरकारी खाद्य खरीद (अधिप्राप्ति) नीति के दोहरे उद्देश्य क्या हैं? इस नीति के साधनों पर चर्चा कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नीति को तत्काल युक्तिसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है?

भारत में सरकारी खाद्य खरीद एक प्रमुख नीतिगत कार्य है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं

- गरीबों / वंचित वर्गों को कम दरों पर खाद्य उपलब्ध कराना
- किसानों को बाजार मंदी के समय उनकी फसल खरीद हेतु MSP के रूप में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना।

=> गरीबों / कम आय वर्गों को कम दरों पर खाद्य उपलब्ध कराने का कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली (PDS) द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना भी शामिल है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अंतर्गत सरकार द्वारा 24 फसलों की खरीद हेतु केन्द्रागत तंत्र उपलब्ध है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में MSP नीति को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

MSP के कारण :

वर्तमान में MSP नीति के गेहूं-चावल के पक्ष में होने के कारण दलहन फसलों को नुकसान उठाना पड़ता है। MSP नीति में सामाजिक व पर्यावरणीय लाभ को भी समाहित करने की आवश्यकता है।

- MSP के उत्तरोत्तर पंजाब, हरियाणा राज्यों में अधिक प्रभावी होने के कारण पूर्वी राज्यों (बिहार, उड़ीसा, झारखंड) तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- MSP के संबंध में किसानों में जागरूकता का अभाव।
- MSP के अंतर्गत जायदादी चीजों का कार्यान्वयन खाद्य निगम द्वारा किया जाता है इस निगम के कार्यों पर उपयुक्त केन्द्रागत निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है
- MSP को दलहन फसलों के लिए आधार प्रभावी बनाने के कृषि उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- MSP के अंतर्गत खरीदारी बड़े किसानों से ही जाती है इस नीति का लाभ लघु व सीमांत कृषकों को नहीं मिलता है क्योंकि उनके द्वारा उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिए ही होता है। जबकि MSP पर बढ़ाने से खाद्य मुद्रास्फीति का लघु, सीमांत किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार MSP को तत्काल समेकित नीति बनाने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Discuss the potential of Food Processing Industry with regards to employment generation in India. What are the key impediments which need to be overcome before the sector can become internationally competitive and achieve high growth?

भारत में रोजगार सृजन करने के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। वे प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं जिन्हें इस क्षेत्रक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उच्च विकास प्राप्त करने हेतु दूर किए जाने की आवश्यकता है?

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रभावी बनाने हेतु तथा रोजगार वृद्धि हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। घरेलू व वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण का वर्तमान निचला स्तर है जिसे बढ़ाने हेतु रोजगार की आवश्यकता।

महिला कार्मिकों के बढ़ने से 'Ready to cook food' की बढ़ती मांग, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना बढ़ती है।

कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण खाद्य का काफी नुकसान होता है जिसे कम करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होने से रोजगार बढ़ेगा जिससे ग्रामीण प्रवासन की मात्रा भी कम होगी।

- प्रमुख बाधाएं - निम्न बाधाओं के होने से यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा -

1) अवसंरचना समस्या - कोल्ड स्टोरेज, भंडारण का अभाव। वर्तमान में 80% से अधिक का अभाव है। तथा इनमें से 70% से अधिक का प्रयोग आलू प्याज के भंडारण में किया जाता है।

- सड़क, रेल नेटवर्क का अभाव

2) खाद्य प्रसंस्करण नीति का अभाव - खाद्य राष्ट्रीय मुद्दा है उपयुक्त विनियमनों का अभाव तथा उनके बीच राज्यगत विषमता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्त उपलब्धता की समस्या

4) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपयुक्त अनुसंधान विकास (R&D) का अभाव

- स्वदेशी तकनीक का प्रभावी न होना।
- सरकारी/संस्थागत का प्रभावी उपयोग न हो पाने के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

5)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Mixed farming for the resource poor farmer is mostly a poverty induced option. Comment. What role can the government play to help farmers realise the potential from mixed farming.

संसाधनहीन निर्धन किसानों के लिए मिश्रित कृषि मुख्य रूप से निर्धनता प्रेरित विकल्प है। टिप्पणी कीजिए। मिश्रित कृषि की संभावनाओं को साकार करने हेतु, सरकार किसानों का सहयोग करने में क्या भूमिका निभा सकती है ?

मिश्रित कृषि से आमतौर पर फसल व पशुपालन से है। निर्धन किसानों के पास उपयुक्त संसाधनों के अभाव के कारण उनके द्वारा फसलों का उत्पादन व पशुपालन साथ-साथ किया जाता है।

निर्धन किसानों द्वारा फसलों हेतु उर्वरक आपूर्ति पशु अपशिष्ट गोबर आदि के द्वारा की जाती है।

पशु फसल आपदा के समय प्राकृतिक बीमा के रूप में भी कार्य करते हैं जिससे किसानों को सूखे के समय कम हानि का सामना करना पड़ता है।

गरीब किसानों द्वारा मिश्रित कृषि निर्धनता प्रेरित है क्योंकि उनके फसल उत्पादन हेतु उर्वरक, सिंचाई, बीजों की खरीद हेतु

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उनके पास वित्त का अभाव है।

- पशुओं के माध्यम से निर्धन किसानों की खाद्य उपभोग - दूध, अंडा आवश्यकताएँ भी पूरी होती हैं।

किसिद्धुधे का वास्तविक कार्यक्षमता को गरीब किसानों द्वारा नहीं पहचाना जाता है। इस संबंध में सरकार एक उपयुक्त भूमिका निभा सकती है।

- सरकार द्वारा गरीब किसानों में कृषित कृषि के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- किसानों को तकनीकी देना फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। किसानों से वित्त उपलब्ध करवाना पशुधन विकास करना।
- किसानों को आधुनिक पशुपालन गतिविधियों के संबंध में जानकारी देना।
- पशुओं के इलाज। चिकित्सा हेतु पशु

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लिमिटेड कालों की गांव में स्थापना करना तथा गरीब किसानों की इन लिमिटेड कालों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना।

गरीब किसानों को पशु उत्पाद बेचने हेतु उपयुक्त विपणन तंत्र सुलभ कराना।

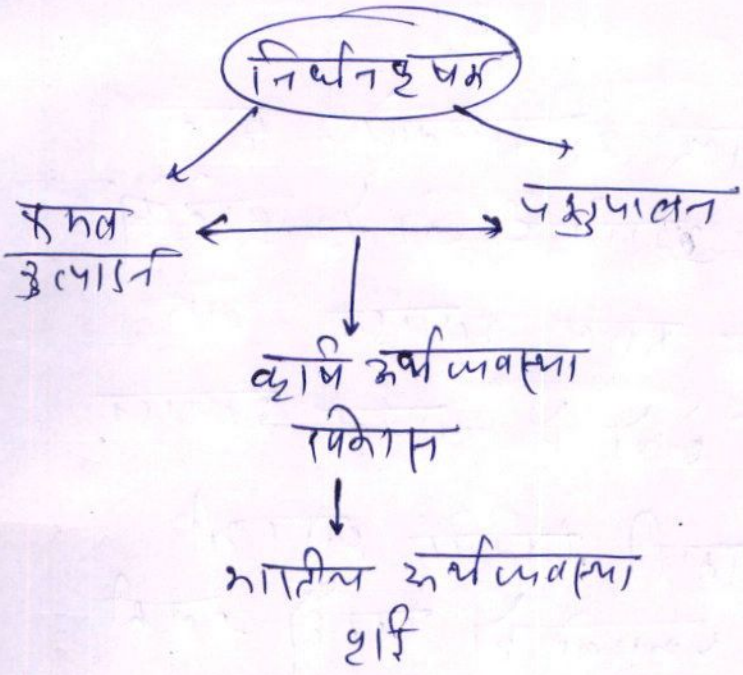

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What do you understand by cropping pattern? What are the factors that influence the cropping pattern in India? Is there a need to change the cropping pattern in the country keeping the agro-ecological concerns in mind?

फसल प्रतिरूप (क्रॉपिंग पैटर्न) से आप क्या समझते हैं? भारत में फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कृषि-पारिस्थितिकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए क्या देश में फसल प्रतिरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है?

फसल प्रतिरूप से तात्पर्य किसी क्षेत्र में बोये गये फसल से है। भारत में फसल प्रतिरूप कई कारकों से प्रभावित होता है-

- कृषकों की घरेलू आवश्यकताएँ- कृषक सामान्यतः वही उगाते हैं जो वे खाते हैं
- मृदा के अनुरूप फसल उत्पादन - जैसे तराई व डेल्टाई क्षेत्रों में चावल उत्पादन.
- वर्तमान में सरकारी नीतियों द्वारा भी फसल प्रतिरूप प्रभावित हो रहा है जलकी कमी वाले क्षेत्रों में भी जलग्रहण फसलों (चावल, गन्ना) बोया जा रहा है क्योंकि इनकी खरीद हेतु MSP तंत्र उपलब्ध है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी फसल प्रतिरूप निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए बड़े किसानों द्वारा देश के बाजार हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है जबकि लघु व सीमांत कृषक उपभोग हेतु उत्पादन करते हैं।
- फिनांस की आवश्यकता के अनुरूप - फिनांस संसाधनों की उपलब्धता फसल प्रतिरूप को प्रभावित करती है। वर्षाधीन क्षेत्रों में फिनांस उपलब्ध न होने के कारण मोटे अनाज बोये जाते हैं।
- सरकार द्वारा तकनीकी की पहुंच कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इसके अनुरूप फसल प्रतिरूप निर्धारित होता है।
- जलवायु / प्राकृतिक स्थितियों के अनुरूप - जिसमें तापमान, वर्षण प्रमुख है। जिसके द्वारा फसल प्रतिरूप निर्धारित होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

=) वर्तमान में देश में फसल प्रतिरूप को कृषि-पारिस्थितिकी के अनुरूप अपनाना चाहिए।

- महाराष्ट्र, विदर्भ जैसे जल विहीन क्षेत्रों में जलगहन- गन्ना, कपास फसलों की खेती नहीं करनी चाहिए।
- सरकारी MSP प्रणाली को दलहन के पक्ष में शिफ्ट करने की आवश्यकता है।
- फसल प्रतिरूप का निर्धारण मानसूनी जलवायु व सिंचाई व्यवस्था को देखते हुए करना चाहिए।

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
RN 23 OCT 2016
SUBMITTED IN 3 HOURS

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 844)

Name of Candidate	Shailendra Singh Endoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	23/10/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. It has been assessed that radicalisation is a security threat to India. Explain the basis of such an assessment with examples. What are the key pillars of the counter radicalisation strategy of the government?

प्रायः यह आकलित किया जाता है कि कट्टरता (रेडिक्लाईजेशन) भारत के लिए एक सुरक्षा संबंधी खतरा है। इस तरह के आकलन के मूलाधारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कट्टरता से निपटने के लिए सरकार की रणनीति के प्रमुख आधार स्तंभ क्या हैं?

कट्टरता भारत के लिए सुरक्षा संबंधी प्रमुख खतरा है। भारत की जनसांख्यिकी व सामाजिक-आर्थिक स्थिति द्वारा यह प्रतिबिम्बित होते है।

- कट्टर संगठनो द्वारा जैसे ISIS 90% भर्तियां online की जाती है। भारत की अधिकतर युवा आबादी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है जिससे उनका खतरा बढ़ जाता है।
- भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी विशेष रूप से कट्टर विचारों के प्रति सुभेद्य है।
- भारत की रणनीतिक भूस्थिति। सीमापार क्षेत्रों द्वारा कट्टरवादी विचारों का प्रसार
- बैंगलोर, हैदराबाद में टियर स्काउट के जरिये युवाओं को कट्टरवादी विचारधारा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के प्रति प्रेरित करना।

- भारत में साइबर सुरक्षा तंत्र की प्रभावी मानकों की अनुपस्थिति। विभिन्न एजेंसियों (कुशल व जांच) के बीच समन्वय की अनुपस्थिति के कारण कुशल का खतरा और बढ़ जाता है।
- युवाओं में बेरोजगारी व अन्य कारणों से सरकार के प्रति रोष भावना की उपस्थिति जिसका कट्टरपंथी संगठनों द्वारा लाभ उठाया जाता है।

सरकार की रणनीति :

- युवाओं में जागरूकता पैदा करना। इन विचारधाराओं से प्रेरित युवाओं पर नजर रखना तथा उन्हें दण्डात्मक प्रणाली के बजाय सुधारात्मक प्रणाली द्वारा कट्टरपंथी विचारों से दूर ले जाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करना।

इस संदर्भ में तेलंगाना की प्रतिउग्रवाद नीति (de radicalization Policy) एक प्रमुख पहल है। इसी प्रकार एक राष्ट्रीय उग्रवाद विरोधी नीति बनाने की आवश्यकता है।

फाइनल सारांश की उपयुक्त निगरानी करना क्योंकि कट्टरता वाले विचारों का प्रसार इन सारांश द्वारा आसानी होता है।

युवाओं में असंतोष की भावना को दूर करना।

विशेष विशेषकर इराक, सीरिया जाने वाले युवाओं पर विशेष निगरानी बनाये रखना।

भारत को इन प्रयासों द्वारा कट्टरपंथी विचारधारा से निजात मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Arguments on Siachen issue often move around the idea of demilitarisation. Examining the key attributes of the Siachen issue explain the basis of arguments regarding its demilitarisation? Also highlight the arguments against such an idea.

सियाचिन मुद्दे पर प्रस्तुत तर्क अक्सर विसैन्यीकरण के विचार के आस-पास मंडराता रहता है। सियाचिन मुद्दे से जुड़े प्रमुख पहलुओं का परीक्षण करते हुए इसके विसैन्यीकरण संबंधी तर्कों के मूलाधारों की व्याख्या कीजिए? साथ ही इस तरह के विचार के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों पर भी प्रकाश डालिए।

सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में कारकोरम में महत्वपूर्ण रणनीतिक अवस्थिति को दर्शाता है। कई कारणों से सियाचिन के विसैन्यीकरण का मुद्दा बना रहा है।

सियाचिन में जलवायु के दृष्टि से प्रतिकूल स्थितियों के कारण प्रतिवर्ष हिमस्खलन तथा हिमस्खलन से कई जवानों की मृत्यु होती है। इस मानव क्षति को रोकने हेतु एक विसैन्यीकरण की बात होती है।

सियाचिन में सरकार का सैन्य व्यय बहुत अधिक है। प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक खर्च होता है।

स्वतंत्रता के पश्चात सियाचिन में हजारों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मौसमों की प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण घटित हो चुकी है।

विकेन्द्रीकरण के खिलाफ तर्क -

- क्रियान्वयन के नीतिगत हाशियेपन के महत्वपूर्ण होने के कारण इसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि इस पर भारतीय नीतिगत लाभ है तथा यहां विकेन्द्रीकरण से भारत एक नीतिगत स्थिति खो देगा।
- पाकिस्तान का भी विकेन्द्रीकरण रवैया इस दिशा में बाधक होगा।
- चीन की बढ़ती भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति। चीन द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी आर्थिक, सामरिक गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है।

इस संबंध में कई विचारकों द्वारा क्रियान्वयन को अव्यावहारिक बताने तथा वैज्ञानिक छेड़ छाड़ बताने पर विचार व्यक्त किया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि सियाचीन पर तैनाती मानव सैनिकों द्वारा न रखकर प्रौद्योगिकी संयंत्रों के माध्यम से भी की जा सकती है।

तथापि ये कभी बेहतर विकल्प नहीं है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए तथा भारत की सीमावर्ती स्थितियों को देखते हुए सियाचीन का विसैन्यीकरण एक अच्छा कदम नहीं होगा।

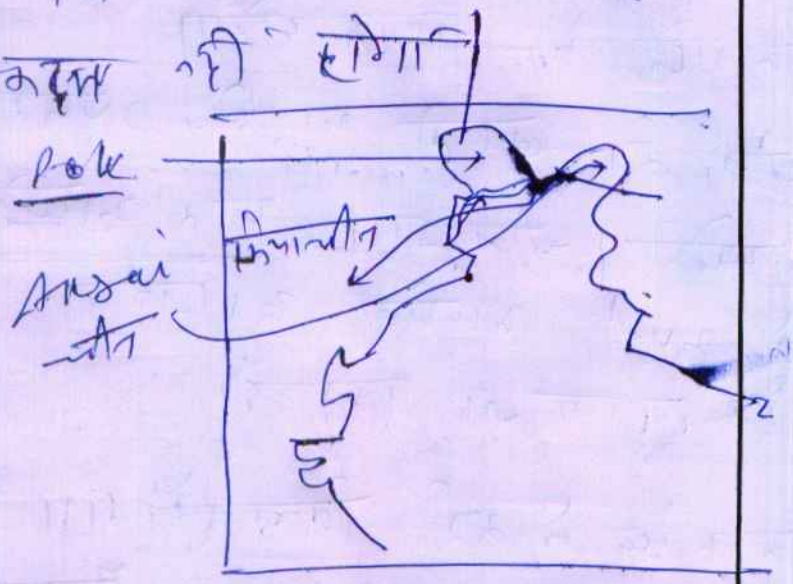

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Money laundering and terrorism have strong inter linkages. Illustrate. In this context, how far do the steps taken by the government confirm with the international commitments?

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद मजबूती से एक-दुसरे से सम्बद्ध हैं। स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाए गए कदम किस हद तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हैं ?

मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध गतिविधियों द्वारा उत्पन्न धन प्रक्रिया से है। आतंकवादी गतिविधियों में इसी धन का प्रयोग किया जाता है।

- जम्मू-कश्मीर राज्य में कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने हेतु ISI तथा अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा हवाला के जरिये धन भारत में भेजा जाता है।
- हथियारों, मानव, सामानों तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा उत्पन्न धन का प्रयोग किया जाता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। देश में अवैध वित्तीय हस्तांतरणों का चलन बढ़ने से पूरी वित्तीय प्रणाली चरमरा जाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आतंकवाद
- धार्मिक
- जैव आतंकवाद
- सामाजिक

↓

नई लामबंदी

↓

देश पर बहुत नकारात्मक प्रभाव

सरकार द्वारा उठाये गये कदम:

- भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 36 वां सदस्य बनाया गया है
- धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इसे अधिनियम द्वारा विहित किया गया है कई अन्य गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है
- G-20 जैसे फोरम के माध्यम से आतंकवाद की निंदा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Longstanding issue of insurgency in the Northeast highlights the linkage between violence, remoteness, underdevelopment and alienation. Elaborate. Also, suggest some corrective measures for a lasting resolution of the conflicts in this region.

पूर्वोत्तर में लम्बे समय से विद्यमान उग्रवाद का मुद्दा वस्तुतः हिंसा, दूरी, अल्पविकास, और अलगाव की भावना के मध्य के संबंधों पर प्रकाश डालता है। सविस्तार व्याख्या कीजिये। इसके साथ ही इस क्षेत्र में संघर्ष के एक स्थायी समाधान के लिए कुछ सुधारात्मक उपायों का सुझाव भी दीजिए।

स्वतंत्रता के पश्चात से ही पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियां विद्यमान हैं।

हिंसा - पूर्वोत्तर में सैन्य बलों द्वारा की गई कई हिंसक कार्रवाहियों ने उग्रवादी संगठनों को सरकार के प्रति लोगों को उकसाने का मौका मिलता है।

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विरोध

दूरी → नागालैंड
→ अरुणाचल
→ आसाम

भारत के कई हिस्सों के लोगों द्वारा पूर्वोत्तर के लोगों को गैर अपनत्व की भावना से देखा जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- मेघालय राज्य में अवसंरचना- रेल, सड़क नेटवर्क का अभाव।
- आर्थिक दृष्टि से संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं।
- अल्पविकास - ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों का प्रभावी विकास नहीं। विस्थापन की समस्या
- अलगाव की भावना - लोगों में एकीकरण की भावना का कई अवसंरचनाओं - NSCN (पृथकतावादी) द्वारा समर्थन किया जाता है।

क्षेत्रीय समाधान हेतु प्रयास :

- अफस्पा के संबंध में त्रिपुरा मॉडल को अपनाना। जिन क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं विद्यमान नहीं है वहां से अफस्पा को समाप्त करना।
- लोगों में अपनत्व की भावना का विकास करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवसंरचना - रेलवे, सड़क नेटवर्क का प्रभावी विकास करना। ताकि ग्रामीण सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो।

कदाचारी व अलगाववादी समूहों पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करना।

अलगाववादी समूहों के वित्त पोषण के स्रोतों को रोकना। इसमें इन समूहों द्वारा सरकार चलाकर सरकारी धन का गलत उपयोग किया जाता है ऐसी गतिविधियों को प्रभावी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है।

लोगों में सांस्कृतिक मेलमिलाप की भावना को प्रोत्साहित करना हॉर्नबिल जैसे त्यौहारों के जरिये सांस्कृतिक सामंजस्यता को, मेलमिलाप को बढ़ावा देना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While on the one hand China's One Road One Belt initiative poses security concerns and challenges for India, on the other, it can help improve India's connectivity to major markets and resource supplies. Discuss.

जहाँ एक ओर चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' पहल भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं और चुनौतीयां खड़ा करता है, वहीं दूसरी ओर यह संसाधनों की आपूर्ति और प्रमुख बाजारों तक भारत की कनेक्टिविटी (संयोजकता) को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। चर्चा कीजिए।

चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति में जहां भू राजनीतिक आयाम सामने आते है वहीं यह बेहतर संपर्कता विकास का मार्ग है

वन बेल्ट वन रोड
- चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
- सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट
- सामुद्रिक सिल्क रोड

- CPEC कॉरिडोर जो इसी नीति का भाग है उसके पाक अधिकृत कश्मीर (POK) से गुजरने के कारण भारत को इसकी चिंता है
- इसके साथ ही कॉरिडोर चीन के जिनजियांग क्षेत्र को पाक के ग्वादर बंदरगाह से जोड़कर अरब सागर में चीन के प्रभाव को बढ़ायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- हिंद महासागर में भारत के प्रभावी हितों को चुनौती।

- मेरीटाइम सिल्क रोड नीति माध्यमिक रूप से चीन, भारत, कोलकाता, अफ्रीका को जोड़ेगी। इसके भी भारत के लिए अपने निहितार्थ है।

- इसके अतिरिक्त 'वन बेल्ट वन रोड' नीति के चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना- रेल, सड़क नेटवर्क विकसित करेगा। जबकि भारत की अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित पहुंच है जिससे पूरा क्षेत्र संबंधी चिंताएं उत्पन्न होंगी।

- अफगानिस्तान नीति के नकारात्मक लाभ होने की भी उम्मीद है

- संसाधन आपूर्ति - इराक, सीरिया, अफ्रीका महाद्वीप बीच बेहतर अवसंरचना नेटवर्क के संसाधनों की अबाध आपूर्ति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कुशलता होगी इसके अतिरिक्त सभी जुड़े हुए देशों में आर्थिक व्यापार व निवेश बढ़ेगा।

भारत के कोलकाता व दमदम की कम समीपवर्ती देशों से बेहतर कनेक्टिविटी कुशलता होगी। भारत का BCIM (बांग्लादेश, चीन, भारत) म्यांमार कॉरिडोर भी इसका एक हिस्सा बनेगा।

भारत की look east policy को बल मिलेगा क्योंकि पूर्वी एशिया के देशों से बेहतर कनेक्टिविटी होगा।

तथापि चीन की इस नीति के अपने भू-राजनीतिक आयाम है कई विश्लेषकों द्वारा इसे अमेरिका की 'pivot to Asia' नीति को कुंठित करने के रूप में देखा जाता है।

भारत को IORA जैसे मंचों के माध्यम से हिंद महासागर में अपने प्रभावी सामर्थ्य विस्तार करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. NATGRID was an ambitious step involving intelligence reforms, however, it remained a non-starter. Explain. In the context of recent initiatives to revive the NATGRID and the challenges it faced previously what steps are required to make it effective?

नेटग्रिड (NATGRID) इंटेलिजेंस सुधारों से सम्बंधित एक महत्वाकांक्षी कदम था, हालांकि यह शुरू नहीं हो पाया। व्याख्या कीजिए। नेटग्रिड को पुनर्जीवित करने की हाल की पहल और पूर्व में इसके द्वारा सामना की गयी चुनौतियों के संदर्भ में, इसे प्रभावी बनाने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

नेटग्रिड से अभिप्राय राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड से है इसके अंतर्गत भारत को एकमुश्त रूप से एक आसूचना ग्रिड के रूप में परिवर्तित कर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जायेगा।

भारत में सभी आपराधिक गतिविधियों/व्यक्तियों का रियल टाइम डाटाबेस तैयार करना, जिससे अपराधियों की शीघ्र पहचान हो सके। आपराधिक आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके।

सभी प्रचलित खतों व आसूचना विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना।

अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना।

आसूचना प्रणाली को बेहतर बनाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नेटग्रिड को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों व भारत सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है।

- राज्य सरकारों के कुछ संबंधी मुद्दों और आदि समितियों के संबंधित लिटिगेशन प्रभावी समाधान करने की आवश्यकता है।
- एक ग्रिड बनाने के लिए डिजीटल डाटाबेस तैयार करने हेतु एक संस्थागत ढांचा बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एम बेहतर प्रौद्योगिकी सेटअप की जरूरत है।
- साइबर अपराधों व हैकिंग के खतरे से डिजीटल डाटाबेस को सुरक्षित करने हेतु उत्तरदायित्व मानकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. India's national security architecture faces a difficult task in detecting digital intrusion in cyberspace. What are the challenges India faces w.r.t. Digital Intrusion? How can these challenges be overcome?

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना ,साइबर स्पेस में डिजिटल घुसपैठ का पता लगाने में मुश्किलों का सामना कर रही है। डिजिटल घुसपैठ के सन्दर्भ में भारत किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है?

डिजीटल घुसपैठ भारत के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समस्या है। डिजीटल घुसपैठ साइबर सुरक्षा प्रणाली के प्रभावपूर्ण न होने के कारण उत्पन्न होता है।

डिजीटल घुसपैठ
- बैंकिंग क्षेत्र
- दूरसंचार क्षेत्र
- रक्षा क्षेत्र

भारत में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी। वर्तमान में 1000 से भी कम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भारत में मौजूद जबकि साइबर सुरक्षा खतरे बढ़ते जा रहे है।

साइबर सुरक्षा हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी तंत्र का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- जियोलॉजिकल सुरक्षा संकेत हेतु बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक प्रचालन तंत्रों का भारत में अभाव।
- भारत में अधिकतर कुआं आबादी के निकट मौजूद रहने के कारण मीडिया में जानकारी लीक हो जाती है अतः सरकार की सुरक्षा हेतु कोई मानक संस्थागत सुरक्षा योजना मौजूद नहीं।
- सारसर पेट्रोलिंग की प्रभावी प्रक्रिया की अनुपस्थिति।
- भारतीय जियोलॉजी को अधिकतर विदेशी कंपनियों द्वारा तैयार किया जाता है। जियोलॉजी सेवाओं के लिए भारत की विदेशी कंपनियों पर अधिक निर्भरता है जिससे भारतीय जियोलॉजी तंत्र पर संकट बना रहता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियों का निराकरण :

- इस हेतु सरकार द्वारा विशेषज्ञों की सेवा बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा।
- सरकार द्वारा नीति 2013 के दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- सरकार पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देना।
- अंतरराष्ट्रीय बेहतर जियोल नेटवर्कों का प्रयोग करना।
- सरकार द्वारा प्रति कंपनियों व लोगों में जागरूकता का प्रसार करना।
- विभिन्न देशों के साथ आपसी सहयोग व समन्वय द्वारा जियोल क्षेत्र का प्रसार करना।
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु भारतको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Relations with Iran hold a lot of potential for India's ambitions for West Asia and beyond, however, realising this potential also involves certain global and regional challenges. Examine.

ईरान के साथ संबंध वस्तुतः पश्चिम एशिया और उससे परे भारत की महत्वाकांक्षा के लिए संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, तथापि इस संभावना को साकार करने के मार्ग में कुछ वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियां भी हैं। परीक्षण कीजिए।

भारत व ईरान के मध्य संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के विकास की आकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा सुरक्षा - चाबहार पोर्ट से भारत को तेल, गैस की आपूर्ति भारत के ऊर्जा सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।

चाबहार पोर्ट के जरिये भारत अफगानिस्तान (जरंज-डेलाराम रोड) के साथ मध्य एशियाई देशों से संपर्क स्थापित कर सकेगा। जिससे मध्य एशियाई देशों के संसाधनों का इसकी उपयोग सुनिश्चित होगा।

भारत की पहुंच मार्ग में वैकल्पिक मार्ग बनाने हेतु ईरान के साथ भारत की मित्रता आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पारस्परिक सुरक्षा में भारत के हितों के दृष्टिकोण से (प्रवासी भारतीय आदि भी ईरान महत्वपूर्ण है)

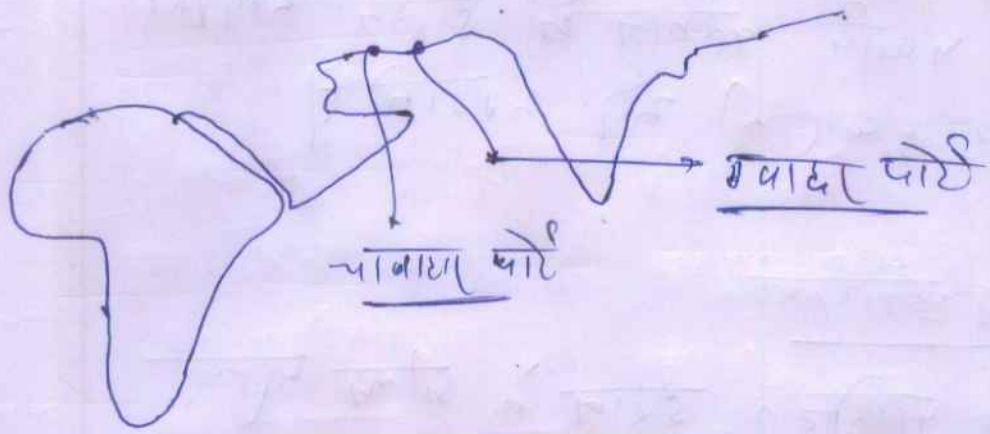

कार्यक्रम चुनौतियां :

भारतीय ईरान के साथ बढ़ती नजदीकी के ~~साथ~~ कुर्दी अरब के साथ भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कुर्दी अरब ईरान के बीच अच्छे संबंध नहीं है

ईरान के भारत के साथ संबंधों से इसराइल के साथ प्रभावित होगी। पाकिस्तान, चीन के परिप्रेक्ष्य में कई चुनौतियां मौजूद है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- हाल में अमेरिका व ईरान के बीच खबरों में है अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए थे जिससे भारत को ईरान द्वारा तेल निर्यात पर भी असर पड़ा यद्यपि वर्तमान में ईरान-अमेरिका संबंध सुधार की ओर अग्रसर है।

- क्षेत्रीय चुनौतियां

- भारत, पाकिस्तान, ईरान के बीच मध्य कॉरिडोर फोकस राजनीतिक स्थितियां

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The internal crisis in Nepal over the past few years has given concrete shape to the fears of China gaining upper hand vis-a-vis a traditionally influential India. Elaborate. What can India do to further strengthen its ties with the Himalayan nation?

पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के आतंरिक संकट ने पारंपरिक रूप से प्रभाव रखने वाले भारत पर चीन द्वारा बढ़त लिए जाने के भय को ठोस आकार प्रदान किया है। विस्तारपूर्वक बताईए। इस हिमालयी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को अधिक मजबूत करने हेतु भारत और क्या कर सकता है?

नेपाल में संवैधानिक संकट के कारण मधेसी व पहाड़ी नेपाली समुदाय में बढ़ती दूरियों का भारत-नेपाल संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

- हाल में मधेसी समुदाय द्वारा ब्लॉक की (नाकेबंदी) घटनाओं के कारण नेपाल-भारत के संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसका लाभ चीन द्वारा उठाकर प्रयास किया गया।
- भारत के हल्दिया बंदरगाह का चीन नेपाल द्वारा सामानों की आवाजाही हेतु उपयोग किया जाता है जो नेपाल से लगभग 1000km है। चीन द्वारा नेपाल को अपने बंदरगाहों का प्रयोग करने की अनुमति देने से चीन द्वारा भारत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

न बढ़त लिए जाने के प्रयासों को बल मिला। यद्यपि चीन का बंदरगाह नेपाल से 3000 km की दूरी के कारण भारतीय तुलना में आर्थिक दृष्टि से कम संभाव्य है।

चीन द्वारा नेपाल के साथ रेल नेटवर्क, सड़क नेटवर्क के संबंध में समझौता। यद्यपि यहां भी यह महत्वपूर्ण होगा कि चीन बाहरी देशों के लिए तिब्बत को कितना खोलना चाहता है।

चीन की अवस्थिति भारत की तुलना में कम लाभकारी है। नेपाल के लिए चीन भारत का विकल्प नहीं हो सकता।

तथापि वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारत-नेपाल संबंधों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- मधेसी समुदाय के साथ मिलकर नेपाल सरकार द्वारा भारत के कूटनीतिक प्रयासों से संवैधानिक संघर्षरत स्थिति का समाधान करना।
- इस संबंध में 'गुजराल डॉक्ट्रिन' व PM मोदी की 'neighbourhood first' (पड़ोसी प्रथम) नीति महत्वपूर्ण है। इनके पारिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा नेपाल के साथ सहयोगी संबंध बनाने होंगे।
- भारत द्वारा भूकंप में नेपालवासियों को सहायता पहुँचाना व 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संबंध संधि में संशोधन करना एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत-नेपाल दोनों देशों को द्विपक्षीय रूप से संबंधों में 'बाधा वाले तत्वों' का समाधान बिना किसी तीसरे देश को बीच में लाये, करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. The Trans-Pacific Partnership agreement (TPP), touted as the world's biggest trade deal to date, has danger of bending the WTO rules. In this context, discuss the impact TPP can have on India's foreign trade. What are the options that India has to deal with the issues arising out of the TPP?

विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते के रूप में प्रचारित ट्रांस-पेसिफ़िक पार्टनरशिप (टी.पी.पी.) समझौते द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के नियमों को प्रभावित करने की आशंका है। इस परिप्रेक्ष्य मे भारत के विदेश व्यापार पर टी.पी.पी. के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। टी.पी.पी. से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए भारत के पास क्या विकल्प हैं?

ट्रांसपेसिफिक पार्टनरशिप समझौता अमेरिका व अन्य 11 देशों के बीच होगा क्षेत्रीय व्यापारिक करार है जिसका भारत के GDP पर प्रभाव पड़ने की संभावना है

TPP का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं :-

- भारत का Trade diversion के कारण निर्यात पर विपरीत असर पड़ेगा। वियतनाम के TPP में शामिल होने के बाद उसके का वियतनाम से कड़ी चुनौती मिलेगी क्योंकि वियतनाम निर्यातकों को TPP देशों में कम टैरिफ दरें होंगी।
- भारत का भुगतान संतुलन प्रभावित होगा।
- भारत की GDP पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

श्रम नियम

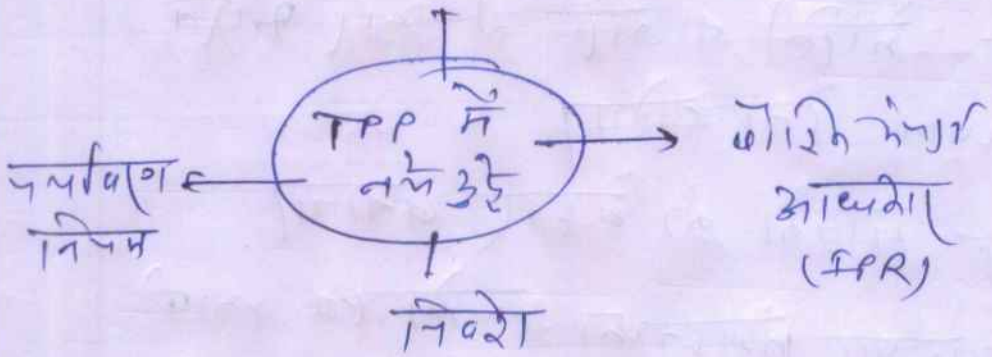

- श्रम, पर्यावरण के संबंध में अधिक कड़े नियम बनेंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी हस्तांतरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- TPP देशों में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी मुद्दों के उठने की संभावना है।

भारत के पास इन TPP उत्पन्न मुद्दों से निपटने हेतु कम विकल्प उपलब्ध है।
- भारत को TPP देशों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से साथ (मुक्त व्यापार समझौता) वार्ता करने की दिशा में प्रयास करना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्यात बाजार की विविधता प्रदान करना
तथा उभरती बाजारों की ओर भारत
को ध्यान देना होगा।
निर्यात मानकों को बेहतर बनाना।
विश्व व्यापार संगठन का प्रभावी एवं प्रभावी
सदस्य बनना ताकि भारत के
प्रतिस्पर्धी आर्थिक हितों पर विपरीत
प्रभाव ना पड़े।
इस संबंध में भारत को RCEP
(क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
समझौता) जैसे संगठनों में समस्याओं
पर ध्यान देना होगा।
श्रम, पर्यावरण मानकों में सुधार कर के
सुधार करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Legal proceedings initiated by the Marshall Islands against India, Pakistan and Britain over nuclear weapons in the International Court of Justice highlights the issues of jurisidiction of the court. What is India's position vis-a-vis the jurisdiction of the ICJ? Also differentiate between binding and advisory pronunciations of the court with suitable examples.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) में मार्शल द्वीपसमूह द्वारा भारत, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के खिलाफ़ परमाणु हथियारों को ले कर आरम्भ की गयी कानूनी कार्यवाहियाँ वस्तुतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मुद्दे को उजागर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में भारत का क्या रुख है? साथ ही उचित उदहारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के बाध्यकारी तथा सलाहकारी निर्णयों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी कार्यवाही हेतु दोनों देशों का सहमत होना आवश्यक है तभी उस कार्यवाही को मान्य माना जायेगा। दोनों पक्षों द्वारा कार्यवाही को सहमति दे दी जाने पर ICJ द्वारा दी गई निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे।

मार्शल द्वीप समूह द्वारा भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन के खिलाफ़ आरम्भ की गई कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रश्न खड़े हो गये हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किसी भी कार्यवाही के प्रारंभ हेतु सभी पक्षों द्वारा सहमति दिया जाना आवश्यक है। इस आदर्श कार्यवाही को एकपक्षीय कार्य माना जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Even though the refugee crisis in Europe does not affect India directly, it presents an opportunity for India to showcase its commitment and capability to take greater responsibility in dealing with global issues. Comment in light of India's strengths, experience and international commitments regarding refugees.

यद्यपि, यूरोपीय शरणार्थी संकट का भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए वैश्विक मुद्दों से निपटने हेतु अधिक बड़ी ज़िम्मेदारी ग्रहण करने संबंधी प्रतिबद्धता तथा क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। शरणार्थी संबंधी भारत के सामर्थ्य, अनुभव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आलोक में इस पर टिप्पणी कीजिए।

यूरोपीय शरणार्थी संकट का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव न होने के बावजूद भारत के एक वैश्विक शक्ति होने तथा भारत के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार होने के संबंध में भारत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

वैश्विक शांति के अपने सिद्धांतों को प्रभावी रूप देने हेतु भारत को शरणार्थी संकट के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1946 तथा शरणार्थी प्रोटोकॉल 1967 का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है तथापि भारत की ~~एक~~ सीमावर्ती स्थिति भी से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देखते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण आकड़ा निभाने की आवश्यकता है।

भारत की चुनौतियां :

- म्यांमार सीमा पर रोहिंग्या शरणार्थी समस्या - हाल ही में बम विस्फोटों में रोहिंग्या शरणार्थी की भूमिका के बारे में पता चला था।
- बांग्लादेश के जलवायु शरणार्थी (डेल्टाई क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव) की समस्या के संबंध में भारत में संस्थागत ढांचे का अभाव।
- श्रीलंका के तमिल लोगों के विस्थापन की समस्या।

भारत अभी शरणार्थी समस्या के निपटने हेतु प्रभावी रूप से सक्षम नहीं है। भारत में संभावित संकट या भूमि समस्या एवं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कुछ हुआ है।

लोगो व आस्लिक आबादी के बीच असम में संघर्ष की स्थिति

अवसर - 1971 में शरणार्थी समस्या के कारण सामना हुआ वर्तमान में भी बांग्लादेशी सीमा पर शरणार्थियों व अवैध प्रवासियों का आवागमन होता रहता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण अभी किसी शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं है। UN शरणार्थी एजेंसी में शरणार्थी की समीक्षा परिभाषा दी गई है। इसमें पर्यावरण शरणार्थी को शामिल नहीं किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रवासन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सुधार की ओर कदम बढ़ाना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. India is endowed with an amazing variety and wealth of soft power resources. Providing examples, illustrate the utilisation of soft power in diplomatic initiatives of the recent past. What are the limitations of the soft power approach in diplomacy in case of a developing country such as India?

भारत सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति) संसाधनों की आश्चर्यजनक विविधता एवं बहुलता से संपन्न है। उदहारण प्रस्तुत करते हुए, हाल के कूटनीतिक पहलों में सॉफ्ट पावर के उपयोग का वर्णन कीजिए। भारत जैसे किसी विकासशील देश के लिए कूटनीति में सॉफ्ट पावर एप्रोच (मृदु शक्ति उपागम) की क्या सीमाएं हैं?

भारत सॉफ्टपावर के रूप में एक प्रमुख देश है। भारत द्वारा इस शक्ति का प्रभावी प्रयोग किया जाता है।

सॉफ्ट कूटनीति - काशी-क्योटो पहल
रांची-अहमदाबाद पहल

'फिट इंडिया' अवधारणा

भारत द्वारा मालदीव में पानी के संकट के दौरान पानी की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करना।

यमन में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन राहत- जिसमें कई विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत जैसे विकासशील देश के लिये soft & hard power दोनों के बीच संतुलन की स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत के कूटनीतिक दांचे पर कोई समस्या उत्पन्न होने पर भारत को एक प्रभावी कदम उठाना होगा।

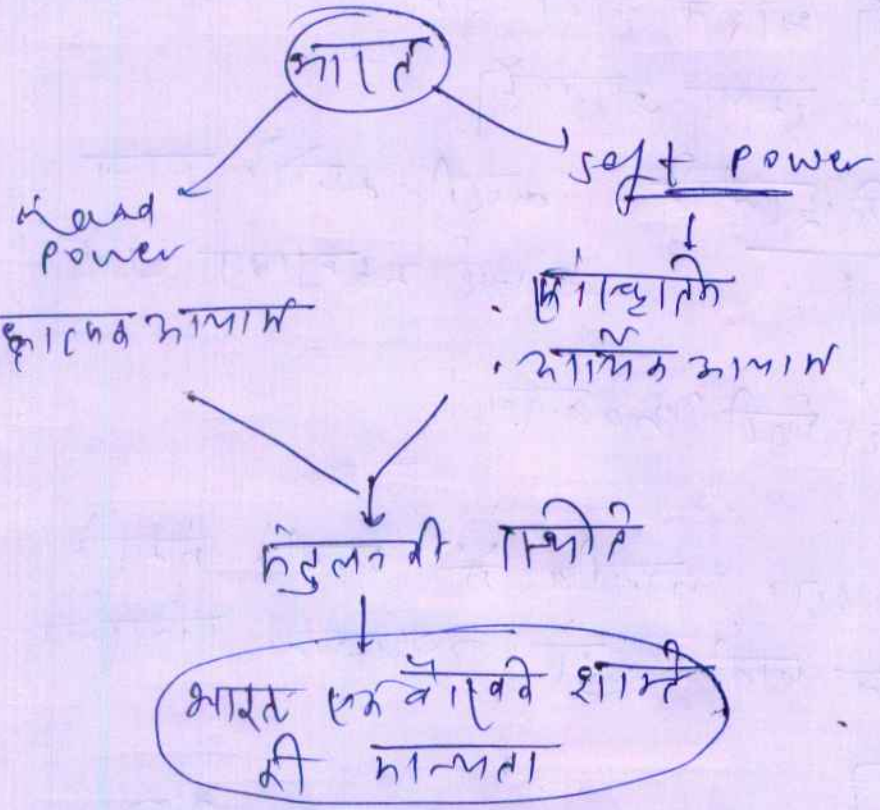

soft power की सीमाएं :

- soft power एक सीमा तक सही है। आक्रमणकारी रुझानों के चलते आक्रमणकारी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुकाबले के लिए हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे आक्रामक होने पर विपरीत असर पड़ेगा।

- भारतको अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर अपनी नीति को तैयार करना होगा। राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हितों व वैश्विक हितों के बीच तारतम्य/सामंजस्य स्थापित कर भारतको कूटनीतिक पहल करनी होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोनों नीतियों का अपना महत्व है तथापि भारत के संदर्भ में वर्तमान समय तक एक प्रमुख नीतिगत पहल नहीं है वर्तमान में कूटनीतिक स्थितियों को देखते हुए हार्ड नीतियों को अपनाना भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight the features of NAVIC and bring out its significance for India. How is it different from GAGAN? Examine whether NAVIC can be a replacement of GPS for India.

नाविक (NAVIC) की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा भारत के लिए इसके महत्व को उजागर कीजिए। यह गगन (GAGAN) से किस प्रकार भिन्न है? परीक्षण कीजिए कि क्या नाविक भारत के लिए जी.पी.एस. को प्रतिस्थापित कर सकता है।

नाविक (नेवीगेशन इंडियन कांस्टेलेशन) भारत का एक नेवीगेशन सेटेलाइट तंत्र है इसके द्वारा भारत को कई लाभ होने की संभावना है-

- इसका संबंध सेटेलाइटों से होने से गति मिलेगी- आपातकालीन/ युद्ध जैसी स्थितियों में विदेशी नेवीगेशन तंत्र पर निर्भरता भारत के लिए इसका हानि से खतरनाक है।
- नाविकों, मछुआरों के लिए बेहतर नौसंचलन सुविधा प्रदान करना।
- आर्थिक संसाधनों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण की दृष्टि से उपयोगी।
- G.P.S. के स्थान पर नाविक का प्रयोग भारत की स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बढ़ायेगा।

- नाविक के अंतर्गत 7 कंस्टेलाइट होंगे।

IRNSS (Indian Regional navigation satellite system. जिसके तहत नाविक तंत्र में 4 उपग्रह व 3 जियोस्टेशनरी कक्षा में चक्कर लगायेंगे।

नाविक → standard enabling service - ऐसी सेवा सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी।

नाविक → Encrypted service विशेष रूप से सैन्य उपयोग हेतु

- नाविक द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के ई. सिर्फ 1500 km तक के क्षेत्र में सेवा आपातें प्रतिबंधित की जायेगी।

- नाविक द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में बचावकार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

गगन (GPS Aided Geo-Augmented Navigation System) नौसंचालन हेतु GPS पर आधारित था जबकि नाविक पूर्णतः भारतीय कोलाइट (स्वदेशी तंत्र) पर आधारित होगा। विदेशी कोलाइटों / तंत्र पर निर्भरता समाप्त होने की संभावना बढ़ेगी। भारत द्वारा स्वयं दिशों के उपग्रहों को लॉन्च करके राजस्व वृद्धि की संभावना है।

=) नाविक G.P.S. की तुलना में कम सटीक हो सकता है लेकिन इसके कुशल के माध्यम से भविष्य में यह एक महत्वपूर्ण नौसंचालन (नेवीगेशन) तंत्र के रूप में विकसित होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. What are Carbon Nanotubes (CNTs) and how are they an improvement over carbon fibres? Highlight the various unique properties of CNTs which makes them suitable to the manufacturing industry.

कार्बन नैनोट्यूब (सी.एन.टी.) क्या होते हैं तथा वे किस प्रकार कार्बन फाइबर से श्रेष्ठ हैं। सी.एन.टी. के उन विशिष्ट गुणधर्मों पर प्रकाश डालिए जो इसे विनिर्माण उद्योग हेतु उपयुक्त बनाते हैं।

कार्बन नैनोट्यूब, कार्बन से बने नैनोट्यूब (10^{-9}m) के स्तरीय संरचना है। कार्बन फाइबर की तुलना में इनका आकार कम होता है।

- इसके अतिरिक्त कार्बन फाइबर की तुलना में ये अधिक प्रभावी हैं।
- CNT- विद्युत संचलन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इनके विद्युत संचलन में विद्युत (ऊर्जा हानि) न्यूनतम होती है।
- विनिर्माण क्षेत्र में इनका उपयोग बिजली के प्रभावपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Explain the significance of gravitational waves recently detected by LIGO. What are the objectives of the recently envisaged LIGO-India project and what benefits will India accrue from it?

हाल ही में एल.आई.जी.ओ. (लिगो) द्वारा खोजे गए गुरुत्वीय तरंगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। हाल ही में परिकल्पित एल.आई.जी.ओ.-इंडिया प्रोजेक्ट (लिगो-भारत परियोजना) के क्या उद्देश्य हैं, तथा भारत को इससे क्या लाभ होंगे?

लिगो द्वारा खोजे गये गुरुत्वीय तरंगो से ब्रह्माण्ड की विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी।

- गुरुत्वीय तरंगे स्पेस- टाइम फैब्रिक (space-time fabric) है इनके द्वारा समय- स्थान तंत्र में हलचल की स्थिति का पता लगता है।
- आकाशीय पिण्डों - सुपरनोवा, white dwarf जैसी स्थितियों को समझने में सहायता मिलेगी।

लिगो-इंडिया प्रोजेक्ट- गुरुत्वीय तरंगो की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What are the criteria employed for a pandemic to be declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the WHO? In the wake of recent Ebola and Zika virus outbreaks examine the efficacy of the prevalent architecture of global health governance. Also, assess India's preparedness in handling such global epidemics.

डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा किसी महामारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ़ इंटरनेशनल कंसर्न (PHEIC) के रूप में घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं? हाल ही में इबोला तथा ज़ीका विषाणु के प्रसार के सन्दर्भ में वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता की जाँच कीजिए। ऐसी वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Give a brief explanation of CRISPR - gene editing technology. Also discuss its signif cance in modern biology and agriculture.

जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी - सी.आर.आई.एस.पी.आर. (CRISPR) की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। आधुनिक जीव-विज्ञान तथा कृषि में इसके महत्व पर भी चर्चा कीजिए।

CRISPR एक जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी है। इसके द्वारा जीन में क्रमबद्ध परिवर्तन करके अच्छे प्रभावी गुणों का विकास किया जाता है।

जीव विज्ञान :

प्रभावी जीन एडिटिंग से अनुवांशिक रोगों के उन्मूलन में मदद मिलेगी।
पार्किन्सन जैसी बीमारियों का सफल इलाज संभव होगा।
जीन के स्तर पर विद्यमान रोगों का निदान मिलेगी।
यद्यपि इससे जिज्ञासा बेबी का खतरे भी पैदा हो सकता है। जिज्ञासा बेबी से कई सकारात्मक नकारात्मक परिणाम पैदा होंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पादपों के स्तर पर बेहतर अनुसंधान/खोज करने में मदद मिलेगी।

कृषि :

- जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में फसलों में व्याप्त रोगों को रोकने में सफलता मिलेगी। सूखा प्रतिरोधी फसल तैयार करने में CRISPR की प्रमुख भूमिका होगी।
- ग्लोबल वार्मिंग के परिदृश्य में प्रभावी फसल उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी।
- बायो फोर्टिफिकेशन - जिंक युक्त चावल, लौह युक्त भाजपा किस्म तकनीक के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकेगा।
- कृषि में नवीन आधुनिक पोषणीय फसलों का विकास होगा जिससे किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Even though large infrastructure projects like High Speed Rail (HSR) facilitate greater technological development, they come with their own set of challenges. Examine in the context of proposed HSR projects in India. Suggest some measures on how HSR can truly be 'Made in India'.

यद्यपि हाई स्पीड रेल (एच.एस.आर.) जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकीय विकास में सहायता करती हैं, लेकिन उनकी भी अपनी चुनौतियां होती हैं। भारत में प्रस्तावित एच.एस.आर. परियोजनायों के परिप्रेक्ष्य में परिक्षण कीजिए। कुछ उपाए बताईये कि कैसे सही मायने में एच.एस.आर. 'मेड इन इंडिया' हो सकता है।

हाईस्पीड रेल अवसंरचना हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तथापि ऐसी परियोजनाओं की अपनी चुनौतियां है।

हाईस्पीड रेल हेतु भूमियों की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा है नई ट्रेन चलाने हेतु उपयुक्त पटरियां आवश्यक है। जबकि भारत में पटरियों का अभाव है।

विदेशी तकनीक पर उपलब्ध न होना। विदेशी तकनीक पर निर्भरता के कारण भारत पर कुप्रभावपूर्ण चिंताएं।

हाईस्पीड रेल परियोजनाओं हेतु निवेश एक प्रमुख कमी है। इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण भी आवश्यक आवश्यक है। भारत में सरकार व लोगों की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आर्थिक स्थिति रेल हेड एक समस्या बनी हुई है।

राजनीतिक मुद्दे

हाईस्पीड रेल लाने के पश्चात उनके लाभ की समस्या। क्योंकि उनका टैरिफ निर्धारण पारदर्शी ढंग से करना भी एक चुनौती होगी। भारत में रेल यात्रा किराया का अत्यधिक राजनीतिकरण होने से रेलवे को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

हाईस्पीड रेलों की सुरक्षा संबंधी मुद्दे उनकी ऑपरेशन लागत व रूटों की समस्या।

हाईस्पीड रेल के क्षेत्र में भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भरता बढ़ानी होगी। इस क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण के जरिये विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हरित रेल के वित्त पोषण हेतु उपयुक्त वित्तीय पोषण तंत्र का विकास करना होगा।

पटरियों की उपलब्धता बढ़ाती होगी व कुशलतापूर्वक ढांचे में सुधार करना होगा।

हरित रेल अवसंरचना विकास के हाशरेखा के महत्वपूर्ण बिंदु है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What do you understand by Big-data? Using SDGs as an example, discuss its role n effective implementation of public policy. Also mention challenges faced in using Big-Data and measures to overcome them.

बिग-डेटा से आप क्या समझते हैं? एस.डी.जी. को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए सार्वजनिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त, बिग-डेटा के प्रयोग में आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान के उपायों पर भी चर्चा कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R No
30 SEP 2016
N 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 845)

Name of Candidate	Shailendra Singh Indoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	30/9/16.

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

Signature of Examiner

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH.
3. All questions are compulsory.
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Soil management in Northeast India is critical for a viable agriculture economy. In this context, discuss the problems of soils in Northeast India. Suggest some steps that can be taken to counter this problem.
पूर्वोत्तर भारत में व्यावहारिक रूप से लाभप्रद कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मृदा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, पूर्वोत्तर भारत में मृदा संबंधी समस्याओं की चर्चा कीजिए। इस समस्या के हल हेतु उठाए जा सकने वाले कुछ कदम सुझाइये।

पूर्वोत्तर भारत में लाभप्रद कृषि व्यवस्था भारत के लिए एक संभावित समाधानात्मक क्षेत्र है इसहेतु मृदा प्रबंधन एक प्रमुख कारक है।

मृदा संबंधी समस्या.

- मृदा का अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होना। मेघालय पठार के क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है जो अनुर्वर है केवल ब्रह्मपुत्र मैदानी मृदा उपजाऊ है
- वर्षा की अधिक मात्रा के कारण मृदा की ऊपरी परत का बहाव।
- झूम कृषि के कारण मृदा का अकुशल प्रबंधन होना।
- मृदा के अनुरूप खेती का अभाव।
- भूस्खलन के कारण मृदा के बहाव की समस्या।
- मृदा का अनुपोषण की समस्या

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूसा कुशल प्रबंधन उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, रोजगार सृजन हेतु आवश्यक है।

समस्या समाधान -

- समस्या के समाधान हेतु सूक्ष्म कृषकों विनियमित करना
- ढाल का उचित प्रबंधन। सीढ़ीदार कृषि करना।
- 5% से अधिक ढलान पर खेती। 5-20% ढलान पर वानिकी तथा 20% से अधिक ढलान पर वन लगाना।

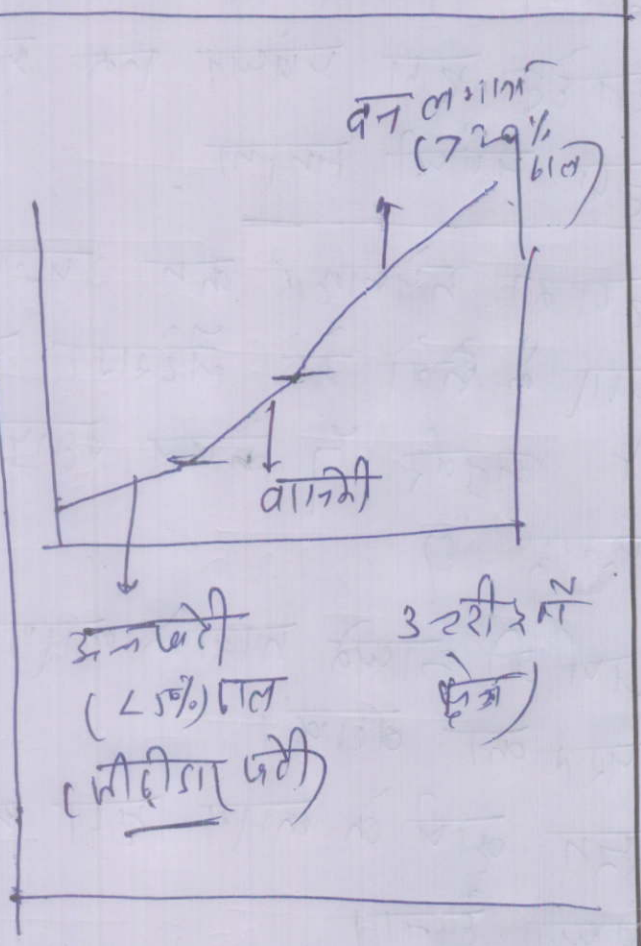

- स्थानीय जनजातियों को कृषि के संबंध में जागरूक करना।
- मृदा के अनुरूप खेती करना। पोषक तत्वों का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस्तेमाल न करना।

- मृदा प्रबंधन हेतु उचित दिशानिर्देश देना। इस संबंध में soil health card योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

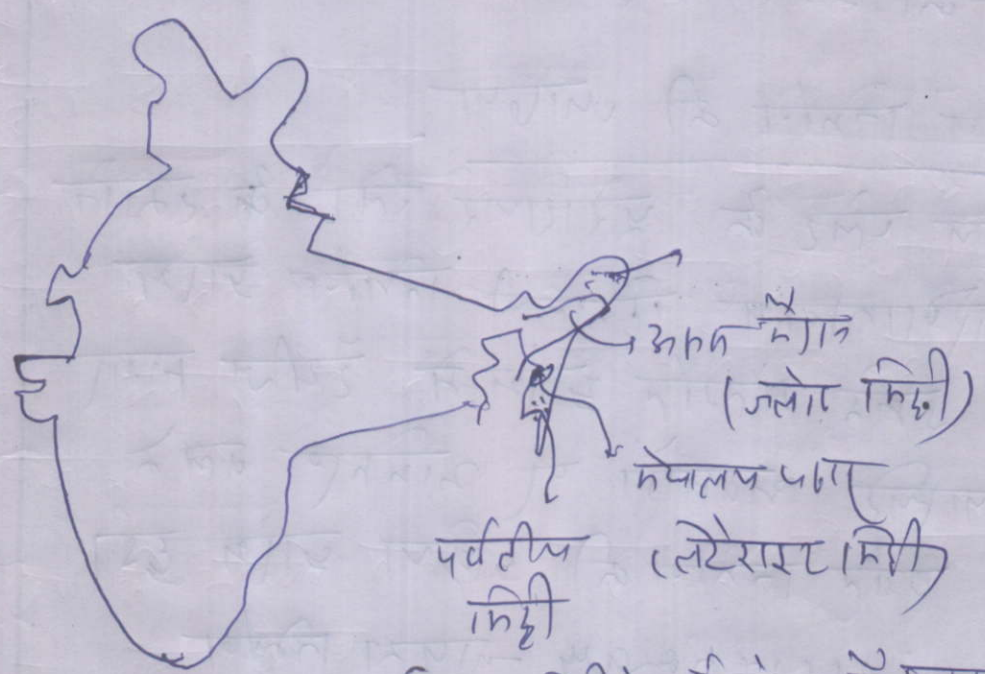

(तीनों मिट्टी के संबंध में मृदा प्रबंधन हेतु ~~इस~~ कठोर नीति बनाने की आवश्यकता)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. How does the plate tectonics theory help explain the formation of Himalayas and Deccan Traps?
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस प्रकार हिमालय और दक्कन ट्रैप्स के निर्माण की व्याख्या करता है?

प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है जो प्लेटों के गतिमान परस्पर अभिसरण व अपसरण की क्रिया द्वारा वर्तमान महाद्वीपीय स्थिति को प्रदर्शित करता है

हिमालय निर्माण की व्याख्या

भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट को टकराने के परिणामस्वरूप हिमालयी निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत प्रारंभ में टेथीज सागर में उपस्थित अवसादों पर अभिसरण बल के कारण पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

- सम्पूरक Accretionary - चापरा निर्माण
- विवर्तनिक क्रियाएं

हिमालयी निर्माण प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न हुई।

1) सागरीय- सागरीय प्लेट अभिसरण - इसके अंतर्गत प्लेटों के अभिसरण से पर्वतनिर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आरंभ में इयो-जियो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व मालो श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ

2) सागरीय-महाद्वीपीय प्लेट (सीमांत) अभिसरण
इसके अंतर्गत कार्डिलेरा का निर्माण हुआ

3) महाद्वीपीय-महाद्वीपीय प्लेट सीमांत
इसके अंतर्गत किसी प्लेट सीमांत का subduction नहीं हुआ बल्कि भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न हुई
उपर्युक्त अभिसरणों में सागरीय प्लेट का subduction हुआ क्योंकि वो भारी व अधिक घनत्व की थी

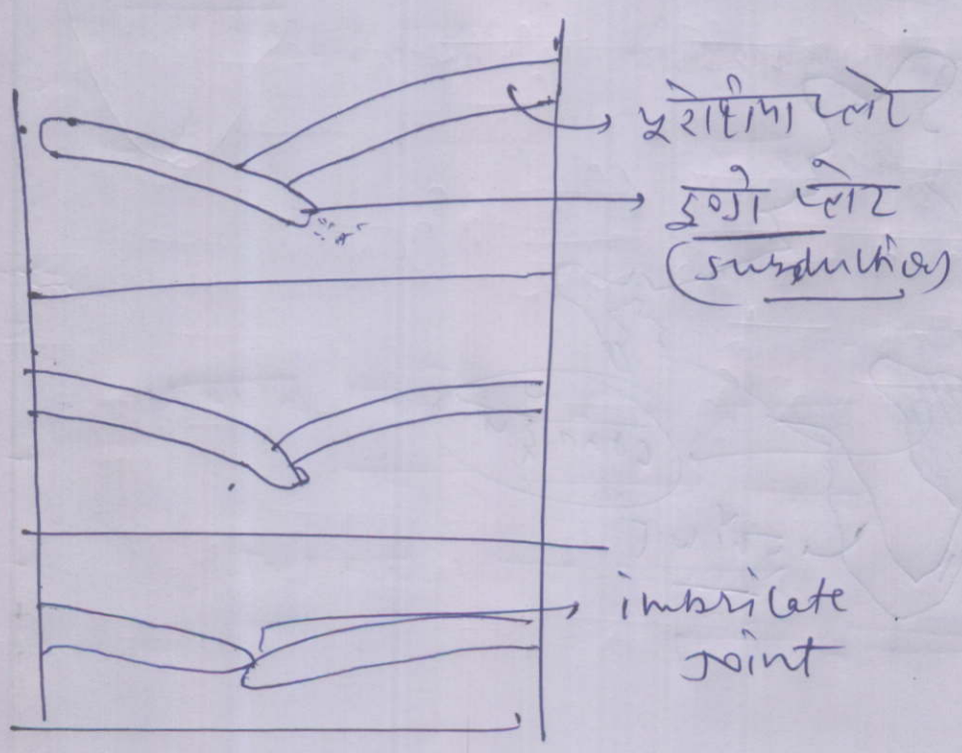

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दक्कन ट्रैप की निर्माण -

इसका निर्माण भारतीय प्लेट के रिइनियन होटस्पॉट से गुजरने के क्रम में हुआ। इसके अंतर्गत इस होट स्पॉट (Hot spot) से गुजरने पर लावा का ऊर्ध्वमुखी संचारण हुआ। इससे लावा के क्रमिक उत्थान से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।

भारतीय प्लेट व अफ्रीकी प्लेट के परस्पर टकराने तथा पृथक होने के संबंध में यह अभिक्रिया हुई।

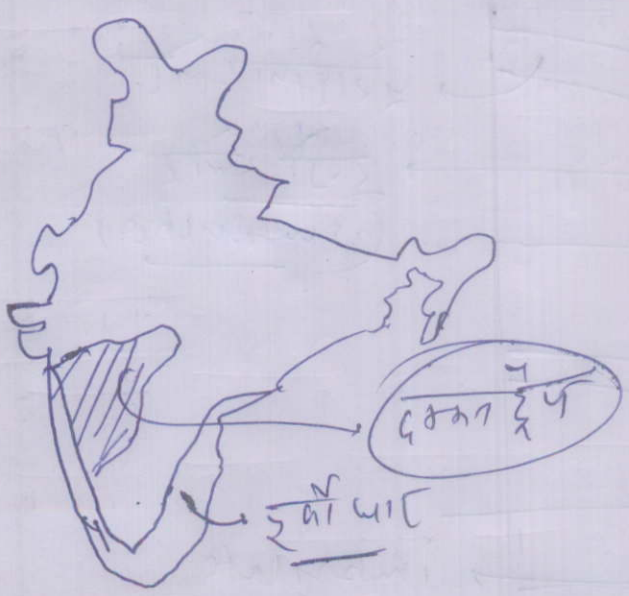

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Inspite being one of the largest producer of fish, there is still considerable scope of improvement in the fishery sector. In light of the above statement, discuss the problems and prospects of Fishery industry in India with respect to both inland and marine fisheries.

मत्स्य के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बाद भी, मत्स्य-क्षेत्र में सुधार की अभी भी पर्याप्त संभावनाएँ हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में भारत में अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्यन दोनों क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं एवं संभावनाओं पर चर्चा करें।

भारत में मत्स्य क्षेत्र में कई समस्याएं आज भी विद्यमान हैं जो अधिसंरचना, तकनीकी आदि से संबंधित हैं

भारत में समुद्रीय मत्स्यन समस्याएं -

I) प्राकृतिक समस्याएं

- मानसून के दौरान समुद्री मत्स्यन गतिविधि प्रभावित रही है। कम उत्पादन
- भारतीय उष्ण कटिबंधीय समुद्रीय क्षेत्र में मत्स्यों की प्रजाति अनुकूल (जाने की हाइट से) नहीं होती - अधिक लवण व कांटे के प्रभाव
- ठंडी व गर्म सागरीय धाराओं का अभिक्रमण ठीक प्रकार से न होने के कारण प्लांकटन का प्रचुर विकास न होने से मत्स्यन प्रभावित
- समुद्री सीमा का उपयुक्त निर्धारण न होने से मत्स्यन विवाद (भारत- श्रीलंका)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंतर्देशीय मत्स्यन समस्या -

- अंतर्देशीय स्तर पर मत्स्यन विकास हेतु प्रभावी प्रयास न करना।
- प्रदूषण के कारण मत्स्यन प्रभावित
- जलवायु परिवर्तन क्रम में नदियों के बहाव पर प्रभाव से मत्स्य प्रभावित
- केवल कुछ क्षेत्रों - बिहार (जल प्रदेश) तक सीमित।

दोनों क्षेत्रों की संयुक्त समस्याएं -

- उपयुक्त तकनीकी का अभाव
- कोल्ड स्टोरेज व अधिसंरचना की समस्या
- मछुआरा समुदाय के विकास हेतु प्रभावी प्रयास न करना।

समाधान -

- उपयुक्त तकनीक व अधिसंरचना प्रदान करना
- बेहतर सीमा निर्धारण करना
- deep sea मत्स्यन पर ध्यान देना (गहन सागरीय)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संभावना

- विश्व में मत्स्यन की बढ़ती मांग के कारण बेहतर संभावनाएं हैं।
- मत्स्यन का बेहतर विकास रोजगार सृजन करेगा।

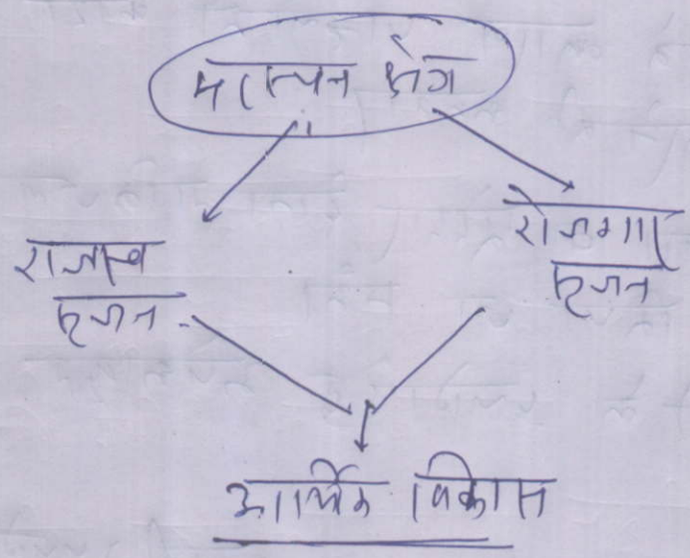

- खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की बढ़ती मांग के कारण मछलियों का भोजन के प्रयोग।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Vegetation in deserts and saline areas have highly specialized means of adapting themselves to the environment. Explain.

मरुस्थलों और लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति में स्वयं को पर्यावरण के प्रति अनुकूलित करने की अत्यधिक विशेषीकृत युक्तियाँ होती हैं। व्याख्या कीजिए।

मरुस्थलों व लवणीय क्षेत्रों में वनस्पति पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होती है।

मरुस्थल -

- जलवायु कमी के कारण पत्तियों को कांटे में रूपांतरित करने की क्षमता।
- तने का मोटा व मुलायम होना ताकि जल का भंडारण किया जा सके।
- जड़ों का पानी के प्रवाह हेतु अपेक्षाकृत गहरा होना
- वनस्पति में पानी भंडारण व प्रमाणी प्रवाह की अल्प झाड़ियाँ होना।

उदाहरण - कैक्टस (नागफनी)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लवणीय क्षेत्रों में विशेष रूपांतरण वनस्पति पाई जाती है।

- न्यूमेटाफोरस की उपस्थिति (श्वसन मूल) श्वसन हेतु उपयुक्त क्रियाविधि प्रदान करती है।
- इन पादपों का vivarious होना एवं बीज के हवा में ही विकसित होने की क्षमता।
- लवण की अधिक मात्रा को बाहर उत्सर्जित करने की क्षमता।
- लवणों की अधिक मात्रा को सहन करने की क्षमता।
- Buttress जड़ों की उपस्थिति जो पेड़ों को जमीन के बांधे रखती है जिससे तूफान के समय इनके टूटने की कम संभावना।

इस प्रकार दोनों क्षेत्रों की वनस्पतियों में उपयुक्त अनुकूलन दशाएं पाई जाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Give an account of the distribution of cement industry in India and the factors that affect its location. Also trace the growth of cement industry in India.

भारत में सीमेंट उद्योग के वितरण और इसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दें। साथ ही, भारत में सीमेंट उद्योग की वृद्धि की रूपरेखा भी प्रस्तुत कीजिए।

भारत में सीमेंट उत्पादन एक विशेष क्षेत्र में फैला है। सीमेंट उद्योग अवस्थिति विकास हेतु महत्वपूर्ण है।

सीमेंट उद्योग वितरण -

- मध्यप्रदेश के रीवा, सतना, कटनी क्षेत्रों में चूना पत्थर की उपलब्धि के कारण सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है।
- राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्रों- नागौर के गोटन, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा, जोधपुर के खरियाखंगार क्षेत्रों में सीमेंट उत्पादन होता है।
- आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के गुण्टूर, करीमनगर क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग फैला है।
- गुजरात के समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में भी इसकी अवस्थिति है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक -

- कच्चे माल की उपलब्धता - इसके अंतर्गत भूमि, पानी, संसाधनों की उपस्थिति आवश्यक होती है।
- तकनीक की उपलब्धता
- सीमेंट खपत हेतु बाजार की उपस्थिति
- पूंजी व सरकारी नीतियों की अवस्थिति पर प्रभाव।

सीमेंट उद्योग हेतु बेवर नियम के अनुसार कच्चे माल की स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह एक भारसह उद्योग है।

- सीमेंट उद्योग का भारत में विकास स्वतंत्रता से पहले प्रारंभ हुआ। सीमेंट उद्योग में कई तरह के सीमेंट का निर्माण होता है।
- सफेद सीमेंट
- ग्लास फर्नेस स्लैग उत्पन्न सीमेंट
- स्टील प्लांट स्लैग उत्पन्न स्लैग से सीमेंट

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सीमेंट उत्पादक कंपनियाँ हैं: ACC सीमेंट, बंगुर, अंबुजा प्रमुख है।

संभावना :-

- अधिसंरचना विकास के कारण सीमेंट की बढ़ती मांग।
- नगरीकरण, औद्योगीकरण गतिविधियों के कारण सीमेंट की खपत में वृद्धि संभावना।
- भारत के सीमेंट की गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग।

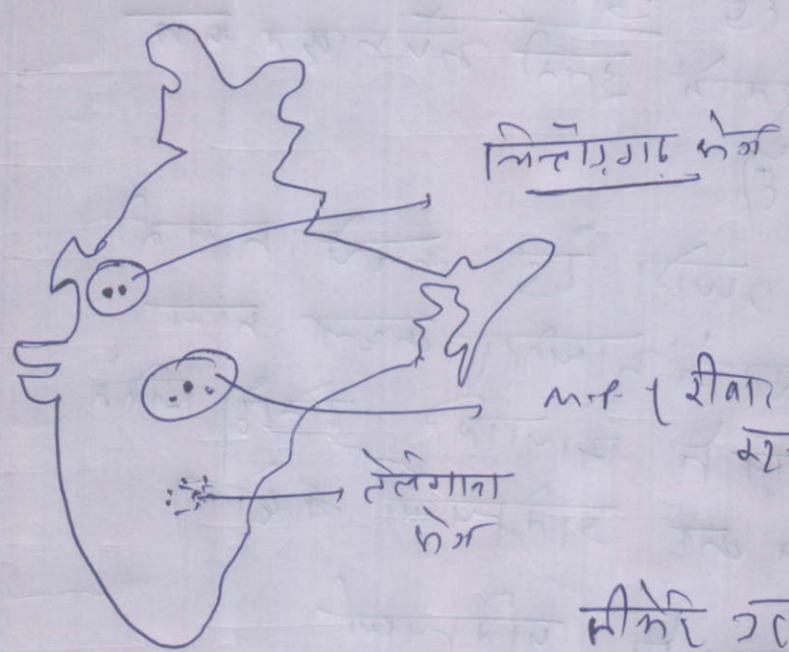

सीमेंट उत्पादक क्षेत्र

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Despite the enormous demand of electronics, the manufacturing of electronic goods has not been a feature of the Indian industry. Enumerate the reasons for the same. Suggest measures which are required to acheive the target of Net Zero Import by 2020.

इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी मांग के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण भारतीय उद्योग का वैशिष्ट्य नहीं है। इसके कारणों को उल्लिखित करें। ऐसे उपायों का सुझाव दीजिए जो 2020 तक शुद्ध रूप से शून्य आयात का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वांछित हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी मांग के बावजूद भारत इस उद्योग में प्रमुख नहीं है।

कारण -

- भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में प्रभावी नीतिगत कार्यक्रमों व योजनाओं की कमी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में इनकी अपेक्षाकृत कम उपलब्धता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु कच्चे माल की समस्या। भारत में अधिकतर कच्चा माल चीन से, जापान से आयात होता है जिसके कारण लागत का प्रतिस्पर्धी न होना।
- वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा
- एशिया में चीन, जापान देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महारथ हासिल होने के कारण भारत पर प्रभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अपेक्षाकृत प्रारंभिक इंजन की समस्या
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास प्रदूषण रहित क्षेत्रों में अधिक होता है। भारत के बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या

विकास हेतु उपाय -

- भारत को इलेक्ट्रॉनिक नीति के मॉडेल में काफी उन्नति की आवश्यकता है।
- अनुसंधान संस्थानों के कुशल लोगों की उपयोगों के संबंध में निरंतर करना
- उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- घरेलू बाजार को फैलाना।
- कच्चे माल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र हेतु उपयुक्त कच्चे माल की आपूर्ति के साथ आधुनिक तकनीक की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Agroforestry is seen as a solution to meet the challenges of food, nutrition, energy, employment and environment security. Elucidate.

कृषि-वानिकी को भोजन, पोषण, ऊर्जा, रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के रूप में देखा जाता है। स्पष्ट कीजिए।

कृषि वानिकी से तात्पर्य कृषि के साथ वृक्षों के रोपण से है। इसके अंतर्गत कृषि व वनों का पारस्परिक विकास किया जाता है।

भोजन.

- कृषि वानिकी से कृषि के साथ उगाये गये पेड़ों से जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति होती है जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है।
- कृषि वानिकी में उगाये वृक्षों से फलों की प्राप्ति (खाद्य में उपयोग)

पोषण.

- भूमि का उपजाऊ होना कृषि-वानिकी से कृषि फसलों हेतु अपेक्षाकृत कम उर्वरकों व कीटनाशकों की आवश्यकता जिससे मृदा का उपजाऊपन बना रहता है पोषक तत्वों का प्रभावी उपयोग।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ऊर्जा -

- ऊर्जा प्रदान करने में वनों की भूमिका लकड़ी की भूमिका।
- फसलों के साथ कई तरह के पौधों को ऊर्जा मुख्य हेतु बोया जा सकता है जैव ईंधन हेतु कई पौधे उपयुक्त हैं।

रोजगार -

- वनों की लकड़ी से संबंधित
- ग्रामीण स्तर पर रोजगार साधनों का विकास
- लकड़ी के कारोबार से संबंधित उद्योगों के विकसित होने की संभावना।

पर्यावरण सुरक्षा

- वनों को पौधे लगाने के उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
- मृदा प्रबंधन हेतु आवश्यक मृदा में पोषक तत्वों का अनुकूलतम उपयोग इससे सुनिश्चित होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- वन-कृषि फसलों के मिश्रित पारिस्थितिकी से बेहतर फसल उत्पादन।

इस प्रकार कृषि वानिकी खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, रोजगार देने का प्रभावी विकल्प है।

- इसके माध्यम से लघु व सीमांत कृषकों को प्रभावी लाभ होगा।
- कृषि में समावेशी व सतत विकास सुनिश्चित होगा।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार

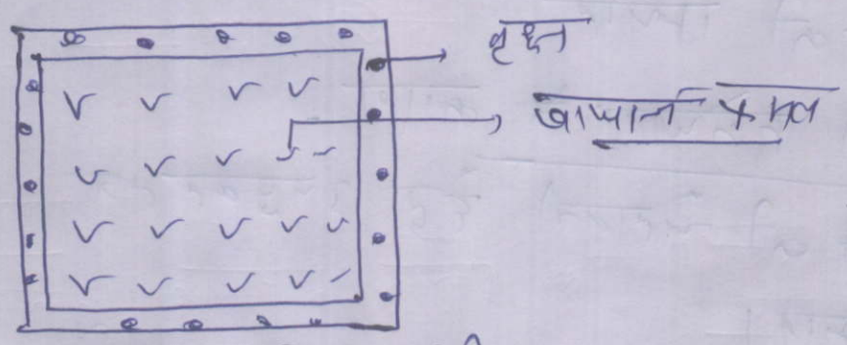

कृषि वानिकी

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Explain the phenomenon of Tsunami formation and highlight reasons for India's vulnerability to Tsunamis. List some measures to mitigate the impact of Tsunamis.

सुनामी उत्पन्न होने की परिघटना की व्याख्या कीजिए और सुनामी के प्रति भारत की सुभेद्यता के कारणों पर प्रकाश डालिए। सुनामियों के प्रभाव का न्यूनीकरण करने हेतु कुछ उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

सुनामी के तात्पर्य जलीय तरंगों के अत्यधिक गतिमान होने तथा तटीय संचरण की गतिविधि से है। इसके अंतर्गत तटों की ओर समुद्रीय तरंगों के बढ़ने से उनका आयाम बढ़ता है किंतु वेग कम होता जाता है।

सुनामी के कारण.

- अन्तः समुद्रीय ज्वालामुखी विस्फोट
- प्लेटों की विवर्तनिक हलचल
- भूकंप की स्थिति

भारत की सुभेद्यता के कारण.

- सुनामी की चेतावनी हेतु उपयुक्त तंत्र का अभाव।
- भारत की आधिकतर जनसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है। जिसके कारण सुनामी की दशा में इनपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सुनामी बचाव हेतु उपयुक्त कार्यविधियों का अभाव।
- सुनामी प्रक्षेप क्षेत्र में भारत की स्थिति। हिंद महासागर में दो सुनामी प्रक्षेप क्षेत्र हैं-
- इण्डोनेशिया सराकान क्षेत्र
- दूरे क्षेत्र

भारत के समीपस्थ स्थिति के कारण भारत पर प्रभाव।

- सुनामी से बचाव हेतु बेहतर तटबंधों का भारत में अभाव। बेहतर आधिसंरचना का अभाव।

न्यूनीकरण करने हेतु उपाय-

- सुनामी-चेतावनी हेतु उपयुक्त तंत्र का विकास करना।
- सुनामी से बचाव हेतु बेहतर डिजाइनों व मानकों का विकास करना।
- तटवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय भागीदारों में जागरूकता का विकास। पारंपरिक तंत्र

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तकनीकों के अलावा सुनामी सफल के बचाव कार्यों हेतु अन्य तंत्रों / रचना तकनीकों का विकास करना।

- सुनामी हेतु बचाव हेतु तटवर्ती क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों का विनियमन करना। वर्तमान में तटवर्ती क्षेत्रों में तीव्र अनियोजनात्मक विकास के कारण उनकी स्थिति, जिसके कारण सुनामी की दशा में ऐसे तटवर्ती क्षेत्रों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- सुनामी बचाव हेतु चेतावनी तंत्रों से सहायता प्राप्त करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Explain the role of Himalayas in influencing the climate of South Asia. Enumerate the changes observed recently in the Himalayan region with respect to climate and geomorphology. What are the possible anthropogenic causes behind them ?
दक्षिण एशिया की जलवायु को प्रभावित करने में हिमालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु और भू-आकृतिविज्ञान के संबंध में हाल ही में चिन्हित किए गए परिवर्तनों की गणना कीजिए। इनके पीछे संभावित मानवजनित कारण क्या हैं?

हिमालय एक प्रमुख जलविभाजक के रूप में कार्य करता है जलवायु प्रभावित करने के संबंध में इसकी एक प्रमुख भूमिका है -

- मानसूनी क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवाएं हिमालय के कारण दक्षिणी एशियातक नहीं पहुंच पाती है
- मानसून की गति दिशा निर्धारित करने में हिमालय की प्रमुख भूमिका बंगाल की खाड़ी की मानसूनी धाराएं शिवालिक के सहारे पंजाब क्षेत्र तक पहुंचती है
- वायुदाब के निर्धारण में हिमालय की प्रमुख भूमिका है

हिमालयी क्षेत्र में परिवर्तन -

जलवायु

भूआकृतिविज्ञान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने के संकेत मिले हैं। हिमाचली क्षेत्रों में गर्मी के बढ़ने के संकेत भी हैं।
- कुल्लू मनाली क्षेत्रों में गर्मी के उपेक्षाकृत बढ़ने के सेबों की फसल प्रभावित हो रही है।
- हिमाचली में माउंट एवरेस्ट की चोटी के संबंध में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं।

मानवीय कारण

- मानव द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से गर्मी बढ़ी है क्योंकि हीरोशिमा गैसों का इन गैसों द्वारा अवशोषण किया जाता है।
- बर्फ के पिघलने से बर्फ की पुरानी चादर सतह पर आती है। इनकी एल्बेडो कम होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है।
- मेथेन उत्सर्जन के तापमान में वृद्धि की संभावना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पर्यटन जैसी गतिविधियों तथा रिसोर्ट, होटलों के बढ़ने के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या।
- हिमालय की भूआकृति विज्ञान में हिमालयी क्षेत्रों में खनन प्रक्रिया, अभियांत्रिकी निर्माण का भी असर पड़ा है।
- भूस्खलन, बाढ़ के बढ़ने के कारण भूमि अपक्षयन की समस्या।

इस प्रकार हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सुकोमल स्थिति में बना हुआ है।

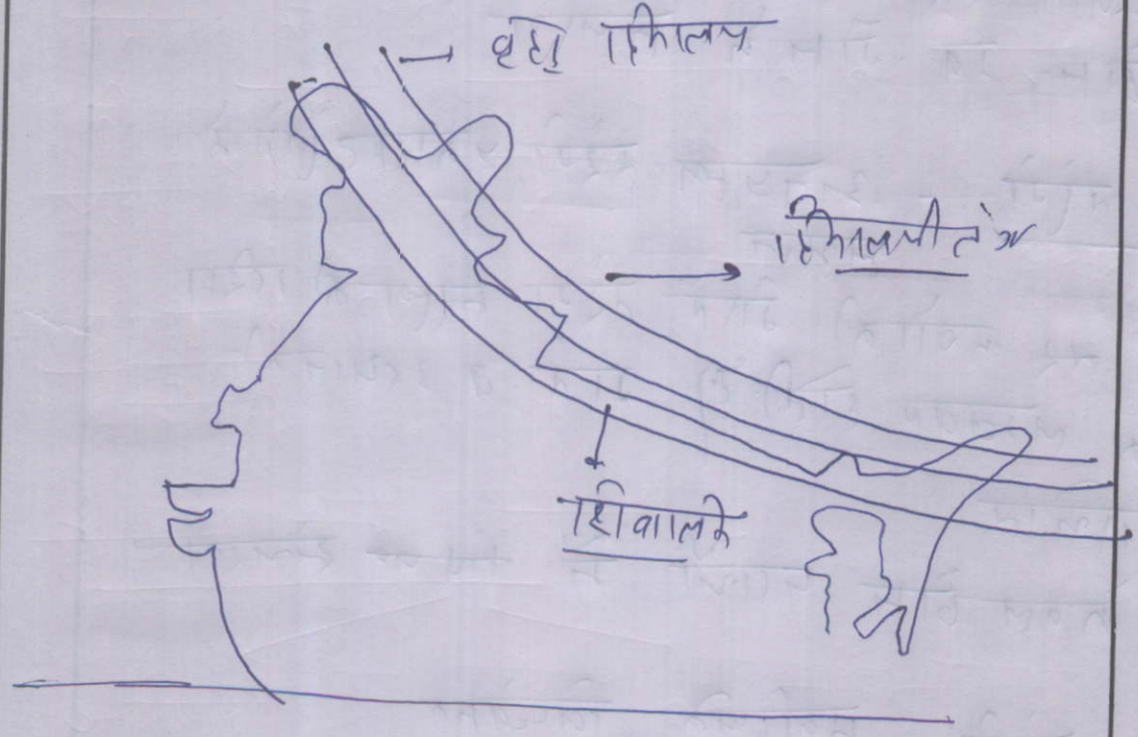

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Explain the different types of earthquake waves and the concept of shadow zone. What inferences can we draw from shadow zones regarding the interior of the Earth?

विभिन्न प्रकार की भूकम्पीय तरंगों और छाया क्षेत्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भांग के संबंध में छाया क्षेत्रों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

भूकंप से तात्पर्य पृथ्वी के आंतरिक भाग में भौगर्भीय स्पंदन से है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की है।

. P तरंगें . S तरंगें - आंतरिक तरंगें

L तरंगें - बाह्य तरंगें

P तरंग - अनुदैर्ध्य तरंग, तरंग गति की दिशा के समान्तर कणों का संचरण, तनाव की स्थिति (Tension) ध्वनि तरंगों के समान।
ठोस - द्रव - गैस में संचरण

S तरंगें - अनुप्रस्थ तरंगें, प्रकाश तरंगों के समान
. इस कणों की गति तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत होती है। गर्त व उत्थान की स्थिति
. केवल ठोस पदार्थों में ~~संचरण~~ संचरण

L तरंगें - सर्वाधिक विध्वंसक
जटिल गति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

छाया क्षेत्र के तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें तरंगों की अनुपस्थिति होती है। P तरंगों के लिए छाया क्षेत्र कम तथा S तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि P तरंगें ठोस S व द्रव तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं।

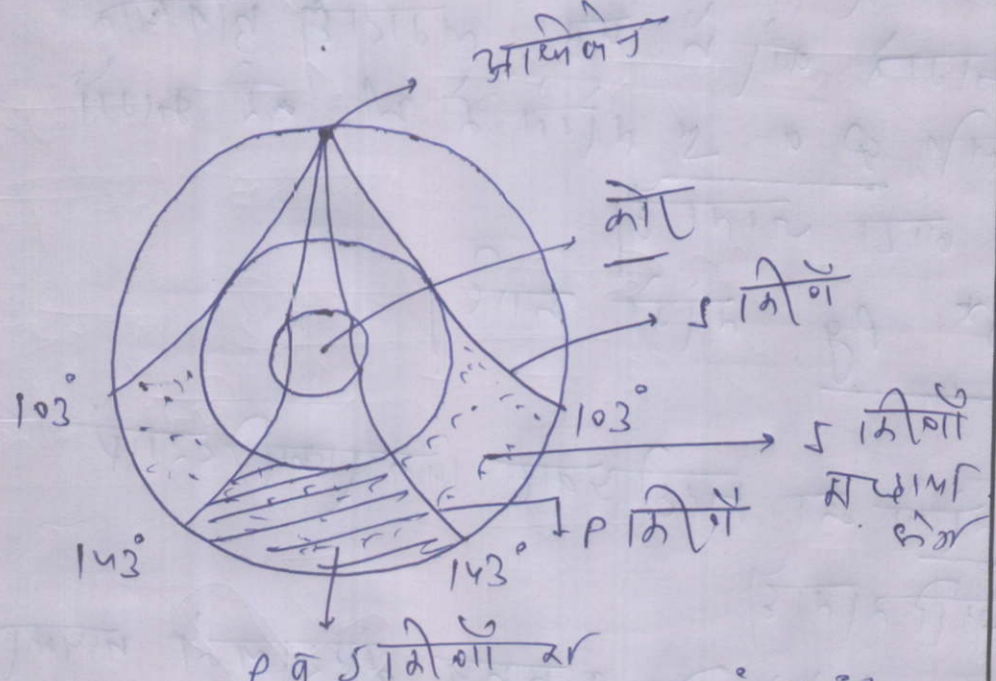

• P व S तरंगों के छायाक्षेत्र से ज्ञात होता है कि ऊपरी कोर क्षेत्र में S तरंगों की गति नहीं होती है। ये तरंगें पूर्णतः अनुपस्थित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रहती है। अतः इनके पृथ्वी के ऊपरी कोर का द्रवित होने का पता लगता है क्योंकि इन माध्यमों से P तरंगें टकराते करती है परंतु S तरंगों का अभाव होता है।

इस प्रकार छाया क्षेत्रों से पृथ्वी की भीतरी भागों के बारे में पता लगता है। सुविधा के लिए P व S तरंगों को भी कई भागों में बांटा जाता है।

P*, Pg, तरंगें आदि।

L तरंगों का सतही प्रवाह विनाशकारी दशाएं उत्पन्न करता है।

P व S तरंगों के वेग व समय अंतराल को मापकर भूकंप के केंद्र में घोषणा की जाती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Explain the difference between chemical weathering and physical weathering. What is the ecological and economic significance of weathering?

रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय के बीच अन्तर की व्याख्या कीजिए। अपक्षय का पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व क्या है?

रासायनिक अपक्षय के तात्पर्य ऐसे अपक्षय की क्रिया से है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जैसे- ऑक्सीकरण, हाइड्रेशन आदि जबकि भौतिक अपक्षय के तात्पर्य भौतिक विघटन की क्रियाओं से है इसमें पांखनीय विघटन प्रमुख है इसके अतिरिक्त डीहाईड्रेशन, ग्लेशियर विघटन प्रमुख है।

अपक्षय का आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व -

- अपक्षय के कारण मृदाओं का विकास अनिश्चित होता है मृदा निर्माण की प्रारंभिक दशा अपक्षय से ही प्रारंभ होती है।
- मृदा में जीवों की उपस्थिति हेतु अपक्षय की क्रियाएं ही प्रभावी है।
- अपक्षय के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता मिलती है अपक्षय किसी स्थान में जीवों की दशाओं की प्रारंभिक स्थिति को प्रेरित करता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• सदा में पर्दानता को समाप्त करने में अपराध की प्रमुख भूमिका है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Tropical regions are not only the most resource rich but also one of the most underdeveloped regions of the world. What are the factors responsible for this? How have some of the tropical countries turned their natural limitations to their advantage? Illustrate.

उष्णकटिबंधीय क्षेत्र न केवल सर्वाधिक संसाधन संपन्न हैं वरन् विश्व के सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रों में से भी एक हैं। इसके लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं? कुछ उष्णकटिबंधीय देशों ने अपनी प्राकृतिक रूकावटों (बाधाओं) को स्वयं हेतु लाभप्रद स्थितियों में किस प्रकार परिवर्तित किया है? व्याख्या कीजिए।

उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र साधन संपन्न होने के बावजूद सर्वाधिक अविकसित देशों में है। यह प्रदेश 'Resource curse' सिद्धांत को इंगित करते हैं। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं

1) प्राकृतिक कारक - उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। तेज गर्मी व साथ में नमी की उपलब्धता शारीरिक कार्यक्षमता को कम कर देती है।

- संसाधनों का प्रतिकूलतम दशा में मिलना जैसे वनों में अलग-अलग प्रजाति के पौधे घोर के रूप में पाये जाते हैं। जिसकारण इनका दोहन कठिन है जबकि टैगा क्षेत्रों में कोनिफेरी वनों का सरल दोहन वहां लकड़ी उद्योग हेतु उपयुक्त दशाएं प्रदान करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- तकनीक का अभाव - इन देशों में उन्नत व आधुनिक तकनीक का अभाव है।
- उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार की में प्रभावी मांग की कमी। क्योंकि अफ्रीकी देशों में गरीबी की स्थिति है।
- लोगों में जागरूकता के कारण, पर्याप्त कौशल अभाव के कारण संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग न हो पाना।
- विकसित देशों की शोषणकारी प्रवृत्तियों का वर्तमान में भी इन विकासशील देशों पर प्रभाव है।
- संसाधनों का दोहन करने हेतु अनुकूलतम साधनों का अभाव।

⇒ तथापि कई देशों जैसे- मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ने प्रकृतिक बाधाओं को लाभप्रद स्थितियों में परिवर्तित किया है।

- इन देशों ने बेहतर तकनीक का विकास किया है। अपने देश की स्थिति के अनुरूप

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

फसलों का विकास।
मलेशिया व इंडोनेशिया में रबर के बागान लगायेगये। वर्तमान में इन बर हेतु वैश्विक मांग उपलब्ध है।

- उपयुक्त सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन
- प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने हेतु लोगों में सामाजिक निवेश- शिक्षा, स्वास्थ्य, मॉरल पर विशेष ध्यान देना।
- प्राकृतिक जलवायु के अनुरूप तकनीकों का अनुकूलतम दोहन
- वैश्विक स्तर पर स्वयं के लिए उपयोगी व प्रभावी व्यापार नीतियों का विकास व क्रियान्वयन
- उपयुक्त बाजार व श्रम शक्ति की उपलब्धता।

इस प्रकार इन देशों का बेहतर विकास हुआ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Coral reefs are the most biologically diverse and economically valuable ecosystems on earth. Elaborate. Discuss the factors responsible for the decline of coral reefs across the world. Also, list some measures that have been taken for their preservation.

प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर जैविक रूप से सर्वाधिक विविधतापूर्ण और आर्थिक रूप से मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र हैं। सविस्तार व्याख्या कीजिए। विश्व में प्रवाल भित्तियों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। साथ ही, उनके संरक्षण हेतु किए गए कुछ उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

प्रवाल भित्तियों के तात्पर्य प्रवाल- पॉलिप के सहजीवी निर्माण प्रक्रम संरचना से है यह भित्तियाँ कैल्शियम कार्बोनेट आदि के निर्मित संरचना है इन्हें समुद्र के वर्षा वन के रूप में जाना जाता है।

- जैव विविधता पूर्ण होना
- प्रवाल भित्ति का प्रयोग ईंटों, सीमेंट आदि निर्माण में होने के कारण आर्थिक रूप से मूल्यवान
- पर्यटन गतिविधियों का प्रवालभित्ति क्षेत्रों में विस्तार होने से आर्थिक लाभ
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख अंग। सौन्दर्यात्मक बोध।

वर्तमान में प्रवालभित्ति का क्षरण (प्रवाल विरंजन) की घटनाएं हो रही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उत्तरदायी कारण -

I) ~~प्रा०~~

- जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के कारण महासागरीय जल की लवणता व तापमान का बढ़ना।
- तटीय क्षेत्रों में अविनियमनात्मक गतिविधियों का विकास होने से प्रवाल नष्ट।
- पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने के कारण प्रवालों पर विपरीत प्रभाव।
- प्रवालों का ईंट, सीमेंट निर्माण जैसी गतिविधियों में अंधाधुंध प्रयोग।
- वर्तमान में समुद्रों में तेल जहाजों के आवागमन के कारण तेल रिसाव की समस्या से प्रवाल विरंजन।
- महासागरीय क्षेत्रों में अतिगहन मत्स्यन का प्रवालों पर विपरीत प्रभाव।
- पोर्वके तिरपर प्रवालों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम न उठाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संरक्षण हेतु उपाय -

- मानवीय गतिविधियों को विनियमित करना।
- तटवर्ती अधिसंरचनात्मक गतिविधियों पर रोक लगाना।
- जलवायु परिवर्तन उपशमन हेतु प्रयास करना।
- समुद्री जल के प्रदूषण को रोकने हेतु कठोर नियम बनाना।
- UNCLOS जैसी वैश्विक संधियों का प्रभावी पालन करना।
- समुद्र में मानवीय संसाधन हेतु प्रयुक्त उपकरणों को प्रभावी बनाना, जिससे उनका प्रवालों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Despite EIA being a useful policy tool for sustainable development, deficiencies in its design and implementation have prevented it from realising its potential. Discuss.

संधारणीय विकास के लिए एक उपयोगी नीतिगत उपकरण होने के बावजूद, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) की अभिकल्पना (डिजाइन) और कार्यान्वयन संबंधी कमियों ने इसकी सम्पूर्ण क्षमता को साकारित होने से बाधित किया है। चर्चा कीजिए।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के तात्पर्य किसी परियोजना की विभिन्न प्रभावों का समग्र पूर्व आकलन करने की प्रक्रिया से है ताकि परियोजना के पर्यावरणीय कुप्रभावों की समय पर जांच की जा सके।

यद्यपि EIA प्रभावी नहीं रहा है

डिजाइन की समस्या -

- EIA को प्रारंभ करने के पहले ही कई परियोजनाओं को अनुमति दे दी जाती है जिसके कारण परियोजनाओं को रोकने में समस्या आती है।
- EIA में स्थानीय समुदायों की प्रभावी भागीदारी का अभाव।
- EIA हेतु उपयुक्त मानकों व दिशानिर्देशों को स्थानीय समुदाय को नहीं बताया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यान्वयन संबंधी कमियां -

- EIA को प्रभावी रूप से कार्यान्वित न करने के कारण इसकी क्षमता प्रभावित।
- EIA के संबंध में उपयुक्त अधिसूचना व सख्त विशेषज्ञों का अभाव।
- EIA की कई परियोजनाओं के लिए छूट दी गई है ऐसी छूट हेतु वास्तविक मानकों का अभाव।
- नौकरशाही तंत्र द्वारा EIA के संबंध में स्थानीय समुदाय को जागरूक न करने के कारण इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं।

पर्यावरणीय विधिक सुधारों से संबंधित समिति (सुब्रह्मण्यम्) ने भी EIA को उदारीकृत करने के संबंध में सुझाव दिए थे।

- EIA के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान

- EIA का पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ सीमित है इस हेतु इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- EIA के संबंध में स्थानीय समुदायों को जागरूक करने की आवश्यकता।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. According to the Indian Fertiliser Scenario 2014, the use of urea in India has increased by more than 50 per cent since 2000. How does human intervention turn nitrogen from a nutrient to a pollutant? Discuss the impacts of nitrogen pollution on environment and human health. Also, explain how nitrogen pollution can be managed.

भारतीय उर्वरक परिदृश्य 2014 के अनुसार, भारत में यूरिया का उपयोग सन् 2000 के बाद 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। मानवीय हस्तक्षेप किस प्रकार नाइट्रोजन को एक पोषक तत्व से प्रदूषक के रूप में परिवर्तित कर देता है? पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। साथ ही, व्याख्या कीजिए कि नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?

उर्वरकों की दृष्टि से यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक है। मानव द्वारा यूरिया के अत्यधिक प्रयोग के चलते उर्वरक एक प्रदूषक बन जाता है-

- नाइट्रोजन : फॉस्फोरस : पोटैशियम का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए किंतु यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से नाइट्रोजन की अधिकता के कारण मृदा का असंतुलन उत्पन्न होता है।
- अतिरिक्त नाइट्रोजन का पौधों द्वारा अवशोषण न होने से यह मृदा के साथ बहकर नदी तंत्र में पहुंचता है जिससे यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है।
- अधिक उर्वरक उपयोग से पोषक तत्वों का अभाव खाद्य फसलों पर विपरीत प्रभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में नाइट्रोजन की मृदा में अधिकता मृदा को अनुर्वर बना रही है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है।

- मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है इसके अतिरिक्त उर्वरक (नाइट्रोजन) का प्रयोग कैंसर के मामलों में भी वृद्धि कर रहा है।

⇒ नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रबंधन.

- सब्सिडी पर नीतियों को युक्तिसंगत बनाना ताकि नाइट्रोजन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो।
- मृदा में उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना तथा दलहन जैसी फसलों को वरीयता देना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- नाइट्रोजन उर्वरक के संबंध में किसानों में जागरूकता पैदा करना ताकि वे इसका अनुकूलतम प्रयोग करें।
- जैविक कृषि का बल देना।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रयोग प्रत्येक किसान तक पहुँचाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Temperate grasslands are called 'Granaries of the world'. Elucidate. How have the farming practices adopted in these regions impacted the environment?

शीतोष्ण घास के मैदानों को 'विश्व के अन्न भंडार' कहा जाता है। स्पष्ट कीजिए। इन क्षेत्रों में अपनायी गई कृषि प्रथाओं ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है?

शीतोष्ण घास के मैदानों को अन्न की अधिक पैदावार के कारण विश्व के अन्न भंडार कहा जाता है। इन मैदानों में प्रमुख है -

- अमेरिका का प्रेरी मैदान
- उत्तरी अमेरिका का प्रेरी मैदान
- यूरोप का स्टेपीज मैदान
- दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश

इन क्षेत्रों में उपयुक्त मृदा के विकास ने अन्न की पैदावार हेतु उपयुक्त दशाएं निर्मित की हैं। इन क्षेत्रों में मृदा निक्षालन की स्थिति पाई जाती है।

- अन्न पैदावार हेतु अधिक मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है।
- आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से अन्न पैदावार को बढ़ावा मिलता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कृषि प्रथाएँ

- इन क्षेत्रों में बड़े फार्मों पर एक साथ कृषि की जाती है। कृषि हेतु बड़े खेतों के उपस्थित होने के कारण तकनीकों का उपयोग आसान रहता है।
- बड़े कृषक फार्मों पर खेती से रोजगार प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है।

- इन क्षेत्रों में अन्न उगाने के साथ पशुपालन गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है।
- किसानों को सरकारी मदद के बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती है।

पर्यावरणीय प्रभाव

- यद्यपि कृषि की उर्वरता हेतु प्रभावी उपाय किये गये हैं तथापि अत्यधिक कृषि के

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कारण तथा सकल फलीन तेज के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Enumerate the global targets and priorities for action of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Discuss the positive features and limitations of the framework.

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेनडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप कार्रवाई के लिए वैश्विक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की गणना कीजिए। इस फ्रेमवर्क की सकारात्मक विशेषताओं और सीमाओं की चर्चा कीजिए।

सेन्डाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एक प्रभावी प्रयास है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्य/लक्ष्य निर्धारित है -

- आपदा जोखिम से प्रभावित नागरिकों संख्या को आधे से कम करना
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रभावी तंत्र का विकास करना
- वैश्विक स्तर पर आपदा से मरने वाले लोगों की संख्या को आधे से कम करने का प्रयास
- स्थानीय समुदाय में क्षमता निर्माण, जागरूकता का विकास करना
- आपदा जोखिम एल्पांकन प्रणाली का विकास करना

सकारात्मक विशेषता -

- यह फ्रेमवर्क आपदा जोखिम के सभी संरचनाओं का प्रभावी उपाय करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- आपदा जोखिम प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में यह फ्रेमवर्क उपयोगी है।
- आपदा के समय मानक दिशानिर्देशों को व मानकों को निर्धारित करता है।
- आपदा जोखिम के निपटने हेतु एक प्रभावी प्रणाली का वे इसके स्तर पर विकास करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में यह फ्रेमवर्क एक उचित कदम है।

सीमाएं

- इस फ्रेमवर्क में उपयुक्त तकनीकी तेजी दिशा में कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर आपदा से लड़ने हेतु प्रभावी उपाय नहीं बताये गये हैं।
- स्थानीय स्तर पर आपदा उपशमन हेतु क्षमता निर्माण व जोखिम गतिविधियों के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निबंध में बात नहीं की गई है।

* आपदा को अलग-अलग भागों में बांटकर प्रभावी दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य स्तर पर अलग-अलग प्रेशर विभिन्न आपदाओं के प्रभावित है। अतः इस निबंध में कोई समाधान नहीं दिया गया है।

तथापि यह केवल एक प्रभावी कार्य है। इसमें तीनों स्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया गया है।

- आपदा पूर्व → उपशमन
- आपदा के दौरान → बचाव राहत कार्यवाही
- आपदा पश्चात → पुनर्वास निर्माण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What is a heat wave? Discuss the health impacts of heat wave in India. Analyse the reasons behind high incidence of mortality rates due to heat wave in India. Suggest measures to tackle the above problem.

हीट वेव (ऊष्ण लहर) क्या है? भारत में ऊष्ण लहर के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की चर्चा कीजिए। भारत में इस घटना के कारण उच्च मृत्यु दरों की घटना के पीछे विद्यमान कारणों का विश्लेषण कीजिए। उपर्युक्त समस्या का समाधान करने के उपाय सुझाइए।

उष्ण लहर से तात्पर्य क्रमागत रूप से औसत तापमान से 3-5°C अधिक तापमान की उपस्थिति के कारण चलने वाली पवनों की उपस्थिति से है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की गतिविधियों के कारण हीट वेव की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रमुख प्रभावित क्षेत्र

- राजस्थान, U.P., M.P. क्षेत्र
- तेलंगाना- आंध्रप्रदेश राज्य

स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव

- उष्ण लहर के कारण शरीर में तुरंत विजलीकरण (डिहाइड्रेशन) के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है।
- तेज बुखार की दशाएं, कमजोरी उत्पन्न होना
- विशेषकर मजदूरों पर गंभीर प्रभाव क्योंकि वे खुले वातावरण में कार्य करते हैं तथा उनके

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पास इलाज करने हेतु धन की भी अनुपलब्धता है।

- शरीर की कार्यक्षमता में कमी।

उच्च मृत्युदर के कारण -

- भारत में स्वास्थ्य देखभाल कारकों का अभाव। प्रभावित व्यक्तियों को उचित समय पर इलाज न मिलना।
- खुले वातावरण में मजदूरों के कार्य करना तथा स्वास्थ्य देखभाल हेतु कम व्यवस्थाएँ।
- पानी पीने की उपयुक्त व्यवस्था का अभाव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की भौगोलिक दूरी का अधिक होना।
- उच्च लहू के बचाव हेतु उपयुक्त दिशानिर्देशों मानकों के संबंध में जनता में जागरूकता का अभाव।
- कार्यस्थलों पर उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निवारण

- नरेगा मजदूरों ने कार्य के दौरान shelter, छाँव की उपयुक्त व्यवस्था करना।
- आपदा के उष्ण लहरों के दिनों में कार्यों को स्थगित करने का प्रावधान होना।
- कार्यस्थलों पर जल की उपयुक्त व्यवस्था होना।
- इलाज की उपयुक्त व्यवस्था होना।
- हीट वेव की चेतावनी की जानकारी हेतु उपयुक्त तंत्र का विकास करना।
- लोगों को जानकारी देने हेतु रोचक तकनीकों का विकास

उष्ण लहरों प्रभावित क्षेत्र

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. "Rising accidents involving merchant ships leading to oil spills in Indian waters is a growing concern that needs to be addressed." Discuss the impact of oil spills on marine environment. Also, suggest measures to prevent such disasters.

"व्यावसायिक जहाज संबंधी दुर्घटनाएँ निरंतर बढ़ने के कारण भारतीय जलीय क्षेत्र में तेल रिसाव की चिंता उत्पन्न हो रही है, जिसका समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है।" समुद्री पर्यावरण पर तेल रिसाव के प्रभावों की चर्चा कीजिए। साथ ही इस प्रकार की आपदाओं का निवारण करने हेतु उपायों का सुझाव दीजिए।

वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों के कारण समुद्री क्षेत्र में ट्रैफिक (यातायात) संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है। भारतीय जलीय क्षेत्र में इस कारण तेल रिसाव की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसके समाधान हेतु प्रयास आवश्यक है।

तेल रिसाव से पर्यावरण पर प्रभाव :

- इसके कारण मत्स्य व समुद्री जीवों की श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है क्योंकि तेलीय परत में उष्मा अवशोषण की अधिकता होने से तापमान प्रभावित होता है तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने में जीवों को परेशानी होती है।
- प्रवालों पर प्रभाव
- तटीय क्षेत्रों के पक्षियों के पंखों में तेल लगने से वे उड़ नहीं पाते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- मानव क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव क्योंकि न्यायोचित समुदाय मछलियों पर निर्भर होते हैं जबकि तेल रिसाव से समुद्री जीवों की मृत्यु तक हो जाती है।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव।
- खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

आपदाओं का निवारण हेतु उपाय:

- तेल रिसाव का पता लगाने हेतु उपयुक्त तकनीकों का विकास करना ताकि तुरंत तेल रिसाव का पता लगाने पर प्रभावी कदम उठाये जा सकें।
- तेल रिसाव से संबंधित कानूनों को प्रभावी बनाना। तेल रिसाव से संबंधित व्यापारिक जहाजों की प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा उनपर प्रभावी कार्यवाही करना।
- उक्त तेल रिसाव क्षेत्र में ह्रास होने वाली जैव विविधता को पुनर्निर्माण करने हेतु प्रभावी कदम उठाना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- वैश्विक स्तर पर तेल रिसाव गतिविधियों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र विकसित करना
- तेल रिसाव से ड्रोन निपटने हेतु एक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Forest fire pose a threat not only to the forest wealth but also to the entire regime of flora and fauna. What are the causes of forest fire? Discuss the ecological, economic and social impacts of forest fires.

दावानल *(जंगल में लगने वाली आग)* न केवल वन सम्पत्ति बल्कि क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पतियों और जीवों के लिए भी खतरा प्रस्तुत करती है। वनों में आग लगने के कारण क्या हैं? दावानलों के पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

दावानल का पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका वन्य-जीवों व मानव पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव है

वनों में आग लगने के कारण :

I) • अधिक तापमान तथा नमी की कमी के कारण आग हेतु उपयुक्त दशाएं निर्मित होना।

• कई स्थानों पर तस्करों द्वारा वन चोरी अपराधों से बचने हेतु आग लगाना।

• उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में चीड़ के पेड़ों की प्रचुरता जिसके पत्ते में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है।

II) पारिस्थितिक कारक -

• वन कारणों के कारण वनों की रचना में स्थानीय समुदायों की भागीदारी न होने से वनों पर कम निगरानी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राज्यों में वन अधिकारियों द्वारा प्रभावी निवारक कार्यवाही न करना।
- वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 67% हिस्से में वन होने चाहिए। इसका पालन न करना।

iii) दावानल रोकने हेतु / चेतावनी हेतु उपयुक्त तंत्र का अभाव। अमेरिका में दावानलों के संबंध में चेतावनी हेतु उपयुक्त तंत्रों का विकास किया गया है। तापमान व आर्द्रता की जानकारी हेतु Radar weather centre स्थापित किये गये हैं।

दावानल के प्रभाव :

1) पारिस्थितिक - वनीय तंत्र का नाश होने से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र - वन्य जीव, पौधों, स्थानीय समुदाय पर प्रभाव।

2) आर्थिक - वनीय संसाधनों पर टिकी स्थानीय समुदाय की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उनके लिए फल, ईंधन, इमारती लकड़ी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की उपलब्धता नहीं रहती।

- वनों के ऊपर राजस्व में गिरावट आती क्योंकि कई पेड़ों को आर्थिक दृष्टि से उगाया जाता है।

=) सामाजिक प्रभाव

- विशाल क्षेत्र में आग लगने के कारण क्षेत्र के निवासियों पर विपरीत प्रभाव। उन लोगों के पुनर्स्थापन व पुनर्वास की समस्या।
- लोगों के रोजगार साधनों का अभाव की समस्या।
- सामाजिक तंत्र में विघटन की समस्या।

समाधान

- पर्वतीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना।
- दावानल की चेतावनी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का विकास करना।
- दावानल के संबंध राज्य वन आयोगों के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण व उपयुक्त प्रशिक्षण, कौशल विकास करना।